चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित | 23 नवंबर–29 नवंबर, 2015 | हर शुक्रवार को प्रकाशित | Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

हार्दिक पटेल

पटेलों का नया सरदार

गुजरात को भारत के सबसे विकसित एवं समृद्ध राज्यों में से एक माना जाता है. अब तक पूरे विश्व में उसकी ऐसी छवि पेश की गई, जैसे वहां किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, हर व्यक्ति खुशहाल है. वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात के विकास की कहानी कुछ यूं बयां की गई कि देश के लोगों की हर समस्या का समाधान गुजरात मॉडल में छिपा है, उसे पूरे देश में लागू करके देश का कायाकल्प किया जा सकता है. लेकिन, उसके एक साल बाद गुजराती संस्कृति की पहचान के रूप में दुनिया भर में विख्यात पटेल (पाटीदार) समुदाय अचानक आरक्षण की मांग लेकर उठ खड़ा हुआ. इस आंदोलन ने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आख़िरकार पटेलों या पाटीदारों को आरक्षण मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? इस आंदोलन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका नेतृत्व एक 22 वर्षीय युवा कर रहा है. ग़ौरतलब है कि वर्ष 2006 में देश में आरक्षण के ख़िलाफ़ यूथ फॉर इक्वलिटी नामक आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन उसके नौ वर्षों बाद एक युवा आरक्षण दिए जाने की लड़ाई लड़ रहा है.

शफीक आलम

पिछले 13 वर्षों से गुजरात में शांति थी, देश–दुनिया में गुजरात के विकास का डंका बज रहा था, लेकिन अचनाक उठ खड़े हुए पाटीदार आंदोलन ने पूरे गुजरात के विकास मॉडल पर हज़ारों सवाल खड़े कर दिए. आख़िर हार्दिक पटेल नामक युवा कौन है, जिसने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया? ऐसा क्या है, जो उसकी एक आवाज़ पर गुजरात के लाखों लोग सड़क पर उतर आए और पाटीदार समाज को आरक्षण दिए जाने की मांग करने लगे? गुजरात में पाटीदारों की संख्या कुल जनसंख्या का तकरीबन 24 प्रतिशत यानी डेढ़ करोड़ के आसपास है. राजनीतिक एवं सामाजिक तौर पर पटेलों को गुजरात में एक मज़बूत समूह के रूप में देखा जाता रहा है. विदेशों, खास तौर पर अमेरिका एवं ब्रिटेन में पटेल समाज के लोगों ने खासी समृद्धि हासिल की है. हर किसी के ज़ेहन में सबसे पहला सवाल उठता है कि आख़िरकार यह आंदोलन किसलिए? एक समृद्ध समाज आरक्षण की मांग क्यों कर रहा है? इन सवालों के जवाब तलाशे बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता. इस संबंध में पाटीदारों का तर्क है कि पांच हज़ार वर्षों से एक समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं मिला है, जिसकी वजह से वह शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से आज भी पिछड़ा है. इसी शैक्षणिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर उसे संवैधानिक तौर पर आरक्षण मिलना चाहिए. पाटीदार समाज को देश के विभिन्न राज्यों में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन गुजरात में ऐसा नहीं है. पाटीदार छात्र–छात्राओं को 90 प्रतिशत अंक प्राप्त करने के बाद भी एमबीबीएस में दाखिला नहीं मिल पाता है, जबकि अनुसूचित जाति/जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र–छात्राओं को इससे बहुत कम अंक प्राप्त करने के बावजूद ऐसे पाठ्यक्रमों में दाखिला

(शेष पृष्ठ 2 पर)

समूचा पाटीदार समाज हमारे साथ है

पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल फिलहाल देशद्रोह के आरोप में जेल में हैं. इस बीच संगठन में फूट पड़ने और इसके कांग्रेस के क़रीब आने की ख़बरें आ रही हैं. आंदोलन को देशव्यापी स्वरूप देने के प्रयास भी हो रहे हैं. ऐसे ही कुछ मसलों पर पटेल नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश कटियार से चौथी दुनिया संवाददाता शफीक आलम ने विस्तार से बातचीत की. पेश हैं, उस बातचीत के मुख्य अंश...

कहा जा रहा है कि आपके आंदोलन में फूट पड़ गई है. इस बात में कितनी सच्चाई है?

हमारे आंदोलन में बिल्कुल फूट नहीं है. गुजरात में पाटीदार समाज की आबादी पौने दो करोड़ है. पाटीदार समाज एकजुट होकर हमारे साथ खड़ा है. एक भी पाटीदार समाज का भाजपा नेता रैली करके तो दिखाए गुजरात में. नहीं कर सकता, हमारे समाज की महिलाएं थाली और चम्मच लेकर बजाने लगती हैं. हमारे समाज पर गोलियां चलती रहीं और समाज के जो नेता भाजपा में हैं, वे बैठे रहे धृतराष्ट्र की तरह. यह रोल भविष्य में तय करेगा कि समाज उन्हें किस रूप में देखता है.

क्या यह आंदोलन गुजरात के पाटीदार नेताओं का राजनीतिक भविष्य भी तय करेगा?

अगर ऐसी कोई आवश्यकता आई भविष्य में, तो देखेंगे. फिलहाल हम आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं.

हार्दिक के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मुक़दमा दर्ज है, वह अभी जेल में हैं. ऐसे में आपकी आगामी रणनीति क्या है?

हार्दिक पटेल के जेल से बाहर आने के बाद उनके साथ बैठकर उनके मार्गदर्शन में तय करेंगे कि हमें आंदोलन को किस तरह और किस रूप में आगे लेकर जाना है. बनारस (उत्तर प्रदेश) में 15 दिसंबर को हमने एक महापंचायत रखी है, जिसमें लगभग 10 लाख कुर्मी, गुर्जर एवं मराठा पाटीदार हिस्सा लेंगे और उसी महापंचायत में हम अपने आगामी कार्यक्रमों की घोषणा करेंगे.

सवाल उठ रहे हैं कि यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित है और कांग्रेस बैकडोर से आपका समर्थन कर रही है?

हमने गुजरात में कांग्रेस का समर्थन किया है. हमने लोगों से कहा कि भाजपा को हराओ और कांग्रेस को जिताओ. हमारे पास नोटा का भी विकल्प है. यदि सारा पाटीदार समुदाय उसका इस्तेमाल करेगा, तो भी भाजपा जीत सकती है. ऐसे में हम अपने वोटों को बर्बाद नहीं करेंगे. किसानों की आत्महत्या के लिए यदि आज भाजपा दोषी है, तो साठ वर्षों तक देश पर राज करने वाली कांग्रेस उससे कम दोषी नहीं है. ■

जिसने दिया था गम खुशी उसी ने दी | P-3

सपा को रफूगर की तलाश | P-5

ख़तरनाक हैं ई–वेस्ट | P-7

हार्दिक पटेल : पटेलों का नया सरदार

पृष्ठ 1 का शेष

मिल जाता है. पाटीदारों का यह भी मानना है कि आम लोगों में यह ग़लतफहमी है कि पाटीदार समृद्ध हैं, लेकिन यह पूर्ण सत्य नहीं है. कई पाटीदार ऐसे हैं, जिनके पास शिक्षा ही तरक्की का एकमात्र साधन है. उनके पास इतनी पूंजी नहीं है कि वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें. ऐसे में पाटीदारों के पास कोई विकल्प शेष नहीं बचता. इसलिए उन्हें पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि कॉलेजों एवं सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिल सके. पटेल नाम रखे जाने से कुछ नहीं बदलता है. गुजरात की कुल आबादी में पाटीदारों की हिस्सेदारी 24 प्रतिशत है, जिसमें से सिर्फ़ पांच प्रतिशत लोग संपन्न हैं. पाटीदार आंदोलन से जुड़े लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में गुजरात में 10 हज़ार कुर्मी किसानों (पाटीदारों) ने आत्महत्या की. यदि वे संपन्न होते, तो उन्हें आत्महत्या न करनी पड़ती. जो चीज़ दिखाई पड़ती है, वह हमेशा हक़ीकत नहीं होती. हक़ीकत दिखाई पड़ने वाले हिस्से से बिल्कुल उलट भी हो सकती है, जैसा कि पाटीदारों के साथ है. समृद्ध दिखने और होने में बहुत फ़र्क़ होता है. यदि ऐसा न होता, तो इस आंदोलन को इतना समर्थन न मिल रहा होता. महज ढाई महीने में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर देना किसी भी तरह से आसान नहीं था. इस आंदोलन को अप्रवासी भारतीयों (एनआरआई पटेलों) का समर्थन मिल रहा है, इसके लिए फंड वहीं से आ रहा है और इसके पीछे वोटों का गणित भी काम कर रहा है.

पाटीदार आंदोलन के नेताओं का मानना है कि देश में अब तक जिस तरीके से आरक्षण लागू किया गया, वह सही नहीं है. इसी वजह से देश 60 वर्ष पीछे चला गया. इसलिए आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, आरक्षण ख़त्म कर देना सही विकल्प नहीं है. वे कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी. यानी जनसंख्या में जिसकी जितनी हिस्सेदारी है, उसे उतने प्रतिशत आरक्षण दिया जाना चाहिए. सरकार के पास जातिगत जनगणना के आंकड़े हैं, वह उन्हें जारी करे और उन्हीं आंकड़ों के आधार पर हर किसी को आरक्षण देने का प्रावधान करे या फिर मंडल आयोग ने आबादी के अनुपात में आरक्षण देने की जो बात कही है, उसे पूरा किया जाए. ऐसा करने से पूरे देश से आरक्षण का मुद्दा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और देश विकास के रास्ते पर आ जाएगा. हालांकि, पाटीदारों द्वारा आरक्षण की मांग चार दशक पुरानी है, जो आज हार्दिक पटेल के नेतृत्व में परवान चढ़ चुकी है. देश में आपातकाल लगाए जाने से पहले भी गुजरात नवनिर्माण समिति के बैनर तले आंदोलन हुआ था. आज पटेल नवनिर्माण सेना इस आंदोलन की झंडाबरदार है. पाटीदार आंदोलन इतिहास से सबक ले रहा है. यह आंदोलन सरदार पटेल के सपनों को साकार करना चाहता है. सरदार पटेल का मानना था कि शारीरिक एवं मानसिक श्रम करने वालों में ज़्यादा भेदभाव न हो. ऐसा अंग्रेजी हुकूमत के दौरान होता था. सरदार पटेल आज़ाद भारत में श्रम की सत्ता स्थापित करना चाहते थे.

इस आंदोलन का विरोध करने वालों का कहना है कि पटेल समुदाय गुजरात में व्यापारी वर्ग का चेहरा है, उद्योग-धंधों में

शामिल है, उसके पास बड़ी मात्रा में खेत-ज़मीनें हैं और हीरा उद्योग (डायमंड इंडस्ट्री) पर उसका कब्जा है. यही नहीं, गुजरात विधानसभा में पाटीदार समाज के 40 विधायक हैं, सात मंत्री हैं और यहां तक कि मुख्यमंत्री आनंदी बेन भी इसी समुदाय की हैं. देश में 60 के दशक में जो भू-सुधार आंदोलन हुआ, उसमें इस समाज के लोग सबसे अधिक लाभांवित हुए थे. पूरे गुजरात में जो भी नकदी फसलें होती हैं, वे भी इसी समाज के पास हैं और उनसे हर साल यह समाज लाखों रुपये कमाता है. इसलिए विरोधी पटेलों द्वारा आरक्षण की मांग के आर्थिक आधार को बुनियादी रूप से ग़लत मानते हैं. कुछ समीक्षक पटेलों की मांग को संकुचित मानसिकता की प्रतीक ठहरा रहे हैं. इससे पूरा गुजरात जातिगत लड़ाई की ओर चला जाएगा.

आख़िरकार आंदोलन करने वाले लोग कौन हैं? दरअसल, ये वे लोग हैं, जिन्होंने नकदी फसलों से पैसा कमाया और उसे लघु-मझोले उद्योगों में डाला, लेकिन नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्रित्व काल में केवल बड़े उद्योगों की ओर ध्यान दिया गया. इस वजह से लघु-मझोले उद्योग धीरे-धीरे बंद होते चले गए. तक़रीबन ऐसे 60 हज़ार उद्योग बंद हो गए और उसका सबसे ज़्यादा असर पटेल समुदाय पर पड़ा. इसी तरह दक्षिण गुजरात में हीरा उद्योग में भी गिरावट आई, उसका भी प्रभाव पटेलों पर हुआ. ऐसे में इस आंदोलन के पीछे आर्थिक कारण होने से इंकार नहीं किया जा सकता. इसमें कोई शक नहीं कि खुशहाल समझा जाने वाला पटेल समुदाय इन दिनों कई तरह की आर्थिक कठिनाइयों का शिकार है. राज्य सरकार पर आरोप है कि वह सिर्फ़ बड़े उद्योगपतियों की मदद करती है. इसके अलावा पटेल समुदाय की युवा पीढ़ी में बेरोज़गारी बढ़ी है. लिहाजा वही लोग अब आरक्षण की मांग कर रहे हैं. पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के नेताओं का कहना है कि आरक्षण की मांग उन लोगों के लिए है, जो समाज में पिछड़े हैं और जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं.

यह आंदोलन अचानक शुरू नहीं हुआ, बल्कि यह गुजरात के कई शहरों में लंबे समय से चल रहा था और इसे सरकार ने दबा रखा था. इस आंदोलन को लेकर जहां तक सरकारी रवैये का सवाल है, तो वह टकराव का रवैया था. हार्दिक पटेल की 25 अगस्त की अहमदाबाद रैली में लाठीचार्ज और उसके बाद भड़की हिंसा पर पुलिस कार्रवाई में नौ लोगों की मौत सवालों के घेरे में है, जिससे पटेल समाज का बड़ा तबका आहत है. उसके बाद भी सरकार द्वारा इस आंदोलन के नेताओं से किसी तरह की बातचीत के बजाय पटेल नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हार्दिक पटेल के ख़िलाफ़ देशद्रोह का मुक़दमा दर्ज कर दिया गया. ऐसा लगता है कि राज्य की भाजपा सरकार के लिए यह आंदोलन सांप-छछूंदर का खेल बन गया है, क्योंकि अगर पटेलों को आरक्षण दिया जाता है, तो दूसरे पिछड़े वर्ग सरकार से नाराज़ हो जाएंगे और यदि नहीं दिया जाता है, तो सरकार को पटेलों की नाराज़गी का सामना करना पड़ेगा. दरअसल, पटेल पिछले कई चुनावों से भाजपा का समर्थन करते रहे हैं. उनकी मांगों के प्रति सरकार का रवैया देखकर ऐसा लगता है कि फिलहाल इस आंदोलन ने भी भाजपा से दो-दो हाथ करने का मन बना लिया है और राज्य में पटेलों का झुकाव कांग्रेस की तरफ़ बढ़ने लगा है. इसका असर आने वाले चुनावों पर निश्चित तौर पर दिखाई देगा. वह भी तब, जबकि बिहार में करारी हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा की लोकप्रियता में गिरावट दर्ज की गई है. ऐसे में 24 प्रतिशत आबादी वाले पटेल समाज को नाराज़ करना भाजपा के लिए महंगा साबित हो सकता है. देश की राजनीति में तेजी से हाशिये पर जाती कांग्रेस किसी भी सूरत में ऐसा मौक़ा हाथ से जाने नहीं देगी.

कौन हैं हार्दिक पटेल

वाणिज्य (कॉमर्स) में स्नातक 22 वर्षीय हार्दिक पटेल ग़ज़ब के वक्ता हैं. अपने जोशीले भाषणों के दम पर उन्होंने अब तक लाखों समर्थक जुटा लिए हैं. उनका जन्म अहमदाबाद के क़रीब विरमगम में हुआ. उनके पिता पानी के पंपों का छोटा व्यवसाय चलाते हैं और वह स्वयं घर पर हैं. हार्दिक पटेल वर्ष 2011 में महिलाओं एवं ग़रीब किसानों के शोषण के ख़िलाफ़ एक सामाजिक संगठन बनाकर सार्वजनिक जीवन में आए. पटेलों के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण मांगने का विचार उन्हें कुछ महीने पहले ही आया. अब वह इस पर काम कर रहे हैं. हार्दिक पटेल ने पाटीदारों के आरक्षण के लिए पहली रैली छह जुलाई को आयोजित की. उनकी इस रैली में क़रीब 12 हज़ार लोग जुटे. उनकी दूसरी रैली में क़रीब पचास हज़ार लोग जुटे, लेकिन 25 अगस्त को अहमदाबाद में हुई रैली में तक़रीबन पांच लाख लोग जुटे. हार्दिक ने दावा किया कि उनकी 25 अगस्त की रैली में दस लाख से ज़्यादा लोग आए. 25 अगस्त की महारैली से पहले उन्होंने छोटी-छोटी एक सौ रैलियां की थीं, जिनमें पटेल समाज ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था.

आंदोलन की मुख्य मांग

पटेल समाज को पिछड़ा वर्ग में शामिल करके शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जाए या कम से कम राजस्थान में जिस तरह गुर्जरों को अलग से आरक्षण का प्रावधान किया गया है, वैसा ही प्रावधान गुजरात में पटेलों के लिए भी कर दिया जाए.

क्या है पाटीदार समुदाय

पाटीदार समुदाय के लोग स्वयं को भगवान श्रीराम का वंशज कहते हैं. उनके मुताबिक वे श्रीराम के बेटे लव एवं कुश की संतान हैं. लव के वंश से नाता जोड़ने वाले पाटीदार स्वयं को लेउवा पाटीदार कहते हैं. कुश के वंश से नाता जोड़ने वाले पाटीदार स्वयं को कडवा पाटीदार कहते हैं. पाटीदारों की चार मुख्य जातियों में से लेउवा और कडवा पाटीदार को आरक्षण नहीं मिला है. हार्दिक पटेल भी कडवा पाटीदार समुदाय से आते हैं.

विरासत की दावेदारी

नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की विरासत का दावा करने में सफल रहे, लेकिन वह जाति से पटेल नहीं हैं. आनंदी बेन मोदी की शिष्या हैं और मौजूदा दौर की सबसे बड़ी पटेल नेता. केशुभाई पटेल को हटाकर नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था और उसके बाद उन पर राजनीतिक संन्यास के लिए दबाव डाला गया. इस तरह पटेलों को एक ग़ैर पटेल नेता ने बेदखल कर दिया और उन्हें हाशिये पर लाकर खड़ा कर दिया. हार्दिक पटेल आधिकारिक तौर पर पटेलों के नए सरदार बनना चाहते हैं. इसलिए भी पटेल समाज उनका समर्थन कर रहा है. ■

shafique.aalam@gmail.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 38
दिल्ली, 23 नवंबर–29 नवंबर, 2015

RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)

सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.
संपादकीय 0120-6451999, 6450888
विज्ञापन व प्रसार 022-42296060, +91-8451050786, +91-9266627379
फैक्स न. 0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

विशेषाधिकार ख़त्म

दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित जाना-माना संस्कृति विद्यालय, जो मुख्य रूप से ग्रुप-ए के अधिकारियों के बच्चों के लिए है, को भारतीय प्रशासनिक सेवा संगठन चलाता है. वर्षों से अन्य पृष्ठभूमि के बच्चों को भी इसमें दाखिला दिलाने की कई कोशिशों के बावजूद यह विद्यालय अपने सिद्धांतों से चिपका रहा, लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट ने संस्कृति विद्यालय में नौकरशाहों का कोटा ख़त्म करने का आदेश दिया है. अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि चूंकि विद्यालय राज्य सरकार की ज़मीन पर बना है, इसलिए इसे भी अन्य विद्यालयों की तरह सामाजिक न्याय और बराबरी के सिद्धांतों का पालन करना होगा. राजधानी के नौकरशाह अदालत के इस निर्णय से खुश नहीं हैं. अब इस विद्यालय में सामान्य और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बच्चों को भी दाखिला मिल सकेगा. वर्तमान में यहां की 60 प्रतिशत सीटें ग्रुप-ए के अधिकारियों के बच्चों के लिए आरक्षित हैं. इसके पीछे नौकरशाह तर्क देते हैं कि विद्यालय की नीतियां स्थानांतरित होने वाले अधिकारियों की मदद के लिए हैं. लेकिन, उनका यह तर्क अदालत ने नकार दिया. ■

फड़नवीस की समस्या

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस राज्य की नौकरशाही द्वारा आदेशों के पालन और क्रियान्वयन में की जा रही देरी के कारण कठिन दौर से गुज़र रहे हैं. हाल में उन्होंने सार्वजनिक रूप से नौकरशाहों की आलोचना की थी और अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बाबुओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी. एक आंतरिक सर्वेक्षण के अनुसार, राज्य के तक़रीबन 30 प्रतिशत वरिष्ठ नौकरशाह सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पिछड़े हुए हैं. राज्य के मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय ने भी वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ बैठक करके उनके साथ प्रदर्शन में सुधार के संबंध में विचार-विमर्श किया. फड़नवीस नौकरशाहों द्वारा उत्पन्न एक अन्य चुनौती का भी सामना कर रहे हैं. कई नौकरशाह केंद्र के साथ अपने संबंधों का लाभ उठाते हुए स्थापित मानकों की अवहेलना करके मलाईदार पदों पर काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि वरिष्ठ नौकरशाहों एवं विभागीय सचिवों को सप्ताह में दो दिन सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और मूल्यांकन का आदेश दिया गया है. संदेश सीधा है कि काम करिए, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहिए. ■

कार्रवाई जारी

सरकार विदेशी पदस्थापना पर स्वीकृत अवधि से ज़्यादा समय तक रहने वाले या अनाधिकृत रूप से लंबी अवधि तक अवकाश पर रहने वाले आईएएस अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई में नरमी बरतने के लिए तैयार नहीं है. सरकार ने ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी है. पहली गाज आईएएस अधिकारी संजीव अहलूवालिया पर गिरी है. उनके आधिकारिक मंजूरी से ज़्यादा समय तक विदेश में सेवा जारी रखने को उनका इस्तीफ़ा मान लिया गया है. एक अन्य आईएएस अधिकारी शिशिर प्रियदर्शी के भी अनाधिकृत रूप से नौ वर्षों तक छुट्टी पर रहने को उनका इस्तीफ़ा मान लिया गया था. इस तरह की कार्रवाई का शिकार होने वालों की सूची में एक नया नाम 1997 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी रीता सिंह के रूप में जुड़ गया है. सुश्री सिंह 2003 में आधिकारिक तौर पर अवकाश पर गई थीं, लेकिन मंजूर अवधि के बाद भी लगातार अनुपस्थित रहने को मई, 2007 में उनका स्वत: इस्तीफ़ा मान लिया गया. सूत्रों के मुताबिक, कई और लोगों पर भी गाज गिरने वाली है. सरकार ने ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है. इससे कुछ अधिकारी खुश हैं और कुछ परेशान. ■

dilipcherian@gmail.com

मुस्लिमों का मानना है कि ओवैसी सिर्फ़ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बिहार आए थे और यही बात बिहार के मुस्लिम वोटरों को पच नहीं पाई. ये कारण ऐसे थे, जो बिहार चुनाव में मुसलमानों का रुझान महागठबंधन की ओर करते चले गए. 2010 के चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे. 35 ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार थे, जिनकी हार मात्र 29 से लेकर 1000 वोटों के बीच हुई थी. अगर क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों पर नजर डालें तो पाएंगे कि भाजपा मुस्लिमों के विरोध में बयानबाजी कर इन क्षेत्रों में अपनी हार को निमंत्रण देने का ही काम कर रही थी.

जिसने दिया था ग़म खुशी उसी ने दी

बिहार

दिव्या त्रिपाठी

बिहार की राजनीति में कांग्रेस पुरानी खिलाड़ी रही है. कभी इस पार्टी का बिहार की राजनीति में जबरदस्त दबदबा था. 1947 से लेकर 1990 के बीच अगर कुछ वर्षों को छोड़कर बात करें तो सूबे की सत्ता कांग्रेस के पास ही रही. बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह भी कांग्रेस के ही थे, लेकिन प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का पतन 1990 के दशक में ही शुरू हो चुका था. एक बार सत्ता से बेदखल होने के बाद कांग्रेस कभी भी मजबूती से अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी. बिहार में कांग्रेस ने अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाने की दिशा में कदम बढ़ाया है. 1990 के बाद 2015 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस ने लम्बी छलांग लगाई. 1990 के विधान सभा चुनाव में 71 सीटें जीतने वाली कांग्रेस पार्टी 1995 में केवल 29 सीटें ही जीत सकी. 2015 विधान सभा चुनाव कांग्रेस के लिए एक वरदान साबित हुआ. इस चुनाव में 41 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस को जनता ने 27 पर जीत दिलाकर खोए हुए सम्मान को फिर से वापस पाया है. जिन लालू प्रसाद और नीतीश के सामंतवादी विरोध के कारण कांग्रेस ने अपनी साख खोई थी आज उसी लालू प्रसाद और नीतीश की नाव पर बैठ कर कांग्रेस ने बिहार में अपने आप को मजबूत किया. 2010 में 243 सीटों पर लड़ रही कांग्रेस मात्र चार सीटों पर सिमट कर रह गई वहीं 2015 में 41 सीटों पर चुनाव लड़कर पार्टी 27 सीटें हथिया लीं.

1990 से लेकर 2010 तक कांग्रेस का जनाधार लगातार घटता ही गया है. 1990 में 71, 1995 में 29, 2000 में 23, 2005 में आठ और 2010 में चार सीटें लाकर कांग्रेस ने लगातार जनता के बीच अपनी लोकप्रियता को कम पाया. राहुल गांधी ने युवाओं और महिलाओं को अपने पार्टी में विशेष जगह देते हुए पार्टी की राजनीति में थोड़ा बदलाव किया, जिससे उनकी पार्टी का जनाधार फिर से मजबूत हो सके और उनके इस फार्मूले ने बिहार में उनकी पार्टी को एक बेहतर जगह पर लाकर खड़ा कर दिया है. गरीबी, बेरोजगारी , और महिला सशक्तिकरण का मुद्दा और महागठबंधन का साथ उनके लिए सोने पर सुहागा का काम किया. 2015 के विधान सभा चुनाव में कांग्रेस के कई नए चहरे भी कामयाब हुए. इतना ही नहीं पार्टी ने अपने पिछली सीटों पर भी अपना कब्ज़ा बरकरार रखा. कहलगांव से कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता सदानंद सिंह एक बार फिर से चुनाव जीत गए. पांच में से चार महिला उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की जिनमे बेगूसराय से अमिता भूषण, गोविंदपुर से पूर्णिमा यादव, बेनीपट्टी से भावना झा और कोढ़ा से पूनम पासवान शामिल हैं.

दशकों बाद कांग्रेस के बिहार प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में कार्यकर्ताओं की ख़ुशी देखने लायक थी. पटाखों की धमक ढोल नगाड़े और मिठाइयों की बौछार सदाकत आश्रम की ख़ुशी को जाहिर कर रही थी. पार्टी के फिर से जिंदा होने की इतनी बड़ी खुशी को देख पार्टी के कई पुराने नेताओ की आंखें छलक गईं और कहने लगे पार्टी को इसी दिन का इंतज़ार था. प्रदेश कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने अपनी जीत पर एक–दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए गर्म जोशी से गले लगाया फिर ढोल की धुन पे खूब नाच कर अपनी खुशी जाहिर की. इस खुशी के माहौल में कार्यकर्ता ने वो दिन भी पुरानी यादों को कहकर भूल गए जब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के कारण कांग्रेस बिहार में हाशिये पर आ गई थी और अपने जनाधार मजबूत करने के लिए लगातार प्रयासरत रही. आखिरकार कांग्रेस को उन्हीं पर दांव खेलना पड़ा और बिहार में अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाने में थोड़ी मजबूती बनाई.

कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने 25 साल के बाद कांग्रेस की जीत की खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस बार पार्टी ने अच्छी सूझ–बूझ का इस्तेमाल करते हुए जीत हासिल की है. कांग्रेस फिर से बेहतर होने की ओर है. यह जीत अभी बहुत बड़ी नहीं है. निम्न स्तर से बिहार कांग्रेस की स्थिति अच्छी हुई है. आने वाले दिनों में और भी बेहतर होगी. 1990 के बाद हमलोग काफी पीछे जा रहे थे. लेकिन इस चुनाव में हमने अपनी स्थिति काफी मजबूत की है. लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के कारण कांग्रेस की खराब हालत पर और इस बार साथ मिलकर सरकार में आने की बात पर उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने साथ मिलकर एक एजेंडे के तहत काम किया. पुरानी बातों पर हम अब बात नहीं करना चाहते.

देश हित में हम साथ मिलकर काम करेंगे. मंत्री पद के लिए पूछे जाने पर सदानंद सिंह कहते है कि 9वीं बार हमने चुनाव जीता है. पार्टी का जो भी फैसला होगा मंजूर होगा. सारण की मांझी सीट से जीत हासिल करने वाले विजय शंकर दुबे ने कहा कि लोकतंत्र में पार्टियां ऊपर–नीचे होती हैं लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके पार्टी को एकबार फिर मजबूत स्थिति देने की कामयाब कोशिश की है. सरकार बनाने के साथ ही मंत्री पद के गठन में महागठबधन के सभी पार्टिया मिलकर विचार कर रही है. कांग्रेस से सदानंद सिंह, विजय शंकर दुबे, शकील अहमद, प्रेमचन्द्र मिश्र, दिलीप चौधरी, अवधेश कुमार, मो.जावेद और अमिता भूषण का नाम हो सकता है लेकिन राहुल गांधी ने महिलाओं और युवाओं की भागीदारी की बात की है तो कई नए और युवा विधायकों को भी जगह मिल सकती है. प्रदेश प्रवक्ता विनोद यादव ने कहा की राहुल गांधी के नेतृत्व के कारण बिहार में अच्छी बढ़त मिली है. सरकार में शामिल हों या न हों ये अभी तय नहीं हुआ लेकिन महागठबंधन के साथ जिन विचारों पर हमने जीत हासिल की है उसपर साथ खड़े हैं. बहरहाल राजनीति में सब कुछ जायज है. जहां कभी एक दूसरे के विचारधाराओ के खिलाफ मोर्चाबंदी की गई आज उसे महागठबंधन का नाम दिया गया. जिसने कभी कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया उसी के साथ ने मजबूती भी दी. अब देखना यह है पार्टियों के विचारों का बदलाव एक पथ पर साथ कबतक रहेगा और बिहार की जनता को यह गठबंधन कितना फायदा पहुंचाता है? ■

इस बार पार्टी ने अच्छी सूझ–बूझ का इस्तेमाल करते हुए जीत हासिल की है. कांग्रेस फिर से बेहतर होने की ओर है. यह जीत अभी बहुत बड़ी नहीं है. निम्न स्तर से बिहार कांग्रेस की स्थिति अच्छी हुई है. आने वाले दिनों में और भी बेहतर होगी. 1990 के बाद हम लोग काफी पीछे जा रहे थे. लेकिन इस चुनाव में हमने अपनी स्थिति काफी मजबूत की है.

– सदानंद सिंह
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता

feedback@chauthiduniya.com

भाजपा नेताओं की बयानबाजी का असर

महागठबंधन को मिला अल्पसंख्यकों का समर्थन

बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में महागठबंधन को भारी बहुमत से जीत मिली है. इस चुनाव में मुस्लिम वोटरों की क्या भूमिका रही, चुनाव में कितने मुस्लिम विधायक चुनकर आए, क्या मुसलमानों को उनकी आशा के अनुरूप जीत हासिल हुई या जिस तरह से इस चुनाव में विभिन्न पार्टियों ने उन्हें लेकर कम संजीदगी दिखाई, क्या वह उनकी रणनीतिक भूल थी? इन सवालों के जवाब जानना जरूरी है. आइए, इन सवालों की पड़ताल करते हैं...

राजीव रंजन

feedback@chauthiduniya.com

बिहार में मुस्लिम वोटरों की आबादी करीब 17 से 20 फीसदी है. राज्य में लगभग 65 सीटें ऐसी हैं, जहां मुस्लिम वोटरों की संख्या 20 से 75 प्रतिशत है. 50 से अधिक सीटों पर 10 से 20 फीसदी मुस्लिम वोटर हैं. फिर भी इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में मुसलमान वोटों को लेकर दोनों प्रमुख गठबंधनों में शुरू से ही कम चिंता देखने को मिली. भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन ने मुस्लिम वोटों को लेकर ज्यादा आशा नहीं की थी. यह बात इसलिए कही जा रही है, क्योंकि चुनाव प्रचार के क्रम में जिस तरह गोमांस, सांप्रदायिक आधार पर आरक्षण का मुद्दा उठाया गया और पाकिस्तान में पटाख़े फूटने जैसे बयान दिए गए, उससे यही लगता है कि बीजेपी को मुसलमान वोटों की फ़िक्र ही नहीं थी. हाल ही में भाजपा में शामिल हुए साबिर अली का भी कहना था कि बीजेपी को इन बयानबाज़ियों से नुक़सान हुआ है. साबिर अली कहते हैं कि ये सही है कि बयानबाज़ी से एक समाज आहत हुआ है. पर्यवेक्षकों का मानना है कि ऐसे बयानों पर चिढ़ा मुसलमान बीजेपी के विकास के दावों को ख़ारिज कर महागठबंधन की ओर खुलकर खड़ा हो गया. दूसरी तरफ भाजपा ने हिंदू–मुसलमान वोटों के ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश भी की थी. मुसलमानों का मानना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब सत्ता संभाली थी, तो सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था. एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात कही गई थी. फिर एकाएक क्या हो गया कि मुसलमानों का भरोसा उन्होंने गंवा दिया. मुस्लिम मतदाताओं का मानना है कि मोदी सरकार को हमने भी वोट दिया था. कुरान और कंप्यूटर वाला उनका नारा बहुत अच्छा था, लेकिन वे मुसलमानों की आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरेंगे, तो कोई मुसलमान साथ नहीं देगा. दूसरी ओर इस सवाल पर भी लोगों के अलग–अलग दावे थे कि मुसलमान कितना इस्तेमाल होता है. मुसलमान वोट बैंक है या नहीं. लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण पर चल रही बयानबाज़ी के बीच मुसलमानों के मुद्दे पीछे छूट रहे थे. इस बार के चुनाव की ख़ासियत ये भी रही कि मुस्लिम वोटों के लिए कोई अपील नहीं जारी हुई थी. किसी पार्टी ने भी अपील नहीं की. मुस्लिमों के मामले में इस बार की चुनाव की खास बात यह भी रही कि इस बार मुसलमानों ने मुख्यधारा में आकर आम लोगों की तरह वोट किया. मुस्लिम अल्पसंख्यक है और उसे अपनी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता भी होती है. यही कारण है कि उसने विकास के लिए नीतीश को और सुरक्षा के लिए भाजपा से इतर नीतीश–लालू को वोट किया. बिहार की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा था, वो बदलाव था मुसलमानों में नीतीश कुमार की बढ़ती पैठ, लालू यादव में मुसलमानों की पैठ तो पहले से ही थी. एक संभावना यह थी, जिसके कयास लगाए जा रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं, लेकिन ओवैसी को अपनी जीत और हार के समीकरण समय से पता चल गए, इसीलिए उन्होंने पहले 24 सीटों पर लड़ने की बात कही, लेकिन बाद में सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़े. ओवैसी के यू–टर्न ने महागठबंधन की ओर मुस्लिमों को झुकने के लिए बाध्य कर दिया और मुस्लिम मतदाताओं का ओवैसी से विश्वास उठा, सो अलग. यह चुनाव के नतीजों से साफ पता भी चलता है. दूसरी तरफ सीमांचल के कुछ हिस्सों में स्थानीय नेताओं के प्रभाव को छोड़कर ओवैसी कम ही नज़र आए और स्थानीय नेताओं का वो प्रभाव भी पूरी तरह से कयासबाजी ही साबित हुई, जब चुनाव में ओवैसी को करारी शिकस्त मिली. मुस्लिमों का मानना है कि ओवैसी सिर्फ़ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए बिहार आए थे और यही बात बिहार के मुस्लिम वोटरों को पच नहीं पाई. ये कारण ऐसे थे, जो बिहार चुनाव में मुसलमानों का रुझान महागठबंधन की ओर करते चले गए. अब एक नजर पिछले विधानसभा चुनाव पर डालते हैं. 2010 के चुनाव में 19 मुस्लिम विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे. 35 ऐसे मुस्लिम उम्मीदवार थे, जिनकी हार मात्र 29 से लेकर 1000 वोटों के बीच हुई थी. अगर क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों पर नजर डालें तो पाएंगे कि भाजपा मुस्लिमों के विरोध में बयानबाजी कर इन क्षेत्रों में अपनी हार को निमंत्रण देने का ही काम कर रही थी. सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज में 78, अररिया में 45, कटिहार में 44 और पूर्णिया में 37 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं. कुछ जिलों को देखा जाए तो दरभंगा में 23, सीमामढ़ी में 21, पश्चिमी चंपारण में 21 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं. पूर्वी चंपारण में 19, भागलपुर में 19, मधुबनी में 19 और सिवान में लगभग 20 प्रतिशत मुस्लिम मतदाता हैं. इन आंकड़ों को गंभीरता से लेते हुए महागठबंधन ने भाजपा की मुस्लिम विरोधी छवि का महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने जबरदस्त फायदा उठाया और उन्हें अप्रत्याशित सफलता मिली. दरअसल, बिहार में जेडीयू–आरजेडी–कांग्रेस गठबंधन को मुस्लिम वोट मिलने की संभावना सबसे ज्यादा थी. खासकर लालू और नीतीश की उम्मीदें इस चुनाव में मुस्लिम–यादव समीकरण पर ही टिकी थीं, जिसका पूरा–पूरा फायदा उन्हें मिला भी. मतदाताओं का एक तबका ऐसा भी था, जिसने जाति और धर्म से ऊपर उठकर नितीश कुमार द्वारा पिछले 10 साल में किए कार्यों को देखकर विकास के नाम पर उन्हें वोट दिया. लिहाजा, मुस्लिम वोटों के बंटवारे की संभावना न के बराबर थी. ये कुछ ऐसे कारण थे, जिन्होंने मुस्लिमों को महागठबंधन के सिर जीत का सेहरा बांधने के लिए आगे किया. वहीं दूसरी ओर भाजपा को पूरी तरह नकार दिया.■

उम्मीदवार	चुनाव क्षेत्र	पार्टी
शमीम अहमद	नरकटिया	राजद
खुर्शीद उर्फ फिरोज आलम	सिकटा	जदयू
अब्दुल जलील मस्तान	अमौर	कांग्रेस
अब्दुल बारी सिद्दीकी	अलीनगर	राजद
मो. नेमतुल्लाह	बरौली	राजद
फैजल रहमान	ढाका	राजद
सर्फुद्दीन	शिवहर	जदयू
फैयाज अहमद	बिसफी	राजद
सैय्यद अबु दोजाना	सुरसंड	राजद
अखतरुल इस्लाम शाहीन	समस्तीपुर	राजद
मोहम्मद इलियास हुसैन	डेहरी	राजद
अबिद उर रहमान	अररिया	कांग्रेस
मो. नवाज़ आलम	आरा	राजद
सरफराज़ आलम	जोकिहट	जदयू
गंज तौसीफ आलम	बहादुरगंज	कांग्रेस
नौशाद आलम	ठाकुरगंज	जदयू
डॉ. मो. जावेद	किशनगंज	कांग्रेस
मुजाहिद आलम	कोचाधामन	जदयू
अब्दुल सुभान	बसाई	राजद
मो. अफाक़ आलम	कस्बा	कांग्रेस
शकील अहमद ख़ान	कडवा	कांग्रेस
महबूब आलम	बलरामपुर	सीपीआई (एमएल)
फराज फातमी	केवती	राजद
मो. इलियास हुसैन	डेहरी	राजद

यह आग इतनी भयावह थी कि दमकल की 30 गांड़ियां करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पा सकीं. इस आग में लोगों के शरीर के कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं बचा. बच्चों की किताबें, कपड़े, रोजमर्रा की वस्तुएं, टीवी, फ्रिज, चारपाई, रिक्शा, रुपये, जेवर सब कुछ इस आग में जलकर स्वाहा हो गये. इस आग ने लोगों के रहने का घर ही नहीं, बल्कि उनका रोजगार भी छीन लिया है. घर के बर्तन से लेकर रोजमर्रा की कोई भी वस्तु नहीं बची है. बच्चों की किताबें–कॉपी, ड्रेस सब कुछ जल कर खाक हो चुके हैं. बस्ती के ऊपर से 60 हजार वोल्टेज के तार गुजरते हैं, जो आग की तपिश से गलकर टूट गये, इनके लोहे के पोल तक टूट गये.

कब तक जलती रहेंगी झुग्गियां

सुनील कुमार feedback@chauthiduniya.com

गत 19 अक्टूबर को हम सब जब नींद के आगोश में थे, उसी समय तड़के करीब 1.45 बजे मंगोलपुरी के टी ब्लॉक की झुग्गी–बस्ती में रहने वाले करीब 300 परिवार अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे. इस झुग्गी–बस्ती में किसी का घर कच्चा तो किसी का पक्का बना हुआ है, किसी का घर प्लास्टिक शीट का है तो किसी का घर ईंट का है, जिसके ऊपर एस्बेस्टस की छत है. यहां के ज्यादातर लोग फैक्ट्रियों से रबड़ प्लास्टिक, कपड़ों के कबाड़ लाकर छांटने का काम करते हैं, इससे उनकी जीविका चलती है. यहां पर कुछ बाहरी लोगों द्वारा कबाड़ का गोदाम भी बनाया गया है. यह झुग्गी बस्ती भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर स्थित है. इसके एक तरफ मंगोलपुरी और उद्योग विहार औद्योगिक क्षेत्र हैं, तो दूसरी तरफ मजरा गांव और मंगोलपुरी का टी,यू ब्लॉक है. सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी की सभी बसें इस झुग्गी–बस्ती के नजदीक से ही गुजरती हैं. यह झुग्गी बस्ती 1984 से स्थित है, लेकिन कई झुग्गियां उसके बाद भी वहां बनीं. इस बस्ती में ज्यादा लोग यूपी के मथुरा से हैं, तो कुछ बिहार हरियाणा. पश्चिम बंगाल से हैं. इस बस्ती में बिजली है, पानी टैंकर से आता है और शौचालय के लिए खुले मैदान में जाना होता है. इस बस्ती से 20 फीट की दूरी पर गैस की तीन एजेंसियां हैं. इस बस्ती में इससे पहले भी दो बार आग लग चुकी है.

आग की भयावहता

18 तारीख की रात कोई ड्यूटी से लौटकर सोया होगा, कोई बच्चा टीवी देखते हुए तो कोई पढ़ते हुए सो गया होगा. रामचंद्र अपनी ड्यूटी खत्म कर रात के 1.30 बजे झुग्गी में आकर सो गए. थोड़ी देर में शोर से रामचंद्र की आंखें खुलीं और दरवाजा खोलकर जैसे ही वह बाहर आए, वह उस भयावह दृश्य को देख कर कांप उठे. अपनी झुग्गी में वापस आए बगैर जान बचाने के लिए बाहर की तरफ भागे. यह आग इतनी भयावह थी कि दमकल की 30 गांड़ियां करीब 3 घंटे बाद आग पर काबू पा सकीं. इस आग में लोगों के शरीर के कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं बचा. बच्चों की किताबें, कपड़े, रोजमर्रा की वस्तुएं, टीवी, फ्रिज, चारपाई, रिक्शा, रुपये, जेवर सब कुछ इस आग में जलकर स्वाहा हो गये. इस आग ने लोगों के रहने का घर ही नहीं, बल्कि उनका रोजगार भी छीन लिया है. घर के बर्तन से लेकर रोजमर्रा की कोई भी वस्तु नहीं बची है. बच्चों की किताबें–कॉपी, ड्रेस सब कुछ जल कर खाक हो चुके हैं. बस्ती के ऊपर से 60 हजार वोल्टेज के तार गुजरते हैं, जो आग की तपिश से गलकर टूट गये, इनके लोहे के पोल तक टूट गये.

विजयपाल, जो कि बस्ती के बाहर अंडे की दुकान लगाते थे, उनकी टेबल, बर्तन, अंडे जल गए. अब वह मायूस हैं और पूरे दिन घर पर इस आस में रहते हैं कि कोई सहायता उनको मिल जाये, जिससे कि वह घर पर प्लास्टिक डाल कर अपना रोजगार शुरू करने की सोचें. साइना, जो अपने पति और चार बच्चों के साथ इस बस्ती में रहती है, अपने जले हुए घर के पास बैठ कर आंसू बहा रही है. साइना को सांत्वना देने के लिए उनके रिश्तेदार बवाना से आये हैं, साथ उसके लिए एक–दो कपड़े भी लेकर आये हैं. साइना अपनी झुग्गी में ही पकौड़े और चाय बेच कर गुजारा करती थी, लेकिन उसने कुछ दिनों से चाय बेचना बंद कर दिया था, क्योंकि लोग उधार पर लेते थे, पैसे नहीं देते थे. अब सिर्फ पकौड़े ही बेचती है, जो कि बच्चे खरीद कर ले जाते हैं. साइना के पति मन्टू मोमीन के पैरों के तलवे में गांठ है, जिससे उनको चलने में परेशानी होती है. पैसा नहीं होने के कारण वह कभी किसी डॉ. के पास नहीं गये और मेडिकल स्टोर से 30 रुपये की पट्टी खरीद लाते हैं और उसको ही चिपका देते हैं, जिससे उन्हें चार–पांच दिन के लिए आराम मिल जाता है. साइना पकौड़े बेचकर अपना तथा अपने चार बच्चों का खर्च किसी तरह चलाती हैं और उनको स्कूल भी भेजती हैं. डर के मारे साइना अपनी जली हुई जगह से एक घंटे के लिए भी नहीं हटती. उन्हें डर है कि दंबग लोग उसकी जगह पर कब्जा कर लेंगे. इस तरह का डर कई परिवारों को सता रहा है. वो अपने बच्चों को खाना लाने के लिए भेजते हैं, लेकिन अपनी जली हुई जगह से नहीं हटते.

इस आग ने आकाश और दीप कुमार के साथ–साथ करीब 150 परिवारों के घरों को उजाड़ कर रख दिया है. अब सभी को एक ही चिंता सता रही है कि ठंड का मौसम आने वाला है और उनके पास पैसे नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, कैसे जुगाड़ होगा? लोगों के कई सालों की मेहनत की कमाई से जुटाये गए पैसे, सामान जल कर खाक हो चुके हैं. आग लगने वाले दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री आये थे और 5 मिनट की खानापूर्ति के बाद बस्ती से चले गए थे और जले हुए घरों के प्रत्येक परिवारों के लिए 25 हजार देने की घोषणा कर गए. दिल्ली में काफी जगहों की झुग्गियों में आग लगी है, लेकिन किसी भी आग की जांच नहीं कराई गई.

राजवीर कहते हैं कि आग में सब कुछ जल कर स्वाहा हो गया. थोड़ा जो भी सामान बचाने की कोशिश की तो उस सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया. राजवीर और उनकी पत्नी यहीं पर कबाड़ छांटने, लोडिंग का काम दिहाड़ी पर करते हैं. जिसके लिए राजवीर को 200 रुपये तथा उनकी पत्नी को 130 रुपये मजदूरी मिलती है. इसी तरह यहां पर ज्यादातर लोग दिहाड़ी पर, तो कुछ लोग महीने के हिसाब से काम करते हैं. आकाश नवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ कर रोटी जुटाने में जुट गया. आकाश के पिता को टीबी की बीमारी है. वह उद्योग विहार की 20 कंपनियों से वैकूलाईट का कबाड़ उठाने का काम करता है. इस कबाड़ को घर पर तोड़कर मां–पिता पीतल, तांबा लोहा निकालते हैं और उसे बेचकर परिवार की रोटी का जुगाड़ करते हैं. आकाश के परिवारवालों ने दीपावली व अन्य कामों के लिए 22 हजार रुपये जोड़े थे, लेकिन इस आग से सब कुछ खत्म हो गया. आकाश का पड़ोसी दीप कुमार छठवीं में पढ़ता है, वह अपनी जली हुई किताबों के टुकड़े उठाने में लगा हुआ था.

इस आग ने आकाश और दीप कुमार के साथ–साथ करीब 150 परिवारों के घरों को उजाड़ कर रख दिया है. अब सभी को एक ही चिंता सता रही है कि ठंड का मौसम आने वाला है और उनके पास पैसे नहीं हैं, कपड़े नहीं हैं, कैसे जुगाड़ होगा? लोगों के कई सालों की मेहनत की कमाई से जुटाये गए पैसे, सामान जल कर खाक हो चुके हैं. आग लगने वाले दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री आये थे और 5 मिनट की खानापूर्ति के बाद बस्ती से चले गए थे और जले हुए घरों के प्रत्येक परिवारों के लिए 25 हजार देने की घोषणा कर गए. दिल्ली में काफी जगहों की झुग्गियों में आग लगी है, लेकिन किसी भी आग की जांच नहीं कराई गई. नहीं तो आज तक पता चल जाता कि आग कैसी लगी या लगाई जाती है. अधिकांश जगह यह देखा गया है कि आग लगने के कुछ दिनों बाद उन बस्तियों को उजाड़ भी दिया जाता है. चुनाव के समय वोट मांगने वाली और अपने आपको गरीबों की हितैषी कहने वाली पार्टियां अब कहां हैं? हर झुग्गी को मकान देने वाले प्रधानमंत्री की घोषणा कब लागू होगी?■

मुख्यमंत्री की आलोचना करने पर लगा देशद्रोह

कोवन कला और साहित्य संगठन मक्कल कलई आईलाक्कियां कझगम के सदस्य हैं. यह संगठन महिलाओं और दलितों जैसे हाशिये पर पहुंचे लोगों के अधिकार को लेकर लोक गीत और नुक्कड़ नाटकों का मंचन करता है. कई समाजसेवी संगठनों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की. एशियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट ने तमिलनाडु के अधिकारियों से राज्य की जेल में देशद्रोह के आरोप में बंद दलित लोक गायक और सामाजिक कार्यकर्ता एस शिवादास उर्फ कोवम को तत्काल रिहा करने की मांग की.

चौथी दुनिया ब्यूरो

अम्मा के नाम से मशहूर तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को भी देश के अन्य मुख्यमंत्रियों की तरह अपनी आलोचना कतई बर्दाशत नहीं है. चाहे वो मीडिया हो या समीक्षक या अन्य कोई साहित्यकार, जयललिता अपनी आलोचना करने वाले को सबक सिखाने में पीछे नहीं रहती हैं. हालिया मामला एक तमिलनाडु के दलित गायक कोवन का है. धुर वामपंथी और शराब विरोधी प्रचारक कोवन ने अपने दो गीतों में मुख्यमंत्री जयललिता की शराब नीतियों की आलोचना की थी और इन गीतों के वीडियो जारी किए थे. देखते ही देखते ये वीडियो इंटरनेट और व्हाट्सएप पर वायरल हो गए. कोवम ने अपने गीतों में राज्य सरकार से कहा है कि वह गरीबों की कीमत पर सरकारी शराब खानों से फायदा उठाना छोड़ दे. उन्होंने सत्तारूढ़ दल से अपने गीत के माध्यम से शराब की दुकानें बंद करने की अपील की थी. उनके दूसरे गीत में कहा गया है कि जयललिता अपने आलीशान बंगले में रह रही हैं और लोग शराब पीकर मर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने में लगी हैं. 54 वर्षीय इस गायक को मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ व्हाट्स ऐप्प और अन्य वेबसाइट्स पर आपत्तिजनक सामग्री अपलोड करने के आरोप में आईटी एक्ट के अंतर्गत तिरुचिरापल्ली के निकट उनके गृहनगर से गिरफ्तार किया गया. कोवन को तिरुचिरापल्ली 30 अक्टूबर को स्पेशल आईटी पुलिस ने हिरासत में लिया. पहले पुलिस वालों ने सादे लिबास में उनका पीछा किया, इसके बाद मौका पाते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद उन पर राजद्रोह, हिंसा भड़काने और लोगों में दुर्भावना फैलाने के आरोप लगाए गए. उनके परिवार वालों को गिरफ्तारी की सूचना दिए बगैर उन्हें गिरफ्तार करके तिरुचिरापल्ली से 375 किलोमीटर दूर चेन्नई ले जाया गया, वहां उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

कोवन कला और साहित्य संगठन मक्कल कलई आईलाक्कियां कझगम के सदस्य हैं. यह संगठन महिलाओं और दलितों जैसे हाशिये पर पहुंचे लोगों के अधिकार को लेकर लोक गीत और नुक्कड़ नाटकों का मंचन करता है. कई समाजसेवी संगठनों ने उनकी गिरफ्तारी का विरोध किया और उन्हें तत्काल रिहा करने की मांग की. एशियन फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डेवलपमेंट ने तमिलनाडु के अधिकारियों से राज्य की जेल में देशद्रोह के आरोप में बंद दलित लोक गायक और सामाजिक कार्यकर्ता एस शिवादास उर्फ कोवम को तत्काल रिहा करने की मांग की. उन्हें आईटी पुलिस ने गिरफ्तार किया और बाद में उनके खिलाफ देशद्रोह जैसे आरोप जड़ दिए गए, ताकि उन्हें जमानत न मिल सके.

कोवन की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए फोरम एशिया के अध्यक्ष हेनरी पिफ्गेन ने कहा कि कोवन की गिरफ़्तारी अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से हुई है. एक स्वस्थ लोकतंत्र में चुने गए लोगों की आलोचना और उनके कार्यों के प्रति सहमति–असहमति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल होते हैं. ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने कोवन के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप किया है. मुख्यमंत्री राज्य की जनता के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करना तत्काल बंद करे. हेनरी कहते हैं कि कोवन का मामला एक बार फिर इस बात को उजागर करता है कि भारत में राजद्रोह के क़ानून आज भी उपनिवेशवादी तंत्र के प्रतीक हैं. इस तरह के कानूनों के बंधन से लोगों को छुटकारा मिलना जरूरी है. इस क़ानून का इस्तेमाल अधिकांशत: मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, कलाकारों और देश के दूसरे आलोचकों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता रहा है.

भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के मुताबिक राजद्रोह की श्रेणी में वे घटनायें आती हैं, जिनमें सरकार के खिलाफ घृणा, अवमानना या असंतोष पैदा किया जाए. इस धारा के अंतर्गत उम्र कैद की सजा का प्रावधान है. यह कानून अभिव्यक्ति के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नहीं है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और कोवन के दोनों गीत सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. ऐसे में कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार उन पर दबाव डाल रही है. कोवम की गिरफ्तारी के विरोध में बड़ी संख्या में लोग और राजनीतिक दल विरोध प्रदर्शन कर उन्हें रिहा करने की मांग कर रहे हैं. राजनीतिक दल पीएमके के संस्थापक एस रमादास ने कोवन की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि शराब तमिलनाडु में सबसे बड़ी बुराई बन गया है. शराब की वजह से प्रदेश के लाखों लोग प्रभावित हैं. रामदास के अनुसार, प्रदेश में बेची जाने वाली 80 प्रतिशत शराब का उत्पादन डीएमके और एआईडीएमके के लोग करते हैं. ऐसे में दोनों पार्टियों में से कोई भी शराबबंदी की दिशा में सार्थक कदम नहीं उठाएगा. वहीं डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि ने नाटकीय ढंग से कोवन को गिरफ्तार करने और उन पर देशद्रोह का मुक़दमा चलाने की आलोचना की है.

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आकड़ों के अनुसार, साल 2004 से 2015 के बीच जहरीली शराब की वजह से 1509 लोग मारे गए हैं. इस अंतराल में यह संख्या देश भर में सबसे ज्यादा है. देश भर में इस दौरान कुल 11,032 लोग मारे गए थे. इन मौतों में से 14 प्रतिशत तमिलनाडु में हो रही हैं. ऐसे में हकीकत को स्वीकार करने में ही जयाललिता की भलाई है. उन्हें शराबबंदी पर लगाम लगाने के लिए कदम उठाने चाहिए, न कि शराबबंदी की पहल करने वालों के खिलाफ देशद्रोह के मुक़दमे दर्ज करना चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

सपा नेतृत्व अब इस जुगाड़ में है कि पार्टी को कोई ऐसा रफूगर मिले, जो फटे की महीन सिलाई कर पाए. लालू यादव का समधी प्रेम फिर से जागृत हो सकता है. महागठबंधन के विस्तार के नाम पर मुलायम को फिर से महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव मिल सकता है. लेकिन अब पुरानी हनक नहीं रह जाएगी और महागठबंधन में शामिल जदयू और कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध भी हो सकता है. इसका पूरा अंदेशा है. लिहाजा, दो अलग–अलग धुरों के धुरंधरों को साथ लेकर बिहार की तर्ज पर एक और महागठबंधन को अस्तित्व में लाने की सुगबुगाहट चल रही है. लेकिन इसके लिए पहल कौन करे?

सपा को रफूगर की तलाश

महागठबंधन में फिर से शामिल हो सकते हैं मुलायम सिंह

प्रभात रंजन दीन

बिहार विधानसभा का चुनाव परिणाम आने के बाद से समाजवादी पार्टी पछतावे में है और नई नीति क्या अख्तियार की जाए, इस पर पार्टी में गंभीर मंथन चल रहा है. जिन शीर्ष नेताओं ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को इस बात के लिए राजी किया कि वे बिहार के महागठबंधन से अलग हो जाएं, उन नेताओं को नीति–निर्माण की प्रक्रिया से कैसे अलग रखा जाए, यह गहन चिंता का विषय बना हुआ है. चिंता इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि महागठबंधन से अलग होने के पक्षधर नेताओं में सबसे आगे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव ही थे. महागठबंधन से अलग होने पर आमादा रामगोपाल यादव के तर्क चाहे निजी रहे हों या राजनीतिक, लेकिन उनके तर्कों ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय फलक पर उभर कर आने का मौका गर्क कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं. बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए पांच सीटों का पचड़ा दूर कर लालू यादव ने दस सीटें सपा के लिए देने का प्रस्ताव भी दे दिया था, लेकिन मामला तो कुछ और ही चल रहा था और डोर कहीं और से खींची जा रही थी. आम राजनीतिक समझ रखने वाले भी यह अच्छी तरह समझते हैं कि समाजवादी पार्टी महागठबंधन से अलग नहीं हुई होती तो बिहार में कई सीटें जीत लेती. सपा के एक–दो मंत्री भी बन जाते, और सबसे अहम यह कि राष्ट्रीय स्तर पर नीतीश के बजाय मुलायम का कद प्रभावकारी चर्चा में होता. भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देशभर के समाजवादियों को एक करने की पहल मुलायम सिंह यादव ने ही की थी और बिहार में महागठबंधन का अस्तित्व में आना मुलायम की उसी पहल और सिलसिलेवार कवायद का नतीजा है. लेकिन आज मुलायम कहीं नहीं हैं. इसे आप उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव पर असर के रूप में भी देख सकते हैं. बिहार चुनाव के परिणामों का समाजवादी पार्टी अपने हित में फायदा उठाएगी, अब यह अवसर हाथ से निकल चुका है. महागठबंधन में शरीक रहती तो यूपी के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का हाथ ऊपर रहता, लेकिन अब तो पासा पलट चुका है. बिहार के मतदाताओं ने भाजपा के वोटकटवा एजेंट का तमगा लगा कर जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी को खारिज कर दिया, उसी तरह बिहार में भाजपा का परोक्ष रूप से साथ देने का कलंक यूपी में समाजवादी पार्टी को काले दिन दिखा सकता है. यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की पेशानी पर बल साफ–साफ देखा जा सकता है. सपा नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं का सुगबुगाहटी–विरोध भी खासा परेशान कर रहा है. महागठबंधन छोड़ने के कारणों से जुड़ा सवाल कार्यकर्ताओं में जितना ही जाग रहा है, पार्टी नेतृत्व उन सवालों से उतना ही भाग रहा है.

सपा नेतृत्व अब इस जुगाड़ में है कि पार्टी को कोई ऐसा रफूगर मिले, जो फटे की महीन सिलाई कर पाए. लालू यादव का समधी प्रेम फिर से जागृत हो सकता है. महागठबंधन के विस्तार के नाम पर मुलायम को फिर से महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव मिल सकता है. लेकिन अब पुरानी हनक नहीं रह जाएगी और महागठबंधन में शामिल जदयू और कांग्रेस की तरफ से इसका विरोध भी हो सकता है. इसका पूरा अंदेशा है. लिहाजा, दो अलग–अलग धुरों के धुरंधरों को साथ लेकर बिहार की तर्ज पर एक और महागठबंधन को अस्तित्व में लाने की सुगबुगाहट चल रही है. इसके लिए पहल कौन करे? जिस समय बिहार का महागठबंधन शक्ल ले रहा था और नीतीश व लालू जैसे धुर विरोधी हाथ मिला रहे थे, उस समय लालू यादव ने उत्तर प्रदेश में भी ऐसे ही विचित्र किंतु सत्य नुमा तालमेल करने की वकालत की थी. तब राजनीतिक विश्लेषकों की भी राय आई थी कि जब लालू–नीतीश मिल सकते हैं तो मायावती–मुलायम क्यों नहीं! उत्तर प्रदेश में मुलायम–मायावती तालमेल की संभावनाएं तो फिलहाल समय के आवरण में हैं, लेकिन बिहार ने यह साबित कर दिया है कि सत्ता हित के लिए नेता राजनीतिक–अस्पृश्यता का अवसरवादी इस्तेमाल कर सकते हैं. इस नजरिए से उत्तर प्रदेश में एक नया सियासी समीकरण करवटें ले रहा है. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने पिछले दिनों कहा भी कि नेताजी (मुलायम) भविष्य की रणनीति फिर से तैयार करेंगे. चर्चा यही है कि मुलायम की नई रणनीति फिर से महागठबंधन में शामिल हो जाने की है. सपाइयों को भी यही उम्मीद है. महागठबंधन में दोबारा शामिल होने से बिगड़ा हुआ परिदृश्य थोड़ा बदल सकता है. महागठबंधन से अलग होने के फैसले से उत्तर प्रदेश का मुसलमान मतदाता सपा से बिदकता हुआ दिख रहा है. ऐसे में सपा का महागठबंधन में फिर शामिल होना मुसलमान मतदाताओं के पलायन को रोक सकता है. अगर समाजवादी पार्टी ने यूपी में कोई राजनीतिक–बाजीगरी नहीं दिखाई तो मुसलमानों के बसपा और कांग्रेस की तरफ खिसकने का पूरा अंदेशा है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें हैं. 224 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी सरकार में है और पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं. यूपी में बसपा के पास 80 सीटें, कांग्रेस और रालोद को 37, भाजपा को 47 और अन्य के पास 15 सीटें हैं.बिहार चुनाव के परिणामों से उत्साहित लालू यादव और नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश में भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतार सकते हैं. बिहार में सीटें जीतकर कांग्रेस भी सोते से जाग उठी है और यूपी के चुनाव में नए जोश से उतरने की तैयारी में है.

बिहार चुनाव के परिपेक्ष्य में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनावों को रख कर देखा जा रहा है. राजनीतिक समीक्षक मानते हैं कि बिहार के चुनाव परिणाम इन पांच राज्यों के चुनाव पर असर डालेंगे और राष्ट्रीय राजनीति में भाजपा का एकजुट विकल्प तैयार होगा.लेकिन इस समीक्षा में स्थान–काल–पात्र को लेकर भी विचार साथ–साथ चलना चाहिए. पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की असली भिड़ंत वाममोर्चा से ही है, ऐसे में बिना वाम को शामिल किए हुए राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के खिलाफ महागठबंधन का कोई कारगर अस्तित्व बनता नहीं दिखता. बंगाल में वाम अलग रहे और राष्ट्रीय राजनीति में साथ रहे, उस स्तर की अवसरवादी राजनीति में वामपंथी दल मुब्तिला नहीं होने वाले हैं. बिहार के महागठबंधन प्रयोग में भी वामदल शरीक नहीं थे. पश्चिम बंगाल में 294 सीटों वाली विधानसभा में तृणमूल और कांग्रेस गठबंधन 226 सीटों के साथ सत्ता में है. वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तल्खियां जगजाहिर हैं, जिसे कम करने की कोशिश समानान्तर गति से चल रही है. पश्चिम बंगाल विधानसभा में वाम मोर्चा के पास 60 सीटें और अन्य के पास 8 सीटें हैं. इस बार वामदल सत्ता हासिल करने की पूरी तैयारी में है, लिहाजा ममता की दूरदृष्टि भी कसौटी पर है, उन्हें वैसा ही गठबंधन बनाना होगा जो तृणमूल को सत्ता से बेदखल न कर सके और वाम दलों को औकात में रख सके. नरेन्द्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तो शुरू में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ मुद्दों पर उनका विरोध जरूर किया, लेकिन बाद में ममता ने कई गंभीर मुद्दों पर भी केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश नहीं की. ऐसे संकेत मिल रहे थे कि ममता और भाजपा के बीच भीतर ही भीतर पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर कुछ चल रहा है. बंगाल के लिए अच्छा पैकेज देकर केंद्र सरकार ममता बनर्जी को पाले में लाने की भरपूर कोशिश कर भी रही है. बांग्लादेश में सीमा समझौते के मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ ममता बनर्जी भी शरीक थीं. लेकिन बिहार चुनाव के बाद समीकरण एक बार फिर बदलता हुआ दिखता है. नीतीश और ममता के बीच बढ़ रही नजदीकियां भी भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं.

2016 में पश्चिम बंगाल के साथ–साथ तमिलनाडु, केरल, असम और केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में भी चुनाव होना है. बिहार में हार के बाद भाजपा इन पांच राज्यों के चुनाव को लेकर सतर्क है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने इसी साल अगस्त में तमिलनाडु चुनाव की तैयारियां बाकायदा शुरू कर दी थीं.235 सीटों वाली तमिलनाडु विधानसभा में 150 सीटों के साथ एआईएडीएमके सत्ता पर काबिज है. मुख्यमंत्री जयललिता की भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अच्छी निभ रही है. डीएमडीके 28 सीटों पर, डीएमके 23, कांग्रेस 5, वामदल18 और अन्य 11 सीटों पर काबिज हैं. समीक्षकों की निगाह तमिलनाडु पर भी है कि वहां महागठबंधन तर्ज का कोई प्रयोग होता है कि नहीं और बिहार चुनाव का कोई असर तमिलनाडु पर पड़ता है कि नहीं. जानकारों का मानना है कि बिहार चुनाव के परिणामों का तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के चुनावों पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर बिहार का असर दिखेगा. असम पर भी इसका असर दिख सकता है, क्योंकि वहां भाजपा का मुख्य मुकाबला कांग्रेस से है, जिसने बिहार में 27 सीटें जीती हैं. बिहार का परिणाम आने के बाद अब पार्टियों का ध्यान असम के चुनाव पर ही केंद्रित हो रहा है. असम का चुनाव भाजपा और कांग्रेस, दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस के खाते में बचे–खुचे कुछ राज्यों में असम एक है. कांग्रेस के सामने सरकार बचाने की चुनौती है तो भाजपा असम को जीतने के लिए पूरी ताकत इस्तेमाल में लाना चाहती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्वोत्तर को भाजपा के प्रभावक्षेत्र में लाने की काफी अर्से से जद्दोजहद करते आ रहे हैं. असम की126 सीटों वाली विधानसभा में 78 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार में है. भाजपा के पास वहां महज 5 सीटें हैं, फिर भी वह सत्ता–स्वप्नदेख रही है. असम में एआईयूडीएफ के पास 18, एजीपी के पास 10, बीपीएफ के 12 और अन्य के खाते में 3 सीटें हैं.

केरल में हाल ही हुए स्थानीय निकाय चुनावों में अच्छे प्रदर्शन से भाजपा को काफी उम्मीद है. वहां भाजपा अपना आधार बढ़ाने में जुटी है. 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में 92 सीटों के साथ यूडीएफ सत्ता में है जबकि विपक्षी एलडीएफ के पास 68 सीटें है.केंद्र शासित प्रदेश पेदुचेरी की भी 30 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव अप्रैल 2016 में ही हैं. वहां एआईएनआरसी 15 सीटों के साथ सत्ता में है. कांग्रेस के पास 7, एआईएडीएमके के पास 5, डीएमके के पास 2 और निर्दलीय के पास एक सीट है. पुदुचेरी के चुनाव पर बिहार का कोई असर नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वहां के राजनीतिक समीकरण बिल्कुल ही अलग हैं. ■

यूपी में भाजपा का चेहरा घोषित करने की मांग तेज

दिल्ली और बिहार के प्रयोगों से भाजपा को मिली भीषण हार के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा के नेता बौखला गए हैं. भाजपा आलाकमान के खिलाफ यूपी में खुला हमला शुरू हो गया है. उत्तर प्रदेश भाजपा के नेताओं का मानना है कि भाजपा नेतृत्व स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के महत्व को जबतक नहीं समझेगा, उसे चुनावों में ऐसी ही पराजय हर तरफ मिलती रहेगी. भाजपा नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनावों को भी पार्टी नेतृत्व लोकसभा चुनाव के नजरिए से देखता है, इसीलिए पार्टी ऐसी स्थिति में पहुंचती जा रही है. भाजपा आलाकमान द्वारा हाशिए पर फेंके जा चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने अर्से बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि अनुभवहीन नेताओं, गलत नेतृत्व और असंयमित भाषा के इस्तेमाल के कारण भाजपा ऐसे राज्यों में भी हार रही है, जहां उसके हारने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी. चिन्मयानंद ने कहा कि अनुभवी और बुजुर्ग नेताओं–कार्यकर्ताओं की उपेक्षा दुर्भाग्यपूर्ण है. उत्तर प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह ने भी अर्से बाद मुंह खोला. उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान के निर्णय में सामूहिकता के विचार की कमी है, लिहाजा पार्टी की कार्यशैली पर चिंतन होना जरूरी है. उन्होंने कहा कि पार्टियां परस्पर विश्वास और सामूहिकता से चलती हैं. भाजपा के पूर्व सांसद राजनाथ सिंह सूर्य ने कहा कि भाजपा आलाकमान को अभी से ही केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा का चेहरा घोषित कर देना चाहिए, नहीं तो यूपी में भी भाजपा का बिहार जैसा ही हाल हो जाएगा. अगर यूपी में भाजपा विधानसभा का चुनाव हार गई तो अगला लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए भारी पड़ जाएगा. प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि आडवाणी–जोशी जैसे अनुभवी नेताओं की सलाह का फायदा लेना पार्टी के हित में होता. फायर ब्रांड नेता विनय कटियार भी बिहार चुनाव में उनका कोई इस्तेमाल नहीं किए जाने के पार्टी नेतृत्व के फैसले से क्षुब्ध हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

भारत सरकार और यूएनडीपी की ओर से विकेंद्रीकरण की दिशा में उठाए जा रहे क़दमों के बीच ओडिशा में केंद्रीय योजनाओं एवं क़ानूनों की स्थिति पर किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि दलितों एवं आदिवासियों के साथ आम निवासी भी इलाके में 1996 से लागू पेसा (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया) क़ानून को नहीं जानते. वे 2006 से लागू वनाधिकार क़ानून जानते हैं, लेकिन उसके प्रावधानों के बारे में न उनकी कोई रुचि है और न ठीक से जानकारी. पेसा क़ानून के तहत इलाके में ग्रामसभा होते उन्होंने न कभी देखी और न सुनी. पेसा क़ानून में स्थानीय रीति-रिवाजों (कस्टमरी लॉज) को स्थान दिया गया है.

मुद्रास्फीति से राजनीति तक

विशाल एस. एन

रिज़र्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने हाल में आईआईटी, दिल्ली के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाषण दिया. राजन लगभग तीन दशक पहले यहां स्वयं विद्यार्थी रह चुके हैं. इस कारण आईआईटी, दिल्ली से उनके दो तरह के संबंध थे, एक भूतपूर्व विद्यार्थी के तौर पर, तो दूसरा भारतीय रिज़र्व बैंक का गवर्नर होने के नाते. ज़ाहिर-सी बात है कि हर भूतपूर्व छात्र को तो मुख्य अतिथि के रूप में दीक्षांत समारोह में अपनी बात रखने के लिए नहीं बुलाया जाता. राजन का भाषण वाकई में अविस्मरणीय था. उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था की वर्तमान दशा पर चिंता जताई और उसके मूलभूत तत्वों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ज़्यादा निवेश करके अधिक मुनाफ़ा कमाने की सोच समस्या का हल नहीं है. स्वस्थ अर्थव्यवस्था के लिए सबसे ज़रूरी चीज है नई पहल या इनोवेशन, न कि ज़्यादा निवेश. नई पहल या इनोवेशन हमेशा आइडिया यानी विचार से आती है. भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत सारे इनोवेशन के लिए बहुत सारे नए-नए विचारों का निरंतर सृजन करना पड़ेगा और नए विचार या आइडिया सिर्फ़ एक ही चीज से आते हैं, वह है सवाल पूछना. बकौल राजन, हमें हर क्षेत्र में सवाल पूछने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा. बुनियादी चीजों पर सवाल करने से तुरंत कोई हल नहीं मिला जाता और न तत्काल कोई इनोवेशन हो जाता है, लेकिन सवाल पूछने से हमें विचारों में वैकल्पिक दृष्टिकोण दिखता है, जो आगे जाकर इनोवेशन में बदलता है. इसलिए हमें विद्यार्थियों में सवाल पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना होगा. पूरी दुनिया में सभी महान एवं अनूठे विचार पुराने विचारों पर सवाल खड़े करने से ही आए हैं. इस वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण और सवालों की प्रवृत्ति का होना बहुत ज़रूरी है. सवालों की संस्कृति विकसित होने पर ही वैकल्पिक दृष्टिकोण के प्रति सम्मान पैदा होता है और वर्तमान विचार ही सार्वभौमिक एवं सर्वमान्य हैं, इस बीमार सोच से छुटकारा भी मिलता है.

राजन ने अपने भाषण में एक दिलचस्प तथ्य का उल्लेख करते हुए कहा कि कैसे राजा चोल ने शिव मंदिर का निर्माण किया, जिसमें विष्णु एवं बुद्ध की भी प्रतिमाएं लगाईं. अकबर ने भी अपने दरबार में हिंदुओं एवं बौद्ध मतावलंबियों को बढ़ावा दिया. इन उदाहरणों के साथ उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत की संस्कृति एवं सभ्यता में अनेकता में एकता की अवधारणा साकार करते हुए विपरीत विचार भी आपसी सामंजस्य के साथ रहते आए हैं, जिससे सहिष्णुता और शांति की अवस्था बनती है, जो किसी भी अर्थव्यवस्था के सुचारू रूप से चलने के लिए आवश्यक है. उन्होंने यह भी कहा कि शरारती तत्व हमेशा समाज में समस्या खड़ी करते हैं और शरारती तत्वों को नज़रअंदाज़ करके ही समाज में शांति एवं सहनशीलता उत्पन्न हो सकती है, जिससे देश की

अर्थव्यवस्था आगे बढ़ सके. उनके इस भाषण से मुख्य सवाल यह उठता है कि रघुराम राजन एक अर्थशास्त्री हैं और भारत के रिज़र्व बैंक के गवर्नर हैं, लेकिन उनका भाषण अर्थव्यवस्था और मुद्रास्फीति जैसे तथ्यों से कहीं दूर राजनीति की ओर जाता दिखाई देता है. इसे सुनकर प्रतीत होता है कि उनके श्रोता आईआईटी के विद्यार्थी नहीं थे, बल्कि शायद वहां से थोड़ी दूर नॉर्थ ब्लाक स्थित वित्त मंत्रालय, रायसीना हिल स्थित प्रधानमंत्री कार्यालय और कट्टरपंथी विचारधारा के सभी समूह थे. सवाल यह उठता है कि क्या अर्थशास्त्री होने के नाते उनका ऐसा भाषण अर्थशास्त्र की विषय-वस्तु में आता है? क्या उन्होंने भारत के रिज़र्व बैंक के गवर्नर होने के कर्तव्यों का अतिक्रमण किया है? क्या भारत के एक अर्थशास्त्री को मुद्रास्फीति और मौद्रिक मामलों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए था?

इन सवालों के जवाब खोजने से पहले हमें 300 ईसा पूर्व के भारत के सबसे बड़े विचारक एवं अर्थशास्त्री कौटिल्य द्वारा दिए गए सिद्धांतों पर ध्यान देना होगा. तक्षशिला के प्राचार्य और दो सम्राटों चंद्रगुप्त एवं बिंदुसार के प्रमुख सलाहकार कौटिल्य एक ब्राह्मण होने के साथ-साथ अर्थशास्त्री भी थे. उनकी लिखी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक-अर्थशास्त्र का लोहा पूरी दुनिया मानती है. उनकी विभिन्न 15 पुस्तकों में राजनीतिशास्त्र, राज्य व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, कूटनीति, अर्थशास्त्र एवं सामरिक रणनीति आदि सभी विषयों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है. अनुशासन, सरकारी निरीक्षकों के कर्तव्य, क़ानून, तख्ता पलट, दुर्गुण, आपदा एवं युद्ध आदि विषयों पर आधारित पुस्तकें कई अध्यायों को मिलाकर बनी है, जिनमें राजा के आचरण, राजनीति, प्रशासन के विभिन्न चरण, सुरक्षा और प्रजा की देखभाल तक यानी हर बिंदु पर विस्तृत चर्चा की गई है. जबकि अर्थ और मुद्रा-व्यवस्था पर सिर्फ़ एक-दो अध्यायों में चर्चा की गई है. कौटिल्य की पुस्तक-अर्थशास्त्र से साफ़ स्पष्ट होता है कि एक सक्षम अर्थशास्त्री का कार्यक्षेत्र सिर्फ़ मुद्रास्फीति और मौद्रिक चीजों तक सीमित नहीं होता, बल्कि उससे कहीं अधिक समाज, प्रशासन एवं राजनीति के हर पहलू तक जाता है. अर्थव्यवस्था समाज के अंतर्गत होती है और हर चीज, जो समाज को प्रभावित करती है, वह अर्थव्यवस्था पर भी उतना ही असर डालती है. राजनीति, राजा, उसका चाल-चलन, खान-पान, सहनशीलता, व्यक्तित्व, बुद्धिमत्ता एवं विचार आदि वे प्रमुख कारक हैं, जो समाज को प्रभावित करते हैं और अर्थव्यवस्था को भी. कौटिल्य ने आदर्श राजा यानी राजर्षि के गुण बताते हुए स्पष्ट कहा है कि उसका खुद पर नियंत्रण होना चाहिए, वह अपनी इंद्रियों का स्वामी होना चाहिए, उसे वरिष्ठ लोगों के साथ रहकर बुद्धि विकसित करनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा एवं कल्याण के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए, अनुशासित होना चाहिए, हर प्रकार का ज्ञान एकत्र करना चाहिए और लोगों का भला करके उनका प्रिय बनना चाहिए. इसके साथ ही उसे सभी जीवों के प्रति अहिंसा का व्यवहार करते हुए हानिकारक लोगों एवं गतिविधियों से दूर रहना चाहिए. कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से इस बात को प्रमाणित किया कि अर्थशास्त्र और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता. राज्य एवं प्रशासन का प्रत्येक पहलू अर्थव्यवस्था से जुड़ा है और उसे अलग करके देखना नामुमकिन है. पुस्तक-अर्थशास्त्र में हज़ारों साल पहले प्रमाणित अर्थशास्त्र के इस अकाट्य सत्य को उद्घाटित करके रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने एक अर्थशास्त्री का कर्तव्य निभाया है. रघुराम राजन ने भारत की संस्कृति ज़िंदा रखते हुए चाणक्य की वह बात दोहरा दी कि राजा एवं उसके मंत्रिमंडल के आचार-विचार और प्रवृत्ति का देश-समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा किसी देश की अर्थव्यवस्था इन चीजों से कभी अछूती नहीं रह सकती. यहां पर यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि रघुराम राजन ही वह अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने पहले से ही 2008 की मंदी की भविष्यवाणी कर दी थी. व्यक्तिगत रूप से आगामी वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका जताकर उन्होंने एक बार फिर अपनी भविष्य आकलन क्षमता प्रमाणित कर दी.

यहां पर यह याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि रघुराम राजन ही वह अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने पहले से ही 2008 की मंदी की भविष्यवाणी कर दी थी. व्यक्तिगत रूप से आगामी वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका जताकर उन्होंने एक बार फिर अपनी भविष्य आकलन क्षमता प्रमाणित कर दी. हमें रघुराम राजन के मन का यह भाव भांपना होगा कि विश्व अर्थव्यवस्था नाजुक परिस्थितियों से गुज़र रही है. पूरी दुनिया विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भारत की ओर देख रही है. भारत अब कोई छोटा-सा विकासशील देश नहीं है, जिसकी राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विश्व पटल पर असर न पड़े. आज भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन चुका है. यहां होने वाली छोटी-सी घटना भी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालती है.

हमें रघुराम राजन के मन का यह भाव भांपना होगा कि विश्व अर्थव्यवस्था नाजुक परिस्थितियों से गुज़र रही है. पूरी दुनिया विश्व अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए भारत की ओर देख रही है. भारत अब कोई छोटा-सा विकासशील देश नहीं है, जिसकी राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का विश्व पटल पर असर न पड़े. आज भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन चुका है. यहां होने वाली छोटी-सी घटना भी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डालती है. इस बात को एक छोटे-से उदाहरण से समझ सकते हैं कि भारत में होने वाले एक छोटे त्योहार के लिए भी विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनियां ज़ोर-शोर से तैयारियां करती हैं. भारत पर आई यह ज़िम्मेदारी पूरी ताकत से निभानी होगी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब-जब विश्व की किसी भी अर्थव्यवस्था पर आर्थिक संकट आया या वह मंदी की चपेट में आई, तो उसकी परिणति सदा जनसंहार और विश्व युद्ध में होती है. ■

(लेखक इंवेस्टमेंट बैंकर एवं जेन एडवाइजर्स के सीईओ हैं.)

feedback@chauthiduniya.com

ओडिशा

योजनाएं फ्लॉप, क़ानून बेअसर

अतुल कुमार

पूर्ण टाकरी (40), नेपाल टाकरी (35), श्याम करकरिया (45) एवं बली करकरिया (35) दलित समुदाय से हैं, वहीं दासरू काटरका (32), दधि पुसिका (65) एवं लक्ष्मण पुसिका (35) डोंगरिया आदिवासी समुदाय से हैं. ये सभी राज्य के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य ज़िले रायगढ़ा के मुनिगुड़ा ब्लॉक की ग्राम पंचायत मुनिखोल निवासी हैं. डोंगरिया समुदाय नियमगिरि शृंखला के पहाड़ों के ऊपर रहता है, वहीं दलित समुदाय पहाड़ के नीचे समतल इलाकों में. समतल में रहने वाले आदिवासियों को कुटियाकुंद कहा जाता है. लद्दू सिकोका (45) एवं नवधन बरक्का (38) कुरली पंचायत के डोंगरिया समुदाय से हैं, जो रायगढ़ा ज़िले के विसमकटक ब्लॉक मुख्यालय से 15-20 किलोमीटर ऊपर पहाड़ में निवास करता है. लद्दू नियमगिरि पहाड़ को वेदांता कंपनी के हाथों में सौंपने के ख़िलाफ़ सफल आंदोलन चलाने वाली नियमगिरि सुरक्षा समिति के रायगढ़ा के अध्यक्ष हैं, जबकि नवधन ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियमगिरि इलाके की 12 पंचायतों में ग्रामसभा की उन बैठकों में दुभाषिए का काम किया था, जो ज़िला जजों की निगरानी में हुई थीं और जिनमें नियमगिरि पहाड़ को बॉक्साइट खनन के लिए वेदांता को न सौंपने का ऐतिहासिक फ़ैसला किया गया था. नियमगिरि पहाड़ रायगढ़ा एवं कालाहांडी यानी दो ज़िलों में फैला है, इसलिए आंदोलन भी दोनों जगह चल रहा है.

भारत सरकार और यूएनडीपी की ओर से विकेंद्रीकरण की दिशा में उठाए जा रहे क़दमों के बीच ओडिशा में केंद्रीय योजनाओं एवं क़ानूनों की स्थिति पर किए गए एक अध्ययन में बताया गया है कि दलितों एवं आदिवासियों के साथ आम निवासी भी इलाके में 1996 से लागू पेसा (पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया) क़ानून को नहीं जानते. वे 2006 से लागू वनाधिकार क़ानून जानते हैं, लेकिन उसके प्रावधानों के बारे में न उनकी कोई रुचि है और न ठीक से जानकारी. पेसा क़ानून के तहत इलाके में ग्रामसभा होते उन्होंने न कभी देखी और न सुनी. पेसा क़ानून में स्थानीय रीति-रिवाजों (कस्टमरी लॉज) को स्थान दिया गया है. इसके तहत समुदायों को परंपरानुसार सभा और व्यवहार करने का प्रावधान है, लेकिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है और न इस संबंध में सरकार की ओर से कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाता है. जागरूकता कार्यक्रमों के नाम पर कुछ ग़ैर सरकारी संगठनों द्वारा सिर्फ़ खानापूर्ति की जाती रही है. पेसा क़ानून 1996 में संसद द्वारा पारित कर नौ राज्यों के आदिवासी बाहुल्य इलाकों पर लागू किया गया. इलाके में केंद्र द्वारा संचालित डोंगरिया समुदाय विकास एजेंसी (डीसीडीए) एवं कुटियाकुंद समुदाय विकास एजेंसी (केकेडी) मौजूद हैं, लेकिन उनकी भी कोई सक्रियता इस दिशा में नहीं है.

वनाधिकार क़ानून के बारे में लोगों के बीच भ्रम है कि वह केवल आदिवासियों के लिए है, अन्य वनवासियों के लिए नहीं. इसलिए आदिवासियों को छोड़कर अन्य किसी जाति-वर्ग के शख्स ने जंगल में पट्टे के लिए कभी आवेदन नहीं किया. आदिवासियों ने भी बहुत कम संख्या में आवेदन किए. ग्राम पंचायत मुनिखोल के आदिवासी सरपंच मालती कटरका (28) कहते हैं कि पहाड़ी इलाकों में जगह बदल कर खेती करने का रिवाज है यानी दो साल एक जगह खेती, तो अगले दो साल जंगल में दूसरी जगह खेती, लेकिन वनाधिकार क़ानून में पट्टा एक जगह का मिलता है. ऐसे में पट्टा लेने के बाद परेशानी होगी. यही नहीं, विभिन्न सरकारी विभागों की उपेक्षा के चलते भी लोग पट्टे के लिए आवेदन नहीं करते. अतीत में कुछ आदिवासियों ने जिस जगह का पट्टा मांगा, वन विभाग एवं तहसील ने उसके बदले उन्हें दूसरी जगह का पट्टा दे दिया, जिसकी पहचान भी आदिवासियों के लिए मुश्किल हो गई. इलाके के डोंगरिया एवं कुटियाकुंद आदिवासी समुदाय परंपरानुसार सामुदायिक रूप से निवास करते हैं. उनके यहां किसी संपत्ति का निजी स्वामित्व नहीं होता, बल्कि वह पूरे समुदाय की होती है. जंगल हो या खेत, उसे सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल किया जाता है. लोग सामूहिक खेती करते हैं और सामूहिक रूप से वनोपज का इस्तेमाल. जबकि वनाधिकार क़ानून में निजी तौर पर पट्टा आवंटन का प्रावधान है. आदिवासियों को लगता है कि यह क़ानून उनमें फूट डालने की सरकारी साज़िश है. वे कोई भी संपत्ति या अधिकार व्यक्तिगत के बजाय सामुदायिक तौर पर चाहते हैं. ऐसे में इस क़ानून के प्रति उनमें घोर अनिच्छा दिखती है. इलाके में जंगल से वनोपज, बांस या सूखी लकड़ी लेने से आदिवासियों को आज तक किसी सरकारी महकमे ने नहीं रोका और न उन्हें कभी पुराने वन क़ानून (1927) से कोई समस्या हुई.

इलाके में इंदिरा आवास योजना की हालत भी दयनीय है. कई लोगों को काफी पहले योजना का लाभ तो मिला, लेकिन उनके घर नहीं बने. दलितों एवं सामान्य बीपीएल समुदायों के लिए इंदिरा आवास योजना अलग है, तो डोंगरिया एवं कुटियाकुंद समुदाय को पीटीजी (प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप) के तहत इसकी धनराशि स्वीकृत होती है. पहाड़ के ऊपरी इलाकों में घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट एवं बालू आदि पहुंचाना कठिन है, क्योंकि ऊपर सिर्फ़ पैदल जा सकते हैं. ऐसे में योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है. लोग उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में कर लेते हैं. एक तथ्य यह भी है कि आदिवासी घर बनाने के लिए जंगली लकड़ियां एवं स्थानीय संसाधन इस्तेमाल करते हैं, वहीं इंदिरा आवास योजना में घर निर्माण के मानक तय हैं. यही स्थिति कालाहांडी ज़िले के लांजीगढ़ ब्लॉक अंतर्गत आने वाली पंचायतों की है. लांजीगढ़ पंचायत के दलित सदानंद नायक, पिछड़े वर्ग के सुरेंदर दंडसेना एवं कुटियाकुंद समुदाय के गुमटी मांझी पेसा क़ानून नहीं जानते. मनरेगा में उनकी कोई रुचि नहीं, क्योंकि भुगतान कई महीने बाद होता है. यहां स्थित वेदांता के प्लांट में उन्हें काफी काम मिल जाता है.

दलितों एवं सामान्य बीपीएल समुदायों के लिए इंदिरा आवास योजना अलग है, तो डोंगरिया एवं कुटियाकुंद समुदाय को पीटीजी (प्रीमिटिव ट्राइबल ग्रुप) के तहत इसकी धनराशि स्वीकृत होती है. पहाड़ के ऊपरी इलाकों में घर बनाने के लिए ईंट, सीमेंट एवं बालू आदि पहुंचाना कठिन है, क्योंकि ऊपर सिर्फ़ पैदल जा सकते हैं. ऐसे में योजना के तहत मिलने वाली धनराशि का दुरुपयोग बड़े पैमाने पर हो रहा है. लोग उसका इस्तेमाल दूसरे कामों में कर लेते हैं.

गुमटी मांझी (62) एवं राजेंद्रपुर की पूर्व सरपंच फूलमे मांझी (35) 2006 में एक्शन एड द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम में लंदन गए थे और उन्होंने वहां वेदांता के मालिक अनिल अग्रवाल से नियमगिरि खनन को लेकर बातचीत की थी. फूलमे कहती हैं कि मनरेगा जैसी योजनाएं यहां फ्लॉप हैं. पेसा क़ानून बेअसर है. हां, वनाधिकार क़ानून के तहत कुछ लोगों को पट्टे मिले हैं और इंदिरा आवास भी बन रहे हैं, लेकिन समस्याएं बहुत हैं. विसमकटक ब्लॉक के बीडीओ राजीव कुमार बोहरा कहते हैं कि इंदिरा आवास के कुछ मामले लंबित हैं, क्योंकि दो साल पहले लोगों ने धनराशि तो ली, लेकिन घर नहीं बनाए. अगर लोग पुराना पैसा वापस करते हैं, तो उन्हें नए सिरे से योजना का लाभ दिया जाएगा. नियमगिरि सुरक्षा आंदोलन के नेता लिंगराज आज़ाद कहते हैं कि आवास योजनाओं के तहत जनजातियों के पारंपरिक मकानों को स्वीकृति मिलनी चाहिए, वनाधिकार क़ानून भी स्थानीय समस्याओं के अनुरूप बनना चाहिए. यही राय ओडिशा गांधी निधि के सदस्य सुरेश संग्राम भी रखते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

ई–कचरे की रीसाइक्लिंग अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है. ई–कचरा न सिर्फ़ जन–स्वास्थ्य को नुक़सान पहुंचा रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहा है. ई–कचरे में कई तरह के ज़हरीले एवं ख़तरनाक रसायन और अन्य पदार्थ जैसे शीशा, कांसा, पारा आदि शामिल होते हैं. सामान्य कचरे के विपरीत ई–कचरा निर्विवाद रूप से बहुत ख़तरनाक है. ऐसे में उत्पादकों की ज़िम्मेदारी है कि वे कम से कम हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल करें.

ख़तरनाक है ई-वेस्ट

मानसी बत्रा

बदलती जीवन शैली और बढ़ते शहरीकरण के चलते भारत ई–कचरे का डंपिंग स्टेशन बनता जा रहा है. भारत में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल के कारण पैदा होने वाले ई–कचरे के दुष्परिणाम से दुनिया बेख़बर है. ई–कचरे से निकलने वाले रासायनिक तत्व लीवर एवं किडनी को प्रभावित करने के अलावा कैंसर और लकवा जैसी बीमारियों की वजह बन रहे हैं. राजस्थान प्रदूषण बोर्ड द्वारा अधिकृत जीरोवेस्ट रिसाइक्लिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने क्योर इंडिया एवं मोरारका फाउंडेशन के सहयोग से नवलगढ़ में ई–कचरा एकत्र करने के लिए पर्यावरण मित्रों का चयन किया है. ग़ौरतलब है कि पर्यावरण को लेकर आज भी हमारे देश में जागरूकता का अभाव है. प्रदूषण जैसे अहम मुद्दा विकास की दौड़ के चलते पीछे छूट गया है. देश के बाज़ार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से भरे पड़े हैं. नई–नई तकनीकों, सुविधाओं, डिजाइनों एवं रंग–रूप वाले फोन लोगों, विशेषकर युवा वर्ग को आकर्षित कर रहे हैं. तकनीक में हो रहे लगातार बदलावों के कारण उपभोक्ता भी नए–नए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से घर भर रहे हैं और पुराने उत्पाद कबाड़ में बेच रहे हैं. यहीं से शुरू होती है ई–कचरे की समस्या.

इलेक्ट्रॉनिक क्रांति के चलते एक तरफ़ जहां लोगों की इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर निर्भरता लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ़ इलेक्ट्रॉनिक कचरे से उत्पन्न होने वाले ख़तरे ने भारत की चिंता बढ़ा दी है. पर्यावरण प्रदूषण और विभिन्न गंभीर बीमारियों का स्रोत बन रहे ई–कचरे को जन्म देने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का भारत प्रमुख उपभोक्ता है. खराब हो चुके मोबाइल फोन, लैपटॉप, फैक्स मशीन, फोटो कॉपियर, टेलीविजन एवं कंप्यूटर आदि का कचरा एक बड़ी तबाही के तौर पर सामने आ रहा है. भारत ई–कचरा पैदा करने वाला दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा देश बन चुका है. भारत ने 2014 में 17 लाख टन इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल उपकरण कचरे के रूप में निकाले. मौजूदा समय में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है. मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि हमारे जीवन के अभिन्न हिस्से बन गए हैं. नई तकनीक के साथ अपने आपको जोड़ने के जुनून में हम भूल जाते हैं कि पुराने कंप्यूटर का क्या होगा? कंप्यूटर ही

इलेक्ट्रॉनिक कचरे के दुष्परिणाम से आम आदमी अभी भी बेख़बर है. ई–कचरा या ई–वेस्ट वह शब्द है, जो तरक्की के इस प्रतीक के दूसरे पहलू की ओर इशारा करता है. वह पहलू है, पर्यावरण का विनाश. पिछले साल दुनिया में सबसे ज़्यादा 1.6 करोड़ टन ई–कचरा एशिया में पैदा हुआ. यानी चीन में 60 लाख, जापान में 22 लाख एवं भारत में 17 लाख टन ई–कचरा.

क्यों, मोबाइल, सीडी, टीवी एवं रेफ्रिजरेटर आदि हमारी ज़िंदगी के इतने अहम हिस्से बन गए हैं कि पुराने के बदले हम फौरन नई तकनीक वाली चीजें खरीदने के लिए तैयार रहते हैं. लेकिन, पुराने उपकरणों यानी ई–वेस्ट को कूड़ेदान में डालते वक्त हम कभी ध्यान नहीं देते कि कबाड़ी वाले तक पहुंचने के बाद यह कबाड़ हमारे लिए कितना ख़तरनाक हो जाता है. यही है, ई–वेस्ट का खामोश ख़तरा. इलेक्ट्रॉनिक कचरे के दुष्परिणाम से आम आदमी अभी भी बेख़बर है. ई–कचरा या ई–वेस्ट वह शब्द है, जो तरक्की के इस प्रतीक के दूसरे पहलू की ओर इशारा करता है. वह पहलू है, पर्यावरण का विनाश. पिछले साल दुनिया में सबसे ज़्यादा 1.6 करोड़ टन ई–कचरा एशिया में पैदा हुआ. यानी चीन में 60 लाख, जापान में 22 लाख एवं भारत में 17 लाख टन ई–कचरा. पिछले साल पैदा हुए ई–कचरे में मोबाइल, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर एवं अन्य छोटे आईटी उपकरणों की हिस्सेदारी महज सात फ़ीसद थी, जबकि क़रीब 60 फ़ीसद हिस्सा घरों और कारोबार में इस्तेमाल होने वाले वैक्यूम क्लीनर्स, टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक रेजर्स, वीडियो कैमरे, वॉशिंग मशीनें एवं इलेक्ट्रिक स्टोव्स जैसे उपकरणों का था. भारत में ई–कचरे के उत्पादन में मुंबई (महाराष्ट्र), चेन्नई (तमिलनाडु) और दिल्ली अव्वल हैं. कुछ वर्षों से ई–कचरे की मात्रा में लगातार तेजी से वृद्धि हो रही है. विश्व भर में प्रति वर्ष लगभग 20 से 50 मीट्रिक टन ई–कचरा फेंका जा रहा है. विश्व भर में उत्पन्न होने वाले ठोस कचरे में ई–कचरे की हिस्सेदारी लगभग पांच फीसद है.

विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे में सबसे तेज वृद्धि दर ई–कचरे में देखी जा रही है, क्योंकि लोग अब अपने टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल एवं प्रिंटर आदि पहले से अधिक जल्दी बदलने लगे है. सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा हो रही है कंप्यूटर एवं मोबाइल से, क्योंकि उनका तकनीकी विकास इतनी तेज गति से हो रहा है कि वे बहुत कम समय में पुराने हो जाते हैं और उन्हें जल्दी बदलना पड़ता है. एक अनुमान के अनुसार, हमारे देश में हर साल लगभग 15 लाख कंप्यूटर एवं 30 लाख मोबाइल के साथ–साथ अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण कबाड़ बन जाते हैं. भविष्य में ई–कचरे की समस्या कितनी विकराल हो सकती है, इसका अंदाज़ा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगातार बढ़ोत्तरी और उनके घटते दामों से लगाया जा सकता है. घरेलू ई–कचरे में लगभग एक हज़ार विषैले पदार्थ होते हैं, जो मिट्टी एवं भू–जल को प्रदूषित करते हैं. इन पदार्थों के संपर्क में आने से सिरदर्द, उल्टी और आंखों में दर्द जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

ई–कचरे की रीसाइक्लिंग अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जिस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है. ई–कचरा न सिर्फ़ जन–स्वास्थ्य को नुक़सान पहुंचा रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी प्रदूषित कर रहा है. ई–कचरे में कई तरह के ज़हरीले एवं ख़तरनाक रसायन और अन्य पदार्थ जैसे शीशा, कांसा, पारा आदि शामिल होते हैं. सामान्य कचरे के विपरीत ई–कचरा निर्विवाद रूप से बहुत ख़तरनाक है. ऐसे में उत्पादकों की ज़िम्मेदारी है कि वे कम से कम हानिकारक पदार्थों का इस्तेमाल करें. उपभोक्ताओं की ज़िम्मेदारी है कि वे ई–कचरे को इधर–उधर न फेंके, बल्कि उसे रीसाइक्लिंग के लिए उचित संस्था को दें. सरकार की ज़िम्मेदारी यह है कि वह ई–कचरे के प्रबंधन के लिए ठोस एवं व्यवहारिक नियम बनाए और उनका पालन सुनिश्चित करे, क्योंकि क़ानून बनाकर सजा का प्रावधान कर देने मात्र से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ■

feedback@chauthiduniya.com

तस्वीरों में यह सप्ताह

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय / सुनील मल्होत्रा*

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाक़ात करते आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत.

नई दिल्ली में नो पीस विदाउट फ्रीडम–नो फ्रीडम विदाउट पीस विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित करते पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह.

दिल्ली मेट्रो के जहांगीरपुरी–समयपुर बादली ट्रैक का उद्घाटन करते केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू एवं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल.

बिहार चुनाव में महा–गठबंधन की ऐतिहासिक जीत के बाद मीडिया से बात करते कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी.

वन रैंक–वन पेंशन के विरोध में जंतर–मंतर पर अपने पदक वापस करते भूतपूर्व सैनिक.

दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी द्वारा नॉन नेट स्कॉलरशिप ख़त्म करने के विरोध में उतरे विभिन्न छात्र संगठन.

1984 में हुए सिख दंगों के विरोध में नई दिल्ली में अपनी किताबें आग के हवाले करते लेखक गुरबचन सिंह बब्बर.

दिल्ली के गांधी नगर इलाके में पहले आम आदमी पॉली क्लीनिक का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल.

नई दिल्ली के करोल बाग में धनतेरस के मौक़े पर आभूषण खरीदती महिला.

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

अगर बिहार चुनाव के बाद विचार, पुनर्विचार एवं योजनाओं का पुनरावलोकन हो, तो बहुत अच्छा होगा, जिस पर मोदी जी अपने बाकी के साढ़े तीन साल तक काम करें. चुनाव से पहले मांस, बीफ, पोर्न या सेंसरशिप के बारे में हमने कभी नहीं सुना था. चुनाव से पहले हमने सुना था कि बुलेट ट्रेनें आएंगी, एफडीआई आएगा, फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और विकास दर नौ-दस प्रतिशत हो जाएगी, लेकिन अब भाषा बिल्कुल बदल गई है. जितनी जल्दी भाजपा अपने वादों एवं योजनाओं पर वापस आएगी, उतना ही भाजपा और देश के लिए बेहतर होगा.

बिहार के नतीजों का केंद्र पर कोई असर नहीं पड़ेगा

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं. हम जैसे कई लोगों ने जो अपेक्षा की थी, ये नतीजे उसी के अनुरूप हैं. महागठबंधन ने भाजपा को न केवल हराया, बल्कि बुरी तरह से हराया. दोनों पक्षों में सीटों का एक बड़ा अंतर है. अब आगे क्या होगा? यह आम सोच है कि केंद्र सरकार पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जो सही नहीं है. प्रधानमंत्री को पांच साल का जनादेश मिला है, जिसमें से 17 महीने गुज़र चुके हैं, लेकिन बिहार चुनाव के नतीजों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला. वर्ष 2016 में पांच राज्यों और 2017 में कुछ अन्य राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. यह एक संघीय व्यवस्था की क़वायद है, जो चलती रहेगी और इनमें से किसी भी राज्य के चुनाव नतीजों का केंद्र सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा. लेकिन, दो बातें महत्वपूर्ण हैं. पहली यह कि अगर महागठबंधन इसे पूरे देश के लिए एक उदाहरण बनाना चाहता है, तो उसे बैठकर कठिन चिंतन करना होगा, लोगों के सामने कुछ ठोस कार्यक्रम रखने होंगे. भाजपा भले ही सेकुलरिज्म का मज़ाक उड़ाए, लेकिन अगर उसे ज़रा भी इतिहास बोध होगा, तो उसे मालूम होगा कि देश का सबसे कमज़ोर आदमी, जो अंग्रेजी नहीं समझता और सेकुलरिज्म का मतलब नहीं समझता, वह भी इस शब्द की आत्मा में छिपे अर्थ को समझता है. बिहार के मतदाताओं ने यह साबित कर दिया है कि देश धार्मिक तनाव के लिए तैयार नहीं है. देश बीफ या मांस या दूसरी किसी संकीर्ण सोच के नाम पर खून की होली खेलने के लिए तैयार नहीं है. वह दौर ख़त्म हो गया है. भाजपा और आरएसएस जितनी जल्दी इस सच्चाई को समझ लेंगे, उतना ही सबके लिए बेहतर होगा.

नीतीश सरकार के लिए ज़रूरी यह है कि वह विशेषज्ञों के साथ बैठकर अपने अगले पांच वर्षों का आर्थिक कार्यक्रम तैयार करे. उसे यह साबित करना होगा कि नरेंद्र मोदी का बुनियादी ढांचे के विकास और 1.25 लाख करोड़ रुपये का वादा केवल वादा था, असल काम हम करेंगे. यह पैसा, जिसे नीतीश ने साफ़ तौर पर दिखाया था, पहले से ही अलग-अलग योजनाओं के लिए स्वीकृत था, जिसे इकट्ठा करके 1.25 लाख करोड़ रुपये का आंकड़ा पेश कर दिया गया. उन्हें एक विश्लेषणात्मक दस्तावेज़ तैयार करना चाहिए और उसे जनता के सामने लाना चाहिए कि किसी मद में, किस तरह से कितनी रक़म खर्च की जाएगी, ताकि कोई ठोस नतीजा निकल सके. चिदंबरम के शब्दों में, व्यय का खाका तो ठीक है, लेकिन उसके नतीजे ज़्यादा अहम हैं. इसलिए नतीजों के लिए एक समय सीमा तय की जानी चाहिए. साल दर साल हमने यह हासिल किया, इतने स्कूल बने, इतनी सड़कें बनीं, इतने अस्पताल बना लिए गए, मेरे ख्याल में यह पहली चीज़ है, जिसे करना चाहिए. अगर आने वाले दो-तीन महीनों में वह ऐसा करते हैं, तो उनकी विश्वसनीयता में इजाफ़ा होगा.

दूसरी बात जो हो रही है, वह भाजपा के अंदर हो रही है, जिससे केंद्र सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा. एक पार्टी की हैसियत से भाजपा को अपने अंदर झांक कर देखना होगा. आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार एवं

एक पार्टी की हैसियत से भाजपा को अपने अंदर झांक कर देखना होगा. आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार एवं यशवंत सिन्हा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही पत्र लिखकर अपनी बात रख दी है. मीडिया ने भी इसका नोटिस लिया है. इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, भोला प्रसाद सिंह एवं मनोज तिवारी ने भी अपनी बात रखी है. पूर्व विदेश सचिव आरके सिंह ने आरोप लगाया था कि बिहार चुनाव में पैसे लेकर पार्टी के टिकट दिए गए हैं. यह ऐसा आरोप था, जो भाजपा में किसी ने पहली बार लगाया.

यशवंत सिन्हा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने पहले ही पत्र लिखकर अपनी बात रख दी है. मीडिया ने भी इसका नोटिस लिया है. इसके अलावा शत्रुघ्न सिन्हा, भोला प्रसाद सिंह एवं मनोज तिवारी ने भी अपनी बात रखी है. पूर्व विदेश सचिव आरके सिंह ने आरोप लगाया था कि बिहार चुनाव में पैसे लेकर पार्टी के टिकट दिए गए हैं. यह ऐसा आरोप था, जो भाजपा में किसी ने पहली बार लगाया. ऐसे आरोप छोटी पार्टियों पर लगाए जाते थे, लेकिन भाजपा के लिए यह पहला मौक़ा है, जिस पर उसे ध्यान देना चाहिए. अगर इस आरोप में सच्चाई है, तो दोषियों के ख़िलाफ़ अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए. अगर इसमें सच्चाई नहीं है, तो भी यह पता लगाना चाहिए कि इस तरह की अफ़वाह कैसे फैली? दरअसल, भाजपा ने अयोग्य उम्मीदवारों को टिकट दिए. भाजपा को आत्मचिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसका बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है. उत्तर प्रदेश में भाजपा, मुलायम सिंह और मायावती का एक-दूसरे से मुक़ाबला है और भाजपा के लिए वहां कुछ अनुकूल परिस्थितियां बन सकती हैं, क्योंकि सरकार विरोधी फैक्टर मुलायम सिंह को प्रभावित कर सकता है.

मैं यह नहीं कहता कि बहुत जल्द कुछ होने वाला है, लेकिन दो संभावनाएं हैं. पहली यह कि भाजपा अपनी पुरानी भाषण कला जारी रखेगी, जिसका उसे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा. दूसरी संभावना यह है कि भाजपा लोगों की मनोदशा समझते हुए उसी हिसाब से अपनी सोच में बदलाव करेगी और समावेशी नीतियां बनाएगी. यदि वह सेक्युलर शब्द पसंद नहीं करती, तो उसे यह शब्द इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसे सभी धर्मों के सम्मान की बात कहनी चाहिए, जिसका प्रावधान देश के संविधान में है. नरेंद्र मोदी बार-बार यह कहते हैं कि भारत के लिए जो सबसे पवित्र किताब है, वह है संविधान. उन्होंने इस थ्योरी को ख़ारिज कर दिया है कि भगवत गीता को देश की प्रमुख किताब बना दिया जाए. अगर आप संविधान के लिहाज से देखेंगे, तो आरएसएस और उसकी विभिन्न शाखाओं द्वारा जो भाषा बोली जा रही है, वह संवैधानिक नहीं है.

वे लेखकों द्वारा पुरस्कार वापसी का मज़ाक उड़ा रहे हैं. यह कोई मज़ाक का विषय नहीं है, बल्कि उनके लिए शर्म की बात है. उनके समर्थक बहुत आसानी से कह देते हैं कि उक्त लेखक इन पुरस्कारों के योग्य नहीं हैं. ये सब बचकाना बातें हैं, जो उनकी पार्टी के विनाश का कारण बनेंगी. और, अगर वे सफल हो जाते हैं, तो देश का नुक़सान होगा, क्योंकि लोकतंत्र इसी तरह असफल होता है. एक पार्टी और एक तरह की सोच से ही फासीवाद का आगमन होता है. अगर बिहार चुनाव के बाद विचार, पुनर्विचार एवं योजनाओं का पुनरावलोकन हो, तो बहुत अच्छा होगा, जिस पर मोदी जी अपने बाकी के साढ़े तीन साल तक काम करें. चुनाव से पहले मांस, बीफ, पोर्न या सेंसरशिप के बारे में हमने कभी नहीं सुना था. चुनाव से पहले हमने सुना था कि बुलेट ट्रेनें आएंगी, एफडीआई आएगा, फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोज़गार के अवसर पैदा होंगे और विकास दर नौ-दस प्रतिशत हो जाएगी, लेकिन अब भाषा बिल्कुल बदल गई है. जितनी जल्दी भाजपा अपने वादों एवं योजनाओं पर वापस आएगी, उतना ही भाजपा और देश के लिए बेहतर होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

खादी अब ग़रीबों को लूटने के लिए है-3

वेतन बढ़ाने की मांग पर चली गोलियां

मज़दूरों का आरोप है कि आश्रम में कार्यरत हरिजन कत्तिनों एवं बुनकरों के लिए सरकार से आश्रम के व्यवस्थापकों को बाढ़ सहायता और सुरक्षा सहायता राशि मिली थी, पर यह सब हड़प लिया गया तथा मज़दूरों को कुछ नहीं मिला. मज़दूरों का यह भी कहना है कि फर्जी बीजकों से माल खरीदा जाता है. आश्रम में पहले कंबल बनाया जाता था, पर इसे बंद कर अब बाहर से कंबलों की खरीद की जाती है. शायद कमीशन ही इसका रहस्य है. गांधी आश्रम, मगहर के मंत्री शिव कुमार पांडे ने अपने लड़के मदन कुमार पांडे को आश्रम में नौकरी दे रखी है. 20-25 वर्षों से कार्यरत कार्यकर्ताओं का वेतन तो पांच-छह सौ से अधिक नहीं है, जबकि मदन कुमार पांडे की नियुक्ति के समय ही उसका वेतन 500 रुपये निर्धारित किया गया. इन तमाम कारणों से खादी आश्रम के मज़दूरों में असंतोष तो था ही, आश्रम व्यवस्थापकों ने जब कार्यकर्ताओं का महंगाई भत्ता दस रुपये से घटाकर पांच रुपये कर दिया, तो स्थिति बेकाबू हो गई. मगहर में ही सरकारी कताई मिल है, जहां मज़दूरों ने आंदोलन कर अपना वेतन बढ़वा लिया था. उसके अनुकरण पर गांधी आश्रम के मज़दूरों ने भी एक जनवरी, 1981 को अपनी यूनियन बनाई तथा खोका सिंह को अपना अध्यक्ष चुना. खोका सिंह उर्फ अनुग्रह नारायण सिंह मगहर कताई मिल मज़दूर यूनियन के भी अध्यक्ष थे तथा उन्हीं के नेतृत्व में मज़दूरी बढ़ी थी. आश्रम की यूनियन का पंजीकरण भी हो गया.

एक अजीब स्थिति थी, क्योंकि तालाबंदी ख़ुद व्यवस्थापकों ने की थी तथा माफी वे मज़दूरों से मंगवा रहे थे. मज़दूरों ने कहा कि प्रबंधकों द्वारा इस प्रकार की शर्त रखना लोकतंत्र और भारतीय संविधान के विरुद्ध स्पष्ट धोखाधड़ी है. वे वापस लौट गए. जवाब में व्यवस्थापकों ने 30-35 वर्षों से कर्मठता से काम कर रहे 450 मज़दूरों को आश्रम से बर्ख़ास्त कर दिया और इसके साथ ही स्थानीय गुंडों से उन पर अत्याचार कराया जाने लगा.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

सात अप्रैल, 1981 को दोपहर के समय खाने की छुट्टी में मज़दूरों ने अपनी पहली सभा की, जिसमें लगभग साढ़े चार सौ मज़दूरों ने हिस्सा लिया. उन्होंने सर्वसम्मति से वेतन बढ़ाने और कारखाना अधिनियम लागू करने की मांग की. ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, बेगार बंद कराने, भ्रष्टाचार की जांच कराने और लखनऊ एवं गोरखपुर के खादी भंडारों में गबन संबंधी आरोपों की जांच की मांग की गई. सभा करने के बाद मज़दूरों ने खाना खाया और काम पर जाने की तैयारी करने लगे. अध्यक्ष खोका सिंह कताई मिल की तरफ़ चले, तभी अचानक उनके ऊपर गोली चली, जिससे वह घायल हो गए. कुछ और मज़दूरों को भी गोलियां लगीं. दूसरी तरफ़ अचानक गांधी आश्रम का दरवाजा बंद कर दिया गया. जो लोग अंदर थे, उन्हें भी बाहर निकाल दिया गया. घटनाक्रम से भौचक मज़दूरों ने देखा कि दरवाजे पर एक नोटिस चिपकाई जा रही है, जिसमें लिखा था, माननीय मंत्री जी ने आदेश दिया है कि आश्रम में सुरक्षा की दृष्टि से दिनांक 8.4.81 से काम बंद रहेगा. पुन: आश्रम का काम प्रारंभ होने की सूचना गेट पर लगा दी जाएगी. इस नोटिस पर व्यवस्थापक पुरुषोत्तम तिवारी के हस्ताक्षर थे. पुलिस ने भी आश्रम के व्यवस्थापकों का साथ दिया तथा मज़दूरों के ख़िलाफ़ झूठे मुक़दमे दर्ज किए जाने लगे. जब मज़दूरों ने उत्तर प्रदेश सरकार, इंदिरा गांधी, खादी ग्रामोद्योग आयोग आदि के पास अपनी शिकायतें पहुंचाईं और तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के आवास पर धरना दिया, तो व्यवस्थापकों ने अख़बारों में आश्रम खोलने का विज्ञापन छपवाया और कहा, अख़बारों में छपी सूचना के बाद भी यदि मज़दूर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे, तो उनकी सेवा समाप्त समझी जाएगी. श्रम आयुक्त, गोरखपुर ने भी मज़दूरों को ड्यूटी पर लिए जाने का आश्वासन दिया.

लेकिन जब श्रमिक खादी आश्रम के दरवाजे पर ड्यूटी देने पहुंचे, तो आश्रम के मंत्री की यह सूचना पढ़कर वे दंग रह गए, श्री गांधी आश्रम मगहर (बस्ती) के श्रमिकों को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि गांधी आश्रम ने निर्णय लिया है कि आश्रम का काम सुचारू रूप से चालू करना है, तो यह आवश्यक है कि जो श्रमिक 7.4.81 को आश्रम का काम छोड़कर चले गए थे, वे उसके लिए पश्चाताप करें और आगे शांतिपूर्वक काम करने का आश्वासन दें तथा इस संदर्भ में आश्रम द्वारा निर्धारित फार्म पर हस्ताक्षर करें. यह एक अजीब स्थिति थी, क्योंकि तालाबंदी खुद व्यवस्थापकों ने की थी तथा माफी वे मज़दूरों से मंगवा रहे थे. मज़दूरों ने कहा कि प्रबंधकों द्वारा इस प्रकार की शर्त रखना लोकतंत्र और भारतीय संविधान के विरुद्ध स्पष्ट धोखाधड़ी है. वे वापस लौट गए. जवाब में व्यवस्थापकों ने 30-35 वर्षों से कर्मठता से काम कर रहे 450 मज़दूरों को आश्रम से बर्ख़ास्त कर दिया और इसके साथ ही स्थानीय गुंडों से उन पर अत्याचार कराया जाने लगा. धारा 144 की आड़ में फर्जी केस कायम कर उन्हें जेल भिजवाने की कोशिश भी की गई.

जारी...

feedback@chauthiduniya.com

संपादकीय

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

बिहार का फ़ैसला एक सबक है

बिहार चुनाव बीत गया, लेकिन बिहार चुनाव की धूल अभी बाकी है. यह धूल किसी को सीख देगी, यह पता नहीं, पर जनता ने इस धूल से सीख ली है और जनता ने एक फ़ैसला भी दिया है. यह फ़ैसला भी दोहरी धार वाला फ़ैसला है.

बिहार चुनाव ने यह बताया कि मुद्दों के ऊपर बातचीत करना किसी को पसंद नहीं आता, लेकिन अगर मुद्दों के ऊपर स्वयं प्रधानमंत्री बात न करें, तो यह ज़्यादा ख़तरनाक है. मुद्दों के ऊपर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बात न करें, तो यह उस ख़तरे को और बढ़ाता है. दरअसल, चुनाव लोक शिक्षण का सबसे बड़ा माध्यम है. कोई दल या नेता कितनी समझ रखता है, जनता को लेकर उसके मन में कितना विश्वास है और वह जनता को ग़ैर समझदारी के दलदल से कितना बाहर निकालना चाहता है, इन सबकी परीक्षा का केंद्र कोई भी चुनाव होता है. जब यह चुनाव लोकसभा या किसी विधानसभा का हो, तो इस परीक्षा केंद्र की गंभीरता बढ़ जाती है. हम एक बार किसी परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, तो उसी तरीके से दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर लेंगे, इस धारणा को बिहार चुनाव ने ग़लत साबित कर दिया. केंद्र का चुनाव लोकसभा में अभूतपर्व बहुमत के साथ भाजपा ने जीता और उसने उस चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण रूप से दोषी ठहराया. कांग्रेस की नीतियों का दिवालियापन, कांग्रेस के नेताओं का मुद्दों को न समझ पाना और समझ कर भी ग़लत जवाब देना भाजपा के पक्ष में गया. भाजपा ने सोचा कि वही तरीका वह बिहार विधानसभा चुनाव में अपना कर पुन: बहुमत प्राप्त कर लेगी. भाजपा यह भूल गई कि बिहार चुनाव, जो हाल में संपन्न हुए और लोकसभा चुनाव, जो डेढ़ साल पहले संपन्न हुए, उनमें बड़ा अंतर है. डेढ़ साल का अंतर है. यह डेढ़ साल का समय लोगों को यह जानने के लिए काफी है कि डेढ़ साल पहले जो वायदे हुए, उन पर कोई अमल हुआ या नहीं. डेढ़ साल पहले हुए चुनाव में भाजपा ने यह कहीं नहीं कहा कि जब वह आएगी, तो पांच साल के बाद क़दमों की शुरुआत करेगी और पांच साल तक वह क्या क़दम उठाए जाएंगे, इसके बारे में सोच-विचार, खाका खींचने, विश्लेषण, बुद्धिजीवियों की बैठकों, कुछ करो या न करो की रणनीति पर चलेगी. और, जब एक ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के बतौर चुनाव लड़ रहा था, जो राज्य का मुख्यमंत्री भी रह चुका है, तो देश के लोगों ने विचारधारा पर ध्यान नहीं दिया. देश के लोगों ने कांग्रेस के नकारापन के ख़िलाफ़ उस व्यक्ति की बातों पर भरोसा किया, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर परखना बाकी था.

डेढ़ साल के बाद यह पता चला कि केंद्र सरकार का नेता, जो बिहार में घूम रहा है, उसके खाते में बड़े-बड़े वायदे अभी भी हैं, बड़ी-बड़ी घोषणाएं अभी भी हैं, लेकिन मध्यम वर्ग एवं निम्न-मध्यम वर्ग, जो वोट देता है या राय बनाता है, के लिए उसके पास कुछ नहीं है. क्योंकि, डेढ़ साल में बिहार के लोगों ने देखा कि उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क़ नहीं आया और फ़र्क़ न आने का ठीकरा उन्होंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर फोड़ दिया. उन्हें लगा कि राज्य सरकार कुछ कर ही नहीं सकती, अगर केंद्र सरकार की नीतियां राज्य सरकार के पक्ष में न हों. इसका यह जवाब कि अगर भाजपा की सरकार होगी, तो केंद्र और राज्य की सरकारें एक सुर में बोलेंगी, बिहार के लोगों ने अस्वीकार कर दिया. लोगों ने स्वयं को इतना खामोश रखा कि न भाजपा कुछ समझ पाई, न मीडिया कुछ समझ पाया और न सर्वे करने वाले कुछ समझ पाए. यही नहीं, भाजपा के विरोधी भी जनता के मन को, मूड को नहीं समझ पाए.

भाषा जिसमें पाकिस्तान आया, भाषा जिसमें बड़े-बड़े महान शब्द आए, भाषा जिसमें आरक्षण आया और भाषा जिसमें हिंदू एवं मुसलमान आए, भाषा जिसमें पहली बार मुसलमानों को देश का हिस्सा न मानने की गंध आई, उसने सारे देश के लोगों को आश्चर्य चकितकर दिया. और, जब देश के लोग आश्चर्य चकित हुए, तो बिहार के लोग कैसे न होते. तब लोगों ने व्यक्तित्व की तुलना की और उस तुलना में उन्हें लगा कि नीतीश कुमार का भाषण संयमित है. नीतीश कुमार की शालीनता और प्रधानमंत्री के धारा प्रवाह भाषण एवं शारीरिक भाषा पलड़े में ऊपर-नीचे हो गई. प्रधानमंत्री थोड़ा ऊपर हो गए पलड़े में और नीतीश कुमार थोड़ा नीचे हो गए.

इसके अलावा एक वैचारिक प्रयोग बिहार की जनता ने नकार दिया. आरक्षण के ऊपर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान कि इसकी विवेचना होनी चाहिए, से लोगों को लगा कि यह उन्हें एक इशारा है कि अगर बिहार का चुनाव भाजपा जीतती है, तो सारे देश में आरक्षण को लेकर न केवल बहस होगी, बल्कि एक आयोग बनेगा, जो आरक्षण को लेकर नई सिफारिशें करेगा, जिनमें आरक्षण का आधार बदल दिया जाएगा और फिर उसे लेकर देश में एक नई लड़ाई शुरू होगी. शायद ये बातें लोगों को पसंद नहीं आईं. लालू यादव के ख़िलाफ़ जिस तरह व्यक्तिगत हमले प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के हर नेता ने किए, उसे भी बिहार ने पसंद नहीं किया. लालू यादव का जंगलराज, प्रधानमंत्री की डेढ़ साल पहले हुई अप्रतिम विजय, केंद्र सरकार के सारे मंत्रियों का बिहार में गली-गली गांव-गांव घूमना और इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता आपसी बातचीत में चुनाव से पहले कहने लगे कि लड़ाई कांटे की है. मेरा माथा तभी ठनका था और मैं अपने अख़बार में एवं टेलीविजन चैनलों में इस अंतर्विरोध को नहीं समझ पाता था कि जहां

बिहार चुनाव यह बताता है कि केंद्र सरकार को जुमलेबाजी, बयानबाजी छोड़कर झूठ की दुनिया से बाहर निकलना होगा. उसे सचमुच उन लोगों के लिए काम करना होगा, जो प्यासे हैं, भूखे हैं, बीमार हैं, अधनंगे हैं और जिन्हें हम दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं मुसलमान कहते हैं. अगर उनके पक्ष में भाजपा सरकार की नीतियां कुछ नहीं करतीं, तो फिर बड़ी-बड़ी योजनाओं का जो सपना प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, वह उन्हें 2019 में वैसी हार दिला सकता है, जैसी 2015 के चुनाव ने बिहार में दिलाई है.

पर लालू यादव का जंगलराज हो, उनके ख़िलाफ़ सजाओं के कसीदे पढ़े जा रहे हों और जहां विशाल बहुमत से जीती भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही हो, वहां भाजपा नेता आपसी बातचीत में कांटे की टक्कर कह रहे हैं! इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे नेताओं को चुनाव में हार का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अपने किसी हसीन सपने में खोए हुए थे.

बिहार चुनाव यह बताता है कि केंद्र सरकार को जुमलेबाजी, बयानबाजी छोड़कर झूठ की दुनिया से बाहर निकलना होगा. उसे सचमुच उन लोगों के लिए काम करना होगा, जो प्यासे हैं, भूखे हैं, बीमार हैं, अधनंगे हैं और जिन्हें हम दलित, आदिवासी, पिछड़े एवं मुसलमान कहते हैं. अगर उनके पक्ष में भाजपा सरकार की नीतियां कुछ नहीं करतीं, तो फिर बड़ी-बड़ी योजनाओं का जो सपना प्रधानमंत्री दिखा रहे हैं, वह उन्हें 2019 में वैसी हार दिला सकता है, जैसी 2015 के चुनाव ने बिहार में दिलाई है. और, यह बात मैं सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं. यह बात कांग्रेस के लिए लागू हो चुकी है और यही बात अब भारतीय जनता पार्टी के लिए लागू होने वाली है.

टेलीविजन चैनलों पर दबाव डालकर प्रोग्राम बदलवा देना, टेलीविजन चैनलों के ऊपर अपना चेहरा लाकर लंबी-लंबी बातें करना, अख़बारों को अपनी मुट्ठी में कर लेना, अख़बारों के ऊपर दबाव डालना, अख़बार मालिक को डरा देना, ताकि वह अपने पत्रकारों को कोड़े लगाए आदि से चुनाव नहीं जीता जाता. अख़बार न चुनाव जिताते हैं और न हराते हैं. टेलीविजन पर दिखने वाला चेहरा न लोगों को पसंद आता है और ज़्यादा दिखने पर उसकी कमियां ज़्यादा नज़र आती हैं. चेहरा वही इतिहास में दर्ज हो पाता है, जो ग़रीबों, भूखों, नंगों, पिछड़ों एवं मुसलमानों की ज़िंदगी में बदलाव लाने की बात करे. यहां मैं स्वर्ण ग़रीबों की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब इन सबकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, तो स्वर्ण ग़रीबों की ज़िंदगी में बदलाव आएगा ही आएगा. लेकिन, अगर स्वर्ण ग़रीबों की ज़िंदगी में बदलाव लाने की योजना बनेगी, तो उससे पिछड़ों, मुसलमानों, दलितों एवं आदिवासियों की ज़िंदगी में बदलाव नहीं आएगा. इस बारीकी को भारतीय जनता पार्टी शायद अभी नहीं समझना चाहती.

इसलिए विनम्रता से निवेदन श्री नरेंद्र मोदी से, अरुण जेटली से, क्योंकि ये दोनों आज सरकार चला रहे हैं. इन्हें चाहिए कि तुरंत विशेषज्ञों के साथ बैठकर ऐसी आर्थिक नीतियां बनाएं, जो देश के ग़रीबों, गांवों, किसानों एवं नौजवानों को कुछ आशा दें. प्रधानमंत्री जी, विश्वास कीजिए, देश के लोगों की आशा ख़त्म हो रही है. उन्हें भरोसा नहीं रहा कि उनकी ज़िंदगी में अगले तीन सालों में भी कोई परिवर्तन आ पाएगा या नहीं. और, आपकी जीत की मुख्य वजह यह थी कि आपने लोगों को भरोसा दिलाया था कि आपके प्रधानमंत्री बनते ही बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा. अब अगर आप यह भाषा इस्तेमाल करेंगे कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, तो आप और आप जिनके उत्तराधिकारी हैं यानी मनमोहन सिंह, दोनों में कोई फ़र्क़ नहीं रह जाएगा. ■

editor@chauthiduniya.com

भारत को थैचर से सीख लेनी चाहिए

मेघनाद देसाई

असहिष्णुता के ख़िलाफ़ बहुत-सी आवाज़ें उठ रही हैं. लोग कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता, जो नेहरू की विरासत है, पर ख़तरा है. बहरहाल, देश में दशकों तक धर्मनिरपेक्षता का दबदबा रहा, लेकिन इसके बावजूद यह एक अभिजात्यवर्गवादी विचारधारा ही रही. नतीजतन यह निचले वर्ग के लोगों तक नहीं पहुंच सकी. यहां तक कि स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले राजनेता अत्यधिक धार्मिक हैं और सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए वे धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़े हुए हैं.

जब मैं पहली बार इंग्लैंड गया, तो मैंने देखा कि वहां की राजनीति बड़ी दिलचस्प थी. हालांकि, वहां की दो पार्टियों कंजरवेटिव एवं लेबर के बीच सख्त मुक़ाबला रहता था, लेकिन राज्य की भूमिका, कल्याणकारी कार्यों की अहमियत, बाज़ार के उतार-चढ़ाव और उदारवाद के प्रति द्विपक्षीय आम सहमति बनी रहती थी. लेकिन, 1970 के दशक में अर्थव्यवस्था में आई गिरावट न तो लेबर रोक सके और न कंजरवेटिव. वर्ष 1979 में मार्गरेट थैचर जब चुनाव जीतकर आईं, तो उन्होंने आम सहमति की पुरानी प्रथा ख़त्म कर दी. इसे लेकर लोग नाराज़ हुए और अचंभित भी. थैचर ने खुले बाज़ार की वकालत की, ट्रेड यूनियनों को अधिक लोकतांत्रिक बनने पर मजबूर किया और लोक हितकारी कार्यक्रमों की अहमियत कम की. उनके कार्यकाल में अश्वेत एवं एशियाई मूल के लोग स्वयं को अलग-थलग महसूस करने लगे. पूरे देश में नस्लभेदी दंगे हुए. थैचर के ख़िलाफ़ शिक्षकों ने बगावत की. इसके बावजूद वह एक के बाद एक चुनाव जीतती रहीं. थैचरवाद के विरुद्ध लड़ाई में जो बात हमें समझ में नहीं आई, वह थी कि लोग आम सहमति की प्रथा से ऊब चुके थे. संभ्रांत वर्ग जो भी सोचे, लोगों का झुकाव दक्षिणपंथ की तरफ़ हो चुका था. बाद में टोनी ब्लेयर के नेतृत्व में लेबर पार्टी ने इस नई संस्कृति को अपना कर ही चुनाव जीता था.

भारत को भी इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है. असहिष्णुता के ख़िलाफ़ बहुत-सी आवाज़ें उठ रही हैं. लोग कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता, जो नेहरू की विरासत है, पर ख़तरा है. बहरहाल, देश में दशकों तक धर्मनिरपेक्षता का दबदबा रहा, लेकिन इसके बावजूद यह एक अभिजात्यवर्गवादी विचारधारा ही रही. नतीजतन यह निचले वर्ग के लोगों तक नहीं पहुंच सकी. यहां तक कि स्वयं को धर्मनिरपेक्ष कहने वाले राजनेता अत्यधिक धार्मिक हैं और सिर्फ़ लोगों को दिखाने के लिए वे धर्मनिरपेक्षता का लबादा ओढ़े हुए हैं. लेकिन, सबसे गंभीर समस्या भारतीय राजनीति का कमज़ोर होना है. मंडलवाद ने गठबंधन सरकारों के दौर की शुरुआत की, जिसकी वजह से सरकारें कमज़ोर होने लगीं. बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई और प्रधानमंत्री पूजा पर बैठे रहे. कांग्रेस शासित महाराष्ट्र में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे और श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट के बावजूद आज तक किसी को सजा नहीं हुई. मुसलमान आज भी ग़रीबी और उपेक्षा का शिकार हैं.

जब यूपीए-2 के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, तो बदलाव की मांग शुरू हुई. भाजपा समावेशी विकास के नारे के साथ चुनकर आई, लेकिन वह हमेशा से कांग्रेस की विचारधारा को सूडो-सेकुलरिज्म की विचारधारा कहती आई थी. यह थैचर की तरह इस विचारधारा का खोल तोड़ना चाहती थी. दरअसल, कांग्रेस के 67 वर्षों के शासन के बाद भाजपा ने एक सांस्कृतिक युद्ध शुरू करके देश को चौंका दिया. यह सांस्कृतिक युद्ध इतिहास जैसे कई और क्षेत्रों में लड़ा जाएगा. भाजपा मुस्लिम दौर के इतिहास, बल्कि प्राचीन इतिहास के नेहरूवादी संस्करण पर सवाल खड़े करती रही है. इतिहास को लेकर कई देशों में विवाद होता रहता है. इतिहास का कांग्रेसी संस्करण कुछ बहुत महान इतिहासकारों द्वारा विकसित किया गया है. इसके बावजूद वैकल्पिक व्यवस्था आधिपत्यवादी संस्करण को चुनौती देती रही है. भारत के एक तार्किक देश होने के नाते विवादों से बचना अजीब लगता है. दरअसल, विवादों के बीच एक रेखा खींची जानी चाहिए, जिसे पार करने पर कोई विवाद ख़तरनाक बन सकता है. यह रेखा मुट्ठी भर लोगों द्वारा अलोकप्रिय घटना अंजाम दिए जाने के क्षेत्र में खींची जानी चाहिए. इस संबंध में कई ग़लतियां हुई हैं. कई समूह तर्कवादियों एवं कलाकारों पर हमले के बाद भी पकड़ से बाहर हैं. एमएफ हुसैन को देश छोड़कर जाना पड़ा. तीन तर्कवादियों की हत्या अब भी रहस्य बनी हुई है. ऐसी घटनाएं कोई नई नहीं हैं. फर्क सिर्फ़ इतना पड़ा है कि फ़िलहाल सत्ता किसी और के हाथ में है. बहरहाल, 1997 में जब दिलीप कुमार को पाकिस्तान की तरफ़ से निशान-ए-इम्तेयाज़ से नवाज़ा गया, तो बाल ठाकरे ने उसका विरोध किया था. आज उद्धव ठाकरे शाहरुख खान पर भाजपा के हमले का बचाव कर रहे हैं. यानी देश में अभी आशा जीवित है. ■

जब यूपीए-2 के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था चरमराने लगी, तो बदलाव की मांग शुरू हुई. भाजपा समावेशी विकास के नारे के साथ चुनकर आई, लेकिन वह हमेशा से कांग्रेस की विचारधारा को सूडो-सेकुलरिज्म की विचारधारा कहती आई थी. यह थैचर की तरह इस विचारधारा का खोल तोड़ना चाहती थी. दरअसल, कांग्रेस के 67 वर्षों के शासन के बाद भाजपा ने एक सांस्कृतिक युद्ध शुरू करके देश को चौंका दिया.

feedback@chauthiduniya.com

जीवन का ज्ञान

अध:पुष्पी के पुष्प उल्टे लटके हुए रहते हैं. इसलिए इसको अध:पुष्पी कहते हैं. इसके पौधों पर नीचे से ऊपर तक कड़ी तथा श्वेतवर्णी रोमावलि रहती है. इसलिए इसको रोमालु भी कहते हैं हिमाचल में 1500 मी की ऊंचाई तक तथा भारत के प्राय: सर्वत्र प्रदेशों में सड़कों के किनारे तथा पथरीली या रेतीली भूभागों पर उत्पन्न होता है. इसके पौधे वर्षा-ऋतु में बहुत होते हैं.

अध:पुष्पी

यह वर्षायु शाखा-प्रशाखायुक्त, फैलने वाला रोमयुक्त लगभग 15-45 सेमी ऊंचा शाकीय पौधा होता है. इसके पत्र 3.8-10 सेमी लंबे, 0.6-5 सेमी चौड़े तथा शाखा के आमने-सामने लगे रहते हैं. नीचे के पत्र छोटे डंठल युक्त होते हैं. परन्तु ऊपर के पत्र डंठल रहित नीचे के पत्रों से छोटे तथा शाखाओं से चिपटे हुए रहते है. पत्रों की ऊपरी सतह गहरे नीले वर्ण की तथा निचली सतह फीके नील वर्ण की होती है. पत्तें दोनों ओर से कठिन रोमों से युक्त होते हैं. इसके पुष्प गोलाकार, फीके गुलाबी या आसमानी रंग के नीचे की ओर लटके हुए रहते हैं. ये शाखाओं के अग्र-भाग पर निकलते हैं.

अनेक स्थानों अर्कपुष्पी तथा अन्धाहुली को पर्यायवाची माना गया है. परन्तु वस्तुत: यह दोनों पौधे एकदम भिन्न हैं. अध:पुष्पी के पुष्प उल्टे लटके हुए रहते हैं. इसलिए इसको अध:पुष्पी कहते हैं. इसके पौधों पर नीचे स ऊपर तक कड़ी तथा श्वेतवर्णी रोमावलि रहती है. इसलिए इसको रोमालु भी कहते हैं हिमाचल में 1500 मी की ऊंचाई तक तथा भारत के प्राय: सर्वत्र प्रदेशों में सड़कों के किनारे तथा पथरीली या रेतीली भूभागों पर उत्पन्न होता है. इसके पौधे वर्षा-ऋतु में बहुत होते हैं.

बाह्यस्वरूप

यह वर्षायु शाखा-प्रशाखायुक्त, फैलने वाला रोमयुक्त लगभग 15-45 सेमी ऊंचा शाकीय पौधा होता है. इसके पत्र 3.8-10 सेमी लंबे, 0.6-5 सेमी चौड़े तथा शाखा के आमने-सामने लगे रहते हैं, नीचे के पत्र छोटे डंठल युक्त होते हैं. परन्तु ऊपर के पत्र डंठल रहित नीचे के पत्रों से छोटे तथा शाखाओं से चिपटे हुए रहते है. पत्रों की ऊपरी सतह गहरे नीले वर्ण की तथा निचली सतह फीके नील वर्ण की होती है. पत्तें दोनों ओर से कठिन रोमों से युक्त होते हैं. इसके पुष्प गोलाकार, फीके गुलाबी या आसमानी रंग के नीचे की ओर लटके हुए रहते हैं. ये शाखाओं के अग्र-भाग पर निकलते हैं. इसके फल 15 मिमी लंबे, 4 मिमी व्यास के, 4 धारियों से युक्त, अण्डाकार, श्वेत वर्ण के बाहर से धूसर चमकीले तथा भीतर भूरे वर्ण के होते हैं. इसकी मूल कुछ धसर या काले वर्ण की होती है. इसकी छाल ऊपर से पतली और खुरदरी तथा अंदर से चमकदार श्वेत होती है. यह तीक्ष्य गंधयुक्त, स्वाद में फीकी तथा रूआबदार होती है. इसका पुष्पकाल जुलाई से जनवरी तक होता है.

आयुर्वेदीय गुण-कर्म एवं प्रभाव

1. अध:पुष्पी कटु, तिक्त, उष्ण, लघु तथा कफवातशामक मूढ़गर्भापकर्षिणी, चक्षुष्य तथा व्रणशोथहर होती है.
2. इसके पत्र विषरोधी, मृदुकारी, स्वेदजनन, मलबंधकारी, गर्भस्रावी, गर्भाशय संकोचक, आर्तवजनन, प्रवाहिकारोधी, वातानुलोमक, उष्ण, अश्मरी, आमवात, अर्श, ग्रहणी, शोथ, अतिसार, मूत्रकृच्छ, मूढ़गर्भ, कुष्ठ, त्वरो, नेत्ररोग, कास, कष्टार्तव तथआ ज्वरनाशक होते हैं.
3. अन्धाहुली के पुष्प स्वेदकारी तथा श्वासरोगरोधी होते हैं.
4. इसकी मूल प्रवाहिकारोधी होती है.
5. इसकी मूल का ऐथेनॉल सत्त सार्थक अतिसाररोधी क्रियाशीलता प्रदर्शित करती है.
6. इसका सत्त खरगोश की पृथक्कृत मध्यान्त्र पर उद्वेष्टरोधी तथा लाइपोक्सीजिनेस एन्जाइनिरोधात्मक क्रियाशीलता प्रदर्शित करता है.

औषधीय प्रयोग मात्रा एवं विधि

शिरो रोग:

1. इन्द्रलुप्त- अन्धाहुली की जड़ का क्वाथ बनाकर बालों को धोने से बालों का झड़ना कम हो जाता है.
2. अन्धाहुली की मूल छाल को पीसकर, गोघृत में भूनकर उसमें थोड़ी भुनी हुई हींग मिलाकर प्रात: एक बार गोघृत को साथ सेवन करने से तथा इन्द्रलुप्त वाले स्थान पर लगाने से लाभ होता है.

नेत्र रोग:

1. नेत्राभिष्यंद- अन्धाहुली पञ्चाग को पीसकर नेत्र के बाहर चारों तरफ लगाने से नेत्राभिष्यंद में लाभ होता है.

वृक्ष रोग:

1. श्वास- अन्धाहुली की जड़ को पानी के साथ पीसकर पिलाने से अतिसार में लाभ होता है.

उदर रोग:

1. अतिसार- अन्धाहुली की जड़ को पानी के साथ पीसकर 65 मिग्रा की गोलियां बनाकर सेवन करने श्वास रोग में लाभ होता है.

वृक्कवस्ति रोग:

1. मूत्रकृच्छ्र- अन्धाहुली पञ्चाग को पीसकर पिलाने से मूत्रदाह तथा मूत्रकृच्छ्र में लाभ होता है.
2. प्रमेह- अंधाहुली के पुष्पों में समभाग मिश्री मिलाकर गुलकंद बनाकर 1-2 ग्राम मात्रा में सेवन करने से प्रमेह में लाभ होता है.

प्रजनन संस्थान रोग:

1. मूढ़गर्भनिष्क्रमणार्थ- प्रात: सायं 2-4 मिली अन्धाहुली पन्चाग स्वरस का सेवन कराने से मूढ़गर्भ का निर्हरण हो जाता है.
2. वीर्य-पुष्टि-2 ग्राम अंधाहुली पञ्चाग चूर्ण में समभाग मिश्री मिलाकर गोदुग्ध के साथ पीने से वीर्य की पुष्टि होती है.

अस्थिसंधि रोग:

1. संधिशोथ- अन्धाहुली पञ्चांग को पीसकर लेप करने से संधि शोथ में लाभ होता है.

त्वचा रोग :

1.व्रण- अन्धाहुली मूल को पीसकर व्रण पर लेप करने से व्रण तथा व्रणशोथ का शमन होता है.
2. विद्रधि- अन्धाहुली मूल कल्क का लेप करने से पृष्ठगत विद्रधि का शमन होता है.

बाल रोग:

1. प्रवाहिका -1-2 ग्राम अंधाहुली मूल चूर्ण का सेवन कराने से बच्चों के प्रवाहिका रोग में लाभ होता है.

विष चिकित्सा

सर्पविष- अन्धाहुली मूल को पीसकर सर्पदंश स्थान पर लेप करने से तथा 1-2 ग्राम मूल कल्क का सेवन करने से दंश जन्य वेदना, शोथ, जलन आदि विषाक्त प्रभावों का शमन होता है.

प्रयोज्याग: मूल एवं पञ्चाग
मात्रा: चूर्ण 1-3 ग्राम क्वाथ 10-20 मिली. चिकित्सक परामर्शानुसार

आचार्य बालकृष्ण

सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर करें शिकायत

सूचना का अधिकार — चौथी दुनिया की पहल

अगर आप किसी अधिकारी को या उसके ड्राइवर को या किसी अन्य व्यक्ति को सरकारी वाहनों का दुरुपयोग करते देखते हैं, उस वाहन का कार्यालय से इतर किसी अन्य कार्य में प्रयोग करते देखते हैं, अगर आपको इससे संबंधित किसी सूचना की दरकार हो, तो आप आरटीआई आवेदन के माध्यम से इससे संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं. इस अंक में हम एक आरटीआई आवेदन प्रकाशित कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल आप ऐसे मामलों के लिए कर सकते हैं. चौथी दुनिया आपकी किसी भी समस्या के समाधान अथवा सुझाव देने के लिए हमेशा आपके साथ है. आप हमसे पत्र, ईमेल या फोन के जरिये संपर्क कर सकते हैं.

सेवा में
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन.

महोदय,

कृपया मुझे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी दी जाये:

1. वित्तीय वर्ष .... में श्री............................... द्वारा प्रयोग की गई अथवा उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी वाहनों की लॉग बुक की प्रति उपलब्ध कराएं.

2. नेताओं एवं नौकरशाहों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे सरकारी वाहनों से संबंधित नियमों की प्रति उपलब्ध कराएं. इनके द्वारा वाहनों के निर्धारित सीमा से अधिक उपयोग से होने वाले खर्च की वसूली से संबंधित नियमों की प्रति भी उपलब्ध कराएं.

मैं आवेदन फीस के रूप में 10 रुपये अलग से जमा कर रहा/रही हूं.

या

मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं, इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं. मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं..............है.

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें. साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें.

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

यदि आपने सूचना अधिकार कानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार कानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ई-मेल कर सकते हैं. आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं. हमारा पता है-

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11 नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन-201301
ई-मेल: rti@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
CHAUTHI DUNIYA

चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध, Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

सू की की पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद संविधान के मुताबिक वे खुद राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगीं, क्योंकि सू की के दोनों बच्चे ब्रिटेन में जन्मे हैं और संविधान के मुताबिक वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, जिनके बच्चे विदेशी नागरिक हों. संसद की 25 फीसदी सीटें म्यांमार की सेना के लिए आरक्षित होने की स्थिति में सू की की जीत को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. हालांकि अंतिम नतीजों के आने में अभी कुछ और दिन लगेंगे, जबकि राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया जनवरी के बाद ही शुरू होगी. इसके बाद ही संसद का सत्र फिर से आरंभ होगा. देश के मौजूदा राष्ट्रपति और सेना प्रमुख थीन सीन ने चुनावों से पहले कहा था कि नतीजे जो भी हों, वे स्वीकार करेंगे.

म्यांमार में लोकतंत्र की वापसी

आंग सान सू की यह तय कर पाने की भी हालत में होंगी कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा. हालांकि सब कुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि सू की के लिए पिछले दशक व्यक्तिगत पीड़ा के भी रहे हैं. पिछले 22 सालों में वह 15 साल नजरबंद रही हैं. उनकी पार्टी ने 1990 में पिछला स्वतंत्र चुनाव भी जीता था, लेकिन सेना ने उसे मानने से इंकार कर दिया था.

म्यांमार में लगभग 50 सालों तक सेना का प्रभुत्व रहा है. पहले शासन की बागडोर प्रत्यक्ष तौर पर सेना के हाथों में रही और फिर वर्ष 2011 से एक अर्द्ध-असैन्य सरकार और उसके सहयोगियों ने शासन चलाया, लेकिन पहली बार हुए चुनाव में आंग सान सू की की अगुवाई में विपक्षी दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. सू की भारत को अपना दूसरा घर मानती हैं. एक ऐसा लोकतांत्रिक देश, जो पड़ोसी भी हो और उसकी मुखिया अगर भारत के प्रति अच्छी सोच रखती हों, तो कूटनीतिक संबंधों के प्रगाढ़ होने की संभावना प्रबल हो जाती है. सही मायने में देखा जाए तो नेपाल के साथ तनातनी के वर्तमान हालात में सू की की जीत भारत के लिए बहुत अहम है.

राजीव रंजन

म्यांमार में 25 साल बाद ऐसे संसदीय चुनाव हुए हैं, जिसमें आंग सान सू की की विपक्षी पार्टी एनएलडी ने बहुमत हासिल कर लिया है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सू की को उनकी पार्टी की भारी जीत के लिए बधाई दी है और भारत आने का न्यौता दिया है. सू की के लिए 13 नवंबर का दिन जिंदगी का महत्वपूर्ण दिन साबित हुआ. पांच साल पहले 2010 में 13 नवंबर को ही उन्हें नजरबंदी से रिहा किया गया था. अब 13 नवंबर को औपचारिक नतीजों की घोषणा में प्रचंड बहुमत पाकर उनकी पार्टी न सिर्फ नई सरकार बनाएगी, बल्कि वे यह तय कर पाने की भी हालत में होंगी कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा. हालांकि सबकुछ इतनी आसानी से नहीं हुआ, बल्कि सू की के लिए पिछले दशक व्यक्तिगत पीड़ा के भी रहे हैं. पिछले 22 सालों में वे 15 साल नजरबंद रही हैं. उनकी पार्टी ने 1990 में पिछला स्वतंत्र चुनाव भी जीता था, लेकिन सेना ने उसे मानने से इंकार कर दिया था. यकीनन सू की की जीत उन देशों के लिए सीख है, जहां सैन्य शासन को तवज्जो दी जाती रही है.

अब 8 नवंबर को हुए संसदीय चुनाव के कुछ अहम आंकड़ों पर नजर डालें तो हम देखेंगे कि 664 सीटों वाली दो सदनों की संसद में सू की की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को 364 सीटें मिल चुकी हैं. निचले सदन की 440 सीटों में सू की की पार्टी को 238 सीटें मिल चुकी हैं. 110 सीटें सेना के लिए आरक्षित है. 224 सीटों वाले ऊपरी सदन में एनएलडी को 126 सीटें मिली हैं.

सू की की पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद संविधान के मुताबिक, वे खुद राष्ट्रपति नहीं बन सकेंगीं, क्योंकि सू की के दोनों बच्चे ब्रिटेन में जन्मे हैं और संविधान के मुताबिक वो व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बन सकता, जिनके बच्चे विदेशी नागरिक हों. संसद की 25 फीसदी सीटें म्यांमार की सेना के लिए आरक्षित होने की स्थिति में सू की की जीत को बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. हालांकि इन नतीजों के आने के बाद राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया जनवरी के बाद ही शुरू होगी. इसके बाद ही संसद का सत्र फिर से आरंभ होगा. देश के मौजूदा राष्ट्रपति और सेना प्रमुख थीन सीन ने चुनावों से पहले कहा था कि नतीजे जो भी हों, उन्हें वे स्वीकार करेंगे और नई सरकार के साथ मिल कर काम करेंगे. एनएलडी की जीत पक्की हो जाने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति थीन सीन, सेना प्रमुख मिन ऑन्ह लेंग और संसद प्रमुख श्वे मान से मुलाकात के लिए चिट्ठी लिखी है. सू की के नजदीक समझे जाने वाले श्वे मान को राष्ट्रपति पद के लिए गंभीर उम्मीदवार माना जा रहा है.

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव बान की-मून ने आंग सान सू की को चुनाव में उनकी पार्टी के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी और चेताया कि लोकतंत्र के निर्माण के लिए काफी मेहनत करनी होगी.

आंग सान सू की

आंग सान सू की म्यांमार (बर्मा) में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाली प्रमुख राजनेता हैं. 19 जून, 1945 को रंगून में जन्मीं आंग सान लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई प्रधानमंत्री, प्रमुख विपक्षी नेता और म्यांमार की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की नेता हैं. इनके पिता आंग सान ने आधुनिक बर्मी सेना की स्थापना की थी और युनाईटेड किंगडम से 1947 में बर्मा की स्वतंत्रता पर बातचीत की थी. इसी साल उनके प्रतिद्वंद्वियों ने उनकी हत्या कर दी. सू की की मां डाउ खीन यी भारत में राजदूत थीं. सू की ने दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज, नई दिल्ली से 1964 में राजनीति विज्ञान में स्नातक की और 1987 में कुछ समय शिमला के इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी में फेलो के तौर पर भी बिताया. आंग सान को 1990 में राफ्तो पुरस्कार व विचारों की स्वतंत्रता के लिए सखारोव पुरस्कार से और 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया. 1992 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य के लिए भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया. लोकतंत्र के लिए आंग सान के संघर्ष का प्रतीक बर्मा में पिछले 20 वर्ष में कैद में बिताए गए 14 साल गवाह हैं. बर्मा की सैनिक सरकार ने उन्हें पिछले कई वर्षों से घर पर नजरबंद रखा हुआ था. इन्हें 13 नवम्बर, 2010 को रिहा किया गया है. ■

भारत मेरा दूसरा घर

पिछले साल जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आंग सान सू की की मुलाकात हुई थी तो सू की ने भारत में बिताये अपने समय को याद करते हुए कहा था कि भारत उनका दूसरा घर है. सू की का यह वक्तव्य भले ही साल भर पहले दिया गया था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने म्यांमार में 50 वर्षों के सैन्य शासन को उखाड़ फेंक फिर से लोकतंत्र की वापसी संभव बनाया है, ऐसे में उनका यह वक्तव्य काफी मायने रखता है. सू की की भारत के प्रति यह सोच इसलिए और भी मायने रखती है कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल से फिलहाल रिश्तों में खटास आ गई है. म्यांमार में हाल के दिनों में जिस तरह से भारत ने सैनिक ऑपरेशन को अंजाम दिया था, उसे देखते हुए भी सू की का बयान काफी गौर फरमाने वाला है. भारत के प्रति सू की की सोच का इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय भारत की प्रशंसा करते हुए सू की भावुक हो गयी थीं. उन्होंने मोदी से कहा था कि भारत पहला देश है, जहां वह बर्मा (म्यांमार का पुराना नाम) से गयीं थीं. ■

feedback@chauthiduniya.com

अंतरराष्ट्रीय अपराधी

खूंखार सीरियल किलर था जॉन क्रिस्टी

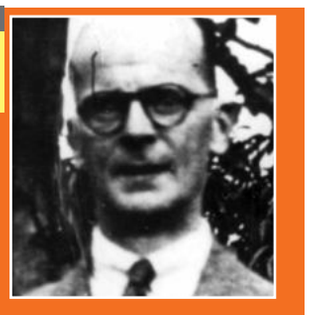

सन् 1898 में इंग्लैंड में जॉन क्रिस्टी का जन्म हुआ. उस वक्त कोई यह अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि यही क्रिस्टी आगे चलकर खूंखार सीरियल किलर बन जाएगा. जॉन रेजिनाल्ड हैलिडे क्रिस्टी का जन्म इंग्लैंड के यॉर्कशायर शहर में हुआ. अनुशासित पिता, बेपनाह प्यार करने वाली मां और बहन की छांव में उसका बचपन गुजरा. उसमें बचपन से ही औरतों के प्रति नफरत और गुस्से को अपने पर हावी होने देने जैसी बुरी आदतें थीं. जॉन क्रिस्टी ने 15 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी और प्रथम विश्व युद्ध में वह संकेत देने वाला अधिकारी के तौर पर काम करने लगा. बचपन से यौन संबंध के प्रति आकर्षण और गुस्से में आपा खो देना उसकी इतनी बुरी आदत बन चुकी थी कि वह 19 साल की उम्र से ही वेश्यावृत्ति करने लगा था. सन् 1992 में जॉन क्रिस्टी ने इथेल सिम्पसन नाम की लड़की से शादी की, लेकिन शादी करने के बावजूद भी जॉन क्रिस्टी ने वेश्यावृत्ति करना नहीं छोड़ा. वक्त बीतता गया और जॉन क्रिस्टी पोस्ट मैन का काम करके अपना जीवन बिताने लगा. लेकिन अचानक पोस्टल आर्डर को चुराने के दोष और उग्र स्वभाव के चलते जॉन क्रिस्टी को 2 साल की जेल हो गई. 29 साल की उम्र तक जेल काटने के बाद जॉन क्रिस्टी अपनी पत्नी के साथ इंग्लैंड को छोड़ कर लंदन चला आया. सतय के साथ जॉन क्रिस्टी की बुरी मानसिकता बड़ा रूप लेने लगी. सन् 1943 में उसके अंदर का दरिंदा बाहर आया, जब उसने 21 साल की रुथ फुयूरेस्ट का यौन शोषण करते वक्त बेरहमी से उसका गला घोट कर उसे मौत की नींद सुला दिया और उसके बाद उसे जला कर कम्यूनल गार्डन में गाड़ दिया. इस घटना के बाद जॉन क्रिस्टी को शक्ति और रोमांच का एहसास हुआ और मजा आने लगा. जॉन क्रिस्टी ने दरिंदगी की सभी हदें तोड़ते हुये 32 साल की म्यूरिएल एडी, 25 साल की रीटा नेल्सन जैसी औरतों का शारीरिक शोषण किया और कभी उनका गला घोट के, तो कभी उन्हें जलाकर दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया. उन सबकी लाशें ठिकाना लगाते हुये घर के पीछे गार्डन में दफना दिया. इसी बीच जॉन क्रिस्टी की पत्नी का दूसरा बच्चा गर्भपात हो गया, जिसकी वजह से गुस्से में आपा खोकर जॉन क्रिस्टी ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. पत्नी की मौत की जब कानूनी जांच हुई, तो जॉन क्रिस्टी के अपराधों की सारी कड़ियां खुलती गईं. सन् 1949 में जॉन क्रिस्टी के गार्डन से उन सब महिलाओं की लाशें मिलीं, जिन्हें पुलिस शहर में काफी वक्त से तलाश रही थी. जॉन क्रिस्टी की बुरी मानसिकता और दरिंदगी जब लोगों के सामने आयी तो पूरा शहर दहल गया. जॉन क्रिस्टी पर हत्याओं के आरोप में कानूनी कारवाई चली और सभी सबूत जॉन क्रिस्टी के खिलाफ होने की वजह से उसे 15जुलाई, 1953 को लंदन की पेन्टोवीले जेल में फांसी की सजा दे दी गई.■

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

संक्षिप्त ख़बरें

मंगल के वायुमंडल की गुत्थी सुलझी

फ्लोरिडा के वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह से विलुप्त वायुमंडल की गुत्थी सुलझाने में अहम कामयाबी मिली है. वैज्ञानिकों ने मंगल के वायुमंडल के बाहर एक सोलर स्टॉर्म के बारे में पता लगाया है, जिससे यह साबित होता है कि धरती की तरह दिखने वाला मंगल ग्रह ठंडे और शुष्क रेगिस्तान में कैसे तबदील हो गया. एक रिसर्च के मुताबिक, धरती की तरह मंगल में मैगनेटिक फील्ड नहीं होने की वजह से मंगल ग्रह सूरज की लपटों से अपने वायुमंडल को महफूज नहीं रख पाया, जिसकी वजह से मंगल ग्रह का वायुमंडल विलुप्त हो गया.

नासा के मंगल अभियान से जुड़े स्पेसक्रॉफ्ट मेवेर ने सोलर स्टॉर्म के बारे में पता लगाया था. इंटर प्लेनेरी कोरोनल मॉस इजेक्सन की वजह से ऑक्सीजन और कार्बनडाईऑक्साइड के बहुत से कण मंगल ग्रह के स्पेस में नज़र आए. मार्च में आया सोलर स्टॉर्म अब तक की सबसे बड़ी खगोलीय घटना है.

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस अध्ययन से ये साफ होगा कि कभी पानी से भरा रहने वाला मंगल कैसे शुष्क रेगिस्तान में तब्दील हो गया. मेवेन अभियान से जुड़े कोलेराडो विश्वविद्यालय के ब्रुस जैकोसी ने बताया कि यह पता लगाया जा रहा है कि मंगल ग्रह पर क्लाइमेट चेंज, स्पेस के खत्म होने की वजह से हुआ था या इसके पीछे कोई और कारण था. ■

कौन खिलाना चाहता था इमरान खान को ज़हर

पाकिस्तान तरकीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चीफ इमरान खान और टीवी जर्नलिस्ट रेहम खान की शादी टूटने के एलान के बाद कई तरह के दावे और अटकलें लगाई जा रही हैं. एक पत्रकार के मुताबिक, इंटेलिजेंस ने पहले ही इमरान को आगाह कर दिया था कि रेहम इमरान को जहर देकर उनकी पार्टी पर कब्जा कर सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक, सितंबर से ही इमरान और रेहम का रिश्ता इतना बिगड़ गया था कि शादी खत्म होने की कगार पर पहुंच चुकी थी. रेहम ने इमरान की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी और शादी खत्म करने का फैसला भी आपसी सहमति से नहीं लिया गया था. दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी. इसके बाद रेहम को एक कॉन्फ्रेंस के बहाने लंदन भेजा गया और तभी इमरान ने उन्हें तलाक का नोटिस ईमेल कर दिया, जो रेहम के लिये किसी शॉक से कम नहीं था. पाकिस्तानी वरिष्ठ पत्रकार आरिफ निजामी ने बताया कि तलाक लेने के दो दिन पहले रेहम ने इमरान को बताया कि वह खुद तरहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की सरपरस्त बनना चाहती हैं. एक अन्य वरिष्ठ पत्रकार शाहिद मसूद ने बताया कि जब इमरान खान हॉस्पिटल में भर्ती थे, तब रेहम ने उन्हें ज़हर वाले लड्डू खिलाने की कोशिश की थी. ■

बच्चे को लगाया गाय का दिल

कहा जाता है कि अगर इरादे बुलंद हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है. ब्रिटेन में एक बच्चे की जान बचाने के लिये उसे गाय का दिल लगाया गया है. डॉक्टरों ने सर्जरी की मदद से गाय के दिल से बच्चे की जान बचाने में सफलता हासिल की है. डॉक्टरों ने बताया है कि अब बच्चे का दिल बेहतर तरीके से काम कर रहा है. नोवा ग्वीलिम प्रिटकार्ड का जन्म 10 फरवरी को हुआ था. वह होलट-ओरम सिंड्रोम नाम की बिमारी से पीड़ित था. इस बिमारी से एक लाख में एक व्यक्ति ही प्रभावित होता है. होल्ट-ओरम की बिमारी में पीड़ित व्यक्ति के लिंब के ऊपरी हिस्से में असामान्य रूप से हड्डी विकसित हो जाती है. जिसकी वजह से दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है. जन्म के बाद ही नोवा का ऑपरेशन किया गया था. डॉक्टरों ने उसका दिल मानव और गाय के अंग के हिस्सों से बदला था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आठ महीने के नोवा का दिल अब बिल्कुल ठीक काम कर रहा है. मालूम हो कि गाय के हार्ट वॉल्व का कभी-कभी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें मौजूद टिश्यू मानव वॉल्व से मिलता-जुलता है.■

रावण ने कई ऐसे गलत काम किए थे, जिनसे किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है. यहां जानिए रावण की गलतियां, इन गलतियों से आज भी सभी को बचना चाहिए.रावण की एक गलती ये थी कि वह कभी भी सही सलाह नहीं मानता था. मंदोदरी, विभीषण, माल्यवंत, कुंभकर्ण, हनुमान आदि ने रावण को सलाह दी थी कि वह श्रीराम से शत्रुता न करें और सीता को पुनः लौटा दें, लेकिन रावण ने ये बात नहीं मानी.

साई वंदना

आध्यात्मिक पथ पर प्रगति

डॉ. चन्द्रभानु सतपथी

सद्गुरु की सहायता कैसे पाएं ?

भक्त को आध्यात्मिक मार्ग में सद्गुरु द्वारा कब सहायता मिलती है ?

सद्गुरु ने जब किसी की मदद की, अकस्मात की. जब वे यह देखते हैं कि व्यक्ति अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपने को अच्छा या निर्मल बनाने का प्रयत्न कर रहा है, पर ऐसा नहीं कर पा रहा है, तो वे उसकी सहायता करते हैं. जैसे श्री उपासनी बाबा–जिनके विषय में श्री साई बाबा ने साफ़–साफ़ कहा था कि आध्यात्मिक तराजू पर यदि सारा संसार एक तरफ है, तो उपासनी बाबा दूसरी तरफ़. जब श्री उपासनी बाबा श्री साई बाबा के पास आए थे, तो बहुत कुछ वे स्वयं करके आये थे. बाबा के पास आने के अनेक वर्ष पूर्व बहुत कम आयु में उन्होंने पूरे एक साल बिना भोजन किए साधना की थी और शरीर एवं मृत्यु के रहस्य को समझने का प्रयत्न किया था. वे एक ऐसी गुफा में, जहां पानी भी उपलब्ध नहीं था, जाकर रहे थे. उन्होंने अपने शरीर को कष्ट दिया. मान–अपमान सहा. घर द्वारा, परिवार सबको छोड़कर चार वर्षों तक खण्डोबा मंदिर में रहे थे. कहने का मतलब यह कि जिसने भी पाया, उसने पहले स्वयं प्रयत्न किया, उसके लिए कष्ट सहा और त्याग किया, तब जाकर वे सद्गुरु की कृपा के पात्र बने.

बाबा ने कहा था पहले मन को छोटे–छोटे बंधनों से तो निकलो. वे जानते थे कि अधिकांश लोग आध्यात्मिक चेतना के निम्न स्तर पर हैं. इसलिए पहले उन्होंने दक्षिणा मांग–मांग कर रुपये–पैसे के मोह से निकलने की बात सिखाई. वे चाहते थे कि लोग पहले इसकी माया से तो निकलें. जब काका साहेब दीक्षित ने सब कुछ छोड़ा, तब जाकर उन्हें सब कुछ मिला.

आंतरिक पूजा

क्या औपचारिक रूप से पूजा–पाठ आदि करना ही आध्यात्मिकता है ?

हां भी और नहीं भी. चेतना के विभिन्न स्तर पर लोग विभिन्न प्रकार की पूजा–परिपाटी करते हैं. एक आदमी सोना, रुपया, फल आदि समस्त वस्तुएं चढ़ाकर किसी देव की पूजा कर सकता है और एक गरीब व्यक्ति तुलसी, अक्षत, फल और दूर्वा के साथ पूजा करता है. श्री कृष्ण ने गीता में यह कहा है कि अगर भाव पूरा हो, चाहे पूजा सरल हो, तो वह ईश्वर द्वारा ग्राह्य है. ईश्वर के प्रति ज़्यादा वस्तुएं अर्पित करने के उपरांत भी भाव न हो तो पूजा पूर्ण नहीं होती. कई लोग तो इस प्रकार पूजा न करके अंतर्मन में पूजा करते हैं. बाबा ने कहा कि आन्तरिक पूजा अर्थात् भाव–पूजा ही श्रेष्ठ है. अन्ततोगत्वा जिसके भाव शुद्ध एवं एकाग्र और चेतना शुद्ध है, तो वह चाहे किसी भी प्रकार की पूजा करे, वह ईश्वर द्वारा ग्राह्य है. यही वास्तव में आध्यात्मिकता का रास्ता है. यदि केवल भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ईश्वर की पूजा की जाती है, तो वह आध्यात्मिकता नहीं है. वह सकाम पूजा है, जब कि–ईश्वर निष्काम पूजा से सतुष्ट होते हैं. जो कुछ भी हमारे प्रारब्ध के कारण जीवन में घटित होता है, क्या हमने उसे स्वीकार किया–चाहे वह दुख अथवा सुख हो?

क्या हम ईश्वर की कृपा पाने के योग्य बन पाये? अपने विषय में न सोचकर क्या दूसरों के हित के लिए कुछ कर पाये? जब तक ऐसा करने की शक्ति अपने में जागृत न कर पाएं, तब तक आध्यात्मिक मार्ग पर चलना संभव नहीं है.

बंधन–मुक्ति

कोई प्राणी जीवात्मा से शिवात्मा कैसे बनता है?

जब कोई प्राणी निस्पृह होकर अर्थात कामना–रहित होकर, संसार में रहकर भी सांसारिक आर्कषणों के प्रति विरक्त रहकर, किसी के लिए कुछ करने पर बदले में बिना कुछ चाहे करुणावश समाज के लिए त्याग करना शुरू करता है तो उसकी आत्मा क्रमशः महात्मा स्वरूप को धारण करने लगती है. फिर वह जीवात्मा के बंधन में नहीं रहता. वह शिवात्मा बनता है, जो कि सर्वव्यापक, शांत और अद्वैत रूप है.

शिवं शांतं अद्वैतम

लेकिन यह एकाएक नहीं होता. कठोर साधना के बाद ही ऐसा भाव उत्पन्न होता है.

अध्यात्म मार्ग : दुख से निवृत्ति

बहुत–सी पुस्तकों में ऐसा कहा गया है कि जो अध्यातम–मार्ग पर चलेगा, वह बहुत कठिनाई पाएगा. क्या यह बात सही है?

आध्यात्मिक जगत में जो जाएगा, उसे भौतिक दुनिया की विचारधारा और प्रणाली से अलग होना पड़ेगा, जो कि समाज में रहते हुए आसान नहीं है. जैसे कि लोभी व्यक्ति से यदि यह कहा जाए कि वह अपनी कमाई का पच्चीस प्रतिशत ईश्वर या गरीबों के लिए दान करे, तो वह अनुभव करेगा कि उस पर अत्यंत संकट का पहाड़ टूट पड़ा है, लेकिन अगर उसका विश्वास पक्का है, तो ऐसा कर भी देगा आगे चलकर त्याग करते समय उसे कष्ट नहीं होगा. जो यह कहा जाता है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का अन्य अर्थ दुख यात्रा को झेलना है, तो यह बात सम्पूर्ण रूप से निराधार है. जो व्यक्ति विचार या मोह आदि बंधन में बंधा हुआ है, वस्तुतः उसी को ही कष्ट होता है. सत्य तो यह है कि व्यक्ति धीरे–धीरे जैसे–जैसे आगे बढ़ता जाएगा, तो उसके दुख का अनुभव भी क्रमशः खत्म होता जाएगा. इस मार्ग पर तो वह बंधन ही हट जाता है और व्यक्ति हल्का हो जाता है, फिर दुख को अनुभव करने का प्रश्न ही नहीं उठता. ■

feedback@chauthiduniya.com

भक्तों का तीर्थ गिरिजा देवी मंदिर

तरुण फोर

गिरिजा देवी मंदिर उत्तराखंड के सुंदरखाल गांव में स्थित है, जो माता पार्वती के प्रमुख मंदिरों में से एक है. यह मंदिर श्रद्धा एवं विश्वास का अद्भुत उदाहरण है. उत्तराखंड का यह प्रसिद्ध मंदिर रामनगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. मंदिर छोटी पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है. देवी के प्रसिद्ध मंदिरों में गिरिजा देवी का स्थान अद्वितीय है. गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण ही उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है. मान्यता है कि जिन मंदिरों में देवी वैष्णवी के रूप में स्थित होती हैं, उनकी पूजा पुष्प प्रसाद से की जाती है और जहां शिव शक्ति के रूप में होती हैं, वहां बलिदान का प्रावधान है.

मंदिर में मां गिरिजा देवी सतोगुणी रूप में विद्यमान हैं, जो सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती हैं. यहां पर जटा नारियल, लाल वस्त्र ,सिन्दूर, धूप, दीप आदि चढ़ा कर मां की वन्दना की जाती है. मनोकामना पूर्ण होने पर श्रद्धालु घंटी या छत्र आदि चढ़ाते हैं. नवविवाहित स्त्रियां यहां पर आकर अटल सुहाग की कामना करती हैं. निःसंतान दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिये माता के चरणों में झोली फैलाते हैं. वर्तमान में इस मंदिर में गिरिजा माता की 4.5 फिट ऊंची मूर्ति स्थापित हैं. इसके साथ ही माता सरस्वती, गणेश तथा बटुक भैरव की संगमरमर की मूर्तियां भी मुख्य मूर्ति के साथ स्थापित हैं. इसी परिसर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थापित है. इस मंदिर में स्थापित मूर्ति यहीं पर हुई खुदाई के दौरान मिली थी.

कार्तिक पूर्णिमा को गंगा में स्नान के पावन पर्व पर माता गिरिजा देवी के दर्शनों एवं पतित पावनी कौशिकी (कोसी) नदी में स्नानार्थ भक्तों की भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है. इसके अतिरिक्त गंगा दशहरा, नव दुर्गा, शिवरात्रि, उत्तरायणी, बसंत पंचमी में भी काफ़ी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं. पूजा के विधान के अन्तर्गत माता गिरिजा की पूजा करने के उपरांत बाबा भैरव (जो माता के मूल में स्थित है) को चावल और मास (उड़द) की दाल चढ़ाकर पूजा–अर्चना करना आवश्यक माना जाता है. कहा जाता है कि भैरव की पूजा के बाद ही मां गिरिजा की पूजा का सम्पूर्ण फल प्राप्त होता है. ■

धर्म

रावण : अधर्म और बुराइयों का प्रतीक

रावण को अधर्म और बुराइयों का प्रतीक माना जाता है. रावण जन्म से ब्राह्मण था और वह सभी शास्त्रों का जानकार था. ज्योतिष और पूजा–पाठ के सभी नियमों की भी जानकारी उसे थी. इन अच्छी बातों के अलावा रावण में बुराइयां काफी अधिक थीं. बुराइयों के कारण ही उसकी सभी अच्छाइयों का महत्व खत्म हो गया. रावण ने कई ऐसे गलत काम किए थे, जिनसे किसी भी व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो सकता है. इन गलतियों से आज भी सभी को बचना चाहिए. रावण की पहली गलती थी सही सलाह न मानना. रावण की एक गलती ये थी कि वह कभी भी सही सलाह नहीं मानता था. मंदोदरी, विभीषण, माल्यवंत, कुंभकर्ण, हनुमान आदि ने रावण को सलाह दी थी कि वह श्रीराम से शत्रुता न करें और सीता को पुनः लौटा दे, लेकिन रावण ने ये बात नहीं मानी. इस गलती के कारण रावण का अंत हुआ. दूसरी गलती थी स्त्री का सम्मान नहीं करना. रावण स्त्रियों का सम्मान नहीं करता था. वह इसे पसंद नहीं करता था. इसी कारण रावण ने अपने भाई विभीषण, नाना माल्यवंत, मंत्री शुक को अपने से दूर कर दिया था. रावण हमेशा ही चापलूसों से घिरा रहता था. जो लोग चापलूसों से घिरे रहते हैं और सच बोलने वालों को नापसंद करते हैं, वे कई बार परेशानियों का सामना करते हैं. हमें चापलूसों से बचना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

साई भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साई से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साई से आप कब और कैसे जुड़े. साई की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साई को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साई भक्त. साई बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है? साई बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@ chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

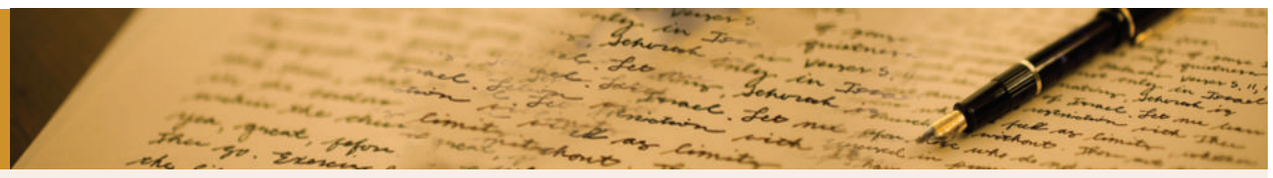

बिहार में नीतीश की सरकार

कवर स्टोरी नीतीश का पलड़ा भारी मैंने पढ़ा. संतोष भारतीय द्वारा लिखी गई यह स्टोरी पूरी तरह से सही साबित हुई. स्टोरी में संपादक महोदय ने कहा था कि बिहार में एक तरफ़ भाजपा है, जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और दूसरी तरफ़ महा–गठबंधन है, जिसके नेता नीतीश कुमार एवं लालू यादव हैं. उस स्टोरी में आपने बताया था कि लालू यादव ने लगभग हर जगह स्पष्ट किया है कि उनकी तरफ़ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं. लेकिन आपने उस स्टोरी में यह भी बताया था कि भाजपा ने मुख्यमंत्री उम्मीदवार का नाम अभी स्पष्ट नहीं किया और भाजपा प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है. चौथी दुनिया की इस स्टोरी में किया गया आपका आंकलन शत–प्रतिशत सही हुआ है.

–सुभाष यादव, पटना, बिहार.

दलित परिवार के बच्चों की हत्या

भारत की सबसे प्रासंगिक किताब संविधान है. कमल मोरारका जी ने बिल्कुल सही कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव, दलित परिवार के बच्चों की हत्या, नाबालिग बच्चियों से बलात्कार, महंगाई और गोमांस खाना चाहिए या नहीं, ये सारे मुद्दे पिछले दिनों अख़बारों की सुर्खियों में छाए हुए थे. मैं ने उनका लेख पड़ा और देखा की किसी तरह से देश के मुद्दों को उन्होंन बड़ी खूबी से विस्तार से समझाया महंगाई पर उन्होंने कहा कि कैसे हेमा मालिनी एवं भाजपा की अन्य महिला नेताओं ने आटा, सब्जी, दल की महंगी क़ीमतों के मसले पर विरोध किया था. आज जिस तरह से इन वस्तुओं की क़ीमतें बढ़ी हैं, वह भाजपा के लिए शर्म की वजह है. मांस–बीफ खाना किसी के लिए भी व्यक्तिगत मुद्दा है, आप इसे सार्वजनिक मुद्दा नहीं बना सकते. संघ को अड़े हाथों लेते हुये कमल मोरारका जी ने बिलकुल सही कहा कि आरएसएस केंद्र सरकार को लड़खड़ाने की कोशिश कर रहा है और केंद्र सरकार दिल्ली की राज्य सरकार को लड़खड़ाने की कोशिश कर रही है. यह सब बंद होना चाहिए.

–अनिल शर्मा, करोल बाग, नई दिल्ली.

मंत्रालय का दावा कितना सच्चा

मैं चौथी दुनिया अखबार हर हफ्ते पढ़ता हूं. इस बार के अखबार में मैं ने पढ़ा की मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दावा है कि उसने देश भर के सरकारी स्कूलों में शौचालय निर्माण का अपना लक्ष्य दो अक्टूबर, 2015 तक हासिल कर लिया है. मंत्रालय के मुताबिक, सौ फ़ीसद लक्ष्य हासिल कर लिया गया है. इस दावे की जांच की, तो इसकी कलई खुलती नज़र आई. कई स्कूलों में तो शौचालय नहीं हैं, जहां बने हैं उनमें से अधिकांश में दरवाजे नहीं हैं, चौथी दुनिया अख्बार के माध्यम से पता चला की किस तरह देश में शौचालय को लेकर बुरा हाल है. चौथी दुनिया ने इन आंकड़ो को सामने लाकर रखा. उससे यह साफ हो जाता है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का दावा कितना सच्चा है.

–प्रमोद रावत, उत्तराखंड.

गंगा की सफाई

मैं चौथी दुनिया अखबार हर हफ्ते का पाठक हूं. इस बार के अखबार में मैं ने पढ़ा की (एनजीटी)ने गंगा की सफाई पर एनजीटी ने सरकार से पूछा कि वह गंगा नदी के 2500 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में कोई एक जगह बताये जहां गंगा साफ़ है. मैं आप की इस खबर से काफी आकर्षित हुआ और 5000 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि खर्च करने के बाद भी गंगा की हालत बद से बदतर होती जा रही है. गंगा सफाई को लेकर बड़ी बड़ी बातें तो होती है लेकिन कोई भी रास्ता नहीं निकलता. गंगा न केवल एक नदी का नाम है बल्कि एक संस्कृति और तहजीब का भी नाम है. इस नदी से करोड़ों लोगों के जीवन और मृत्यु, आशा और निराशा, ख़ुशी और गम का सिलसिला जुड़ा हुआ है. हज़ारों साल से जीवनदायिनी साबित होती आ रही गंगा का पानी अब पीने योग्य तो दूर, नहाने और सिंचाई के योग्य भी नहीं बचा है. गंगा दिन पर दिन मैली हो रही है लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती.

–कपिल कुमार, कानपुर, उत्तर प्रदेश.

कादर खान एक महान अभिनेता

मैं चौथी दुनिया हर बार पढ़ता हूं. हर बार कुछ नया और दिलचस्प लेख पढ़ने को मिलता है. क्योंकि संतोष भारतीय द्वारा लिखा गया संपदाकीय हमेशा से काफी अच्छा होता है. मैं सबसे पहली खबर ही अखबार में संतोष भारतीय की पड़ता हूं. जिसमें तोप मुकाबिल मेरा पंसदीदा है. पिछले हफ्ते मैं ने कादर खान के बारे में पढ़ा कि किस तरह कादर खान एक महान अभिनेता है. उनके बारे में लोग भूल ही गए थे. उन्होंने चार सौ से ज़्यादा फिल्मों की पटकथा लिखी, संवाद लिखे और उन्होंने छह सौ से ज़्यादा फिल्मों में काम किया. कादर ख़ान ने अमिताभ बच्चन, गोविंदा एवं जॉनी लीवर को कॉमेडी के टिप्स दिए. चढ़ते सूरज को सब सलाम करते है. मैं ने लेख में पढ़ा की क़ादर ख़ान साहब कई वर्षों से बीमार हैं. उनके दिमाग़ में घुस गया कि अब उनका रोल इस दुनिया में ख़त्म हो गया है. लेकिन पतंजलि योगपीठ में आने, रहने और इलाज कराने आमंत्रण दिया यह बाबा राम देव द्वारा बड़ी पहल की गई है.

–मोहित, दरभंगा, बिहार

साहित्यिक असहिष्णुता पर हो विचार

अनंत विजय

पिछले दिनों जिस तरह से देश में बढ़ती असहिष्णुता को लेकर लेखकों ने विरोध जताया, पुरस्कार वापसी आदि हुआ उसके बाद दिल्ली में पहले सोनिया गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया फिर अभिनेता अनुपम खेर ने मार्च ऑफ इंडिया किया. उसमें भी तमाम कलाकार, गायक, लेखक, वैज्ञानिक आदि जुड़े. असहिष्णुता की आड़ में जिस तरह से राजनीति की गई उसको देखते हुए राष्ट्रकवि दिनकर द्वारा उन्नीस अक्तूबर उन्नीस सौ पैंतालिस में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के तैंतीसवें अधिवेशन में दिया गया भाषण याद आ रहा है. तब दिनकर ने कहा था –साहित्य राजनीति का अनुचर नहीं, वरन उससे भिन्न एक स्वतंत्र देवता है और उसे पूरा अधिकार है कि वो जीवन के विशाल क्षेत्र में से वह अपने काम के योग्य वे सभी द्रव्य उठा ले जिन्हें राजनीति अपने काम में लाती है. अगर कार्ल मार्क्स और गांधी जी को यह अधिकार प्राप्त है कि जीवन के अवस्था–विशेष की अनुभूति से वे राजनीति के सिद्धांत निकाल लें तो एक कवि को यह अधिकार सुलभ होना चाहिए कि वह ठीक उसी अवस्था की कलात्मक अनुभूति से ज्वलंत काव्य की सृष्टि करे. अगर राजनीति अपनी शक्ति से सत्य की प्रतिभा गढ़कर तैयार कर सकती है तो साहित्य में भी इतनी सामर्थ्य है कि वह उसके मुख में जीभ धर दे. दिनकर ने आज से सत्तर साल पहले जो कहा था वो आज भी मौजूं है. आज जिस तरह से असहिष्णुता को मुद्दा बनाकर लेखक अपने राजनीतिक आकाओं के हाथ के मोहरे बन रहे हैं उससे बेहतर होता कि वो अपनी लेखनी से सत्य की प्रतिभा गढ़ते और विरोध के मुंह में जीभ धर देते. दिनकर ने अपने उसी भाषण में यह भी कहा था साहित्य जहां तक अपनी मर्यादा के भीतर रहकर जीवन के विशाल क्षेत्र में अपना स्वर ऊंचा करता है वहां तक वह पूज्य और चिरायु है किंतु जभी वह राजनीति की अनुचरता स्वीकार करके उसका प्रचार करने लगेगा तभी उसकी दीप्ति छिन्न जाएगी और वह कला के उच्च पद से पतित हो जाएगा. दशकों तक प्रगतिशीलता के नाम पर साहित्यकारों ने राजनीति की अनुचरता स्वीकार करते हुए उसका प्रचार किया. नतीजा सबके सामने है.

यह तो एक पहलू है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसपर भी साहित्य जगत को गंभीरता से विचार करना चाहिए. हिंदी के लेखक रूप सिंह चंदेल ने फेसबुक पर एक टिप्पणी लिखी–पिछले कुछ समय से व्यस्ततावश में अपने ब्लॉग वातायन को अपेक्षित समय नहीं दे पा रहा था अत: मैंने व्हाट्सएप पर इसी नाम से एक समूह बनाया और हिंदी के गणमान्य साहित्यकारों को इसमें जोडा. किन्हीं कारणों से बहुत भारी मन के साथ मुझे इस फलते फूलते समूह को बंद करना पड़ा. इस टिप्पणी के बाद

चंदेल ने किसी साथी को दुख पहुंचने पर क्षमा आदि जैसी औपचारिकता निभाई. सतह पर देखें तो यह लगता है कि ये तो सामान्य बात है और इसका उल्लेख गैरजरूरी है लेकिन अगर रूप सिंह चंदेल की बातों पर ध्यान दें और उसके शब्दों को ठहरकर देखें तो एक बड़ी तस्वीर नजर आती है. वह तस्वीर है हिंदी के लेखकों और साहित्यकारों के बीच बढ़ रही असहिष्णुता की. अपनी आलोचना नहीं सुन पाने की प्रवृत्ति के लगातार ह्रास होने की. चंदेल ने अपनी टिप्पणी में लिखा है कि उन्होंने साहित्यक समूह में गणमान्य साहित्यकारों को इससे जोड़ा और फिर भारी मन से बंद करना पड़ा. इस टिप्पणी में इन्हीं दो शब्दों पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए. गणमान्य साहित्यकार और भारी मन. इन दो शब्दों की विवेचना करने से हिंदी के लेखकों के बीच बढ़ी असहिष्णुता सामने आती है जिसके नतीजे में चंदेल जैसे लेखक भारी मन से साहित्यिक समूह बंद करने के फैसले पर विवश होते हैं.

पुरस्कार वापसी और उसके विरोध के शोरगुल में साहित्य में बढ़ती असहिष्णुता का मुद्दा लगभग दब सा गया है. समाज में बढ़ती असहिष्णुता, अगर सचमुच यह बढ़ रही है तो, पर छाती कूटनेवाले लेखकों को साहित्य में बढ़ती असहिष्णुता नजर नहीं आती, बल्कि यह कहना ज्यादा उचित होगा कि जो लोग समाज में बढ़ती असहिष्णुता के खिलाफ झंडा बुलंद कर रहे हैं उनमें से ज्यादातर साहित्यिक असहिष्णुता के ध्वजवाहक हैं. समकालीन हिंदी साहित्यिक परिदृश्य पर अगर विचार करें तो इस बात पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि वो कौन सी वजह थी कि हिंदी की वरिष्ठ आलोचक निर्मला जैन को यह लिखना पड़ा था कि आलोचना लिखने में हिचक होती है कि कौन कब नाराज हो जाए. यह सही है कि आलोचकों को किसी के नाराज होने या खफा होने से डरना नहीं चाहिए लेकिन यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अस्सी साल की आलोचक को यह कहने पर क्योंकर मजबूर होना पड़ा. दरअसल हिंदी में कवियों से लेकर कथाकारों तक में अपनी आलोचना सुनने सहने की क्षमता का उत्तरोत्तर ह्रास हो रहा है. यह इसी बढ़ती प्रवृत्ति का नतीजा है कि चंदेल जैसे लेखकों को व्हाट्सएप पर चलनेवाले साहित्यक समूह को बंद करना पड़ा है और अपनी पीड़ा का इजहार फेसबुक पर करना पड़ा है. फेसबुक पर इस बढ़ती असहिष्णुता के तमाम चिन्ह आपको दिखाई पड़ सकते हैं. व्हाट्स ऐप पर चलनेवाले ज्यादातर साहित्य समूह उसको बनानेवालों की प्रशंसा करने का मंच है. जहां इससे विचल होता है वहीं समूह अल्पायु का हो जाता है या फिर उसके सदस्य एक–एक कर अलग होने लगते हैं और फिर जो बच जाते हैं वो जुलूस की शक्ल में एक दूसरे के लिए नारेबाजी करते नजर आते हैं. व्हाट्सएप पर चलने वाले समूहों में आलोचनात्मक टिप्पणी के लिए कोई जगह नहीं है. अगर किसी ने कर दी तो उसकी खैर नहीं. वहां तो बस एक दूसरे की प्रशंसा करने की होड़ लगी रहती है. जिनको कविता की समझ नहीं वो खुद को रामविलास शर्मा और जिनको गजल की समझ नहीं वो अपने को दुष्यंत कुमार मानकर बैठे रहते हैं. अब अगर कोई यह मानकर बैठ जाए कि वो रामविलास शर्मा या दुष्यंत कुमार है तो फिर वो अपनी रचनाओं की आलोचना कैसे बर्दाश्त कर सकता है. उनके समर्थक आलोचना करनेवालों पर संगठित होकर हमले करने लगते हैं और अपमानित करने की हद तक टिप्पणी आपको समूह छोड़ने को विवश कर देती है जो हिंदी साहित्य समाज के असहिष्णु होने का संकेत है. इस असहिष्णु प्रवृत्ति का विकास युवा लेखकों में ज्यादा हुआ है. दो चार कविताएं लिखकर अपने को निराला मानने वाले युवा कवियों को ना तो मर्यादा का ख्याल होता है और ना ही वरिष्ठता का. बीच संवाद में कूदकर उसको खराब कर देना उनका उद्देश्य होता है. दरअसल फेसबुक ने अपनी आलोचना ना सहने की प्रवृत्ति को खूब हवा दी है. तुकबंदी कर खुद को कवि मानने वालों पर अखबारों आदि में प्रायोजित टिप्पणी छप जाती है तो वो बेलगाम हो जाते हैं. मर्यादा भूलते हुए संवाद के बीच में कूदते हैं और बगैर जाने बूझे बस शुरू हो जाते हैं. हमारे वरिष्ठ लेखकों ने कभी युवा लेखकों के बीच बढ़ती इस प्रवृत्ति पर कुछ नहीं कहा. कहें भी तो कैसे उनके सामने देश के बड़े सवाल हैं जिनसे वो टकरा रहे हैं. उनको याद रखना चाहिए कि ये असहिष्णु युवा लेखक ही आनेवाले दिनों में साहित्य को अपने कंधे पर उठाएंगे तब क्या स्थिति होगी. देश का सामाजिक ताना–बाना तो इतना मजबूत है कि उसको तोड़ने में सदियां लग सकती हैं लेकिन साहित्य की डोर बहुत कमजोर है उसको टूटते वक्त नहीं लगेगा.

एक जमाने में बिहार से निकलनेवाली एक साहित्यिक पत्रिका में खराब किताबों की सूची प्रकाशित की जाती थी और उसके कवर पर लिखा होता था कि इन किताबों को न पढ़ें, ये स्तरहीन किताबें हैं. क्या आज के साहित्यिक माहौल में इस तरह की हिम्मत की जा सकती है? क्या कोई आलोचक या समीक्षक इतने बेबाक ढंग से कृतियों पर टिप्पणी कर सकता है? इन दिनों तो हालत ये है कि किसी उपन्यास या कविता या कहानी पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है. यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर भी कह रहा हूं. करीब चार पांच साल पहले जब निर्मला जैन की उक्त टिप्पणी छपी थी तो मैंने उसपर प्रति टिप्पणी करते हुए एक लेख लिखा था कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात करना छोड़ देना होगा. तब लगता था कि निर्मला जैन ने ठीक वही कहा है लेकिन अब लगता है कि उन्होंने दशकों के अपने समीक्षाकर्म के अनुभव के आधार पर अपनी बात कही थी. अब तो हालत ये है कि किसी कृति की आलोचना आपको रचनाकार से दूर कर सकती है. दरअसल रचनाकार रचना की आलोचना को अपनी व्यक्तिगत आलोचना मानने लगा है. जैसे ही ये बात उसके दिमाग में घर करती है तो फिर वो समीक्षक को व्यक्तिगत दुश्मन के तौर पर देखने लगता है उसको निबटाने की रणनीति पर काम शुरू हो जाता है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

कहानी

बेग़म एक हुकुम की उर्फ़ ब्लैक क्वीन

अनय शर्मा

ताश के पत्ते की गड्डी की तरह जिंदगी ने उसे फेंट कर जोकर सा बाहर फेंक दिया था.

ये लड़का जो किसी भी खेल में किंग मेकर की भूमिका निभा सकता था, जिंदगी के इस अजब खेल में जोकर बना मैदान के बाहर पड़ा था.

इस खेल का नाम प्यार था,और वो इस खेल में बुरी तरह हार चुका था.

उसने तो अब तक यही सुना था कि प्रेम में प्रतिद्वंदिता नहीं होती, पर सामने वाला पक्ष उसे प्रतिद्वंद्वी मान सबक सिखाने को उतारू था. कब मौका लगे और उसे पटखनी दी जा सके.

कैक्टस के झुर्रियां नहीं पड़ती कभी, किसी भी प्रजाति के नहीं. बस उम्र के निशान छोटी–छोटी कीलों की शक्ल में निकल आते हैं कैक्टस के चेहरे पर ... और ग्वारपाठे की चिकनाई सारा खुरदरापन सोख लेती है. काश कोई ऐसा इलाज होता जो समाज में उपजे खुरदरेपन को मिटा पता. कभी पेड़ों को तो देखा नहीं यूं लड़ते की तू फलां पेड़ है की तू फलां... ये बुरी लत इंसानों में ही क्यों पायी जाती है? गोल सड़क से उतरते हुए अजीत ने सोचा. पुरानी कमीज़ से जितना पानी टपक चुका था, उससे कहीं ज्यादा पानी उसकी आंख में था. तेज बारिश के बाद जमीन और भी भभक रही थी. मानों जैसे सूखे पत्तों को अभी और पतझड़ झेलना हो. उसे लगा अगर वो वहां और रुका तो पागल हो जायेगा. भाड़ में गयी उर्मिला उसने बुदबुदाते हुए कहा. वो पलटा और सड़क पर बेतहाशा भागने लगा.

उर्मिला दूसरी जात की थी और यही चीज़ अब उन दोनों के भविष्य में फांस सी थी.

वो जब घर में घुसा तो पेट्रोमेक्स के हल्के पीले उजाले में घर की बारिश में भीगी दीवारें अजीब सा भय पैदा कर रहीं थीं. ये उसके शहर की खासियत थी की जरा बूंदाबांदी हुई नहीं की बत्ती गुल. उसने टिमटिमाते हुए उजाले में गौर से देखा. बरामदे के एक कोने में खटोले पर पड़ी अम्मा सो रहीं थीं. अपनी दादी उसे हमेशा डाकखाने की इमारत सी लगती थीं. दोनों ही अपनी जर्जर अवस्था में कभी भी भरभरा कर गिरने के अंदेशे से ग्रसित थीं.

लम्बे बरामदे को पार कर जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो मां पहले से ही वहां उसका इंतज़ार कर रही थी.

चल खाना खा ले, बत्ती का तो कोई भरोसा नहीं.

पापा कहां है?

कारखाने, अभी कहां से आ जायेंगे.

तो छोटे वाले कमरे में कौन है?

मैनपुरी वाली जीजी, कल चले जाना उन्हें छोड़ने और कुछ दिन वहीं रुक जाना. मां ने थाली पकडाते हुए कहा. क्यों?

यहां माहौल ठीक नहीं है तुम्हारे लिए. कुछ दिन रह आओ, मामला ठंडा पड़े तो लौट आना. और फिर जीजी अकेली हैं तुम रहोगे तो कुछ दिन घर में जवान आदमी का सहारा रहेगा उन्हें. घर–बाहर के काम तो निबटा सकते हो उनके कम से कम, हमारे तो किसी काम आये नहीं तुम.

बिजली चमकी आंगन में खड़ा हरसिंगार घड़ी भर को दिखा और फिर अंधेरे में गुम हो गया.

मां जूठे बर्तन समेट कर चली गयी थी, और अब वो अकेला था अपने कमरे में. इन दिनों ये अकेलापन उसे बहुत भाता था. उसने अंधेरे में टटोल कर अपना रेडियो उठाया. विविध भारती के स्टेशन पर लता की मीठी अवाज में गाया गाना आ रहा था.

मिले तो फिर झुके नहीं नज़र वही प्यार की

पर इसी प्यार की नज़र के चक्कर में उर्मिला के घर वालों ने उसे पिछले हफ्ते कितना पीटा था. सेंट्रल टॉकीज़ के चौराहे पर लोग मजमा सा लगाये उसकी पिटाई देख रहे थे. कितनी शर्म आ रही थी उसे. अपने पिटने पर नहीं, पिटना तो प्यार में लाजिमी है. बल्कि अपनी छोटी जात का दु:ख था उसे. वो जात ही क्या जो प्यार में बाधा बने, उसने सोचा. उसने करवट ली तो मुंह से एक टीस निकल गयी.

यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो...

आज कल ऐसे दार्शनिक ख्याल बहुत आने लगे थे उसे, जो उसे खुद में एक हीरो पैदा करने के लिए झंझोड़ते थे.

वो पहले ऐसा नहीं था, आम लड़कों की तरह मस्तमौला था, पर पिछले दो सालों से जब से उर्मिला से मिला था तब से ऐसा दार्शनिक सा हो गया था.यूं भी प्रेम में पड़ा हर लड़का दार्शनिक ही होता है, अपना खुद का एक दर्शन शास्त्र लिए, एक अनोखी आइडियोलॉजी लिए.

उर्मिला शहर के उस स्कूल में पढ़ती थी जिसके विद्यार्थी पीले–नीले रंग की यूनिफॉर्म पहन कर जाया करते थे. जो शहर की धारणा में सबसे महंगा था, और इंग्लिश मध्यम स्कूल या कान्वेंट कहलाता था. जो सिर्फ अमीर बच्चों के पढ़ने के लिए बना था. और वो छोटे लाल इंटर कॉलेज में पढ़ता था.

साथ वाले कमरे में किरायेदार का कोई बच्चा कुनमुनाया तो उसकी मां ने थपकियां देकर उसे फिर से सुला दिया. माओं की आधी जिंदगी अपने बच्चों को थपकाने में ही गुज़र जाती है उसने सोचा.

रात की चुप्पी को तोड़ती बूंदाबांदी फिर शुरू हो गयी थी. जब आधी रात गए बत्ती आई तो अम्मा ने अपने कांपते स्वर में आवाज़ लगाई ... नैक मेरा पंखा चला जा रामसरन की बहू. मां नहीं आई तो उसने बाहर आकर पंखा चलाया. पूरा घर उसने देखा गहरी नींद में डूबा पड़ा था. वो अपने कमरे में लौटा और दिन भर की थकान से चूर तख्त पर लेटते ही सो गया.

जुगनू या पटबीजने बरसात के गहरे अंधेरों में बहुत चमकते हैं. बीजना (हाथपंखा) हिलाती हवा इन्हें चौखाने या चारखाने में बंटी रात में इधर–उधर फ़ेंक देती है. ये गिरते हैं, भीगते हैं, फिर उठ कर जगमगाने लगते हैं. तांबे के रंग सा दिल जब उदासी के गहरे खून में डूबता है तो फिर न संभल पाता है, न धड़क पाता है, न

जगमगाता है. दिल की नसें हमेशा की तरह खून की आवाजाही बनाये रखती हैं. कोई एक बड़ी नस चोरी से एक जुगनू छुपा कर रख लेता है, मौका–बेमौका जब कभी ये जगमगा जाता है तो लोगों को लगता है की दिल के मरीज की धड़कनें लौट आयीं हैं. जुगनूओं को बारहों महीने जगमगाना चाहिए, उसने ढलते हुए सूरज को देखते हुए सोचा.

उसे मैनपुरी आये तीन महीने हो गए थे. और वो बुरी तरह ऊब गया था. अब यहां उसका मन नहीं लगता था. घर की याद आती थी. घर जो उसके लिए जवानी के मंडराते खतरे लिए बैठा था. उर्मिला की याद आ रही थी उसे और बड़ी ज़ोरों की आ रही थी. उसने सोच लिया था कि अब वो वापस चला जायेगा चाहे जो हो. अब यहां और रुकना पागलपन होगा.

मैं कल वापस चला जाऊं बुआ?

क्यों?

बस मन नहीं लग रहा, बहुत दिन हो गए हैं.

उस लौंडिया की याद आ रही होगी तुम्हें. भैया जी ने भेजा है तुम्हें हमारे साथ. जो वो वापस बुलायेंगे तो हम भेज देंगे. यादवों की लौंडिया है वो और हम कुम्हार मार–मूर के कहीं फ़ेंक देंगे तो माँ–बाप का बुढ़ापा मिट्टी में मिल जायेगा. पढ़ो–लिखो कुछ बनो तो मां–बाप को आस बंधे. दो साल से इंटर में फेल हो रहे हो, महतारी ने मोटर साइकिल और दिला दी ऊपर से ये चक्कर. कोई और कसर रह गयी हो तो वो भी कर लो. सब महतारी की शह है तुम्हें. सही कहतीं हैं अम्मा कि रामसरन की बहू के ऐसे लच्छन है की तन पै नहीं लत्ते,बीबी खाएं पान के पत्ते.

वो कुछ नहीं बोल, चुपचाप उठा और कमरे में चला गया. अकेले कमरे में एक बार को उसकी रुलाई छूट गयी फिर अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया. उर्मिला को भूलने की एक झूठी कसम खाई और जाकर सो गया. रात के अंधेरे और सन्नाटे को सिर्फ़ सड़कों पर दौड़ने वाले ट्रकों की हेड लाइट्स की रौशनी और हॉर्न्स की आवाजें चीर रही थी. कभी–कभी रात की चुप्पी में कोई नागिन धुन लहराती और फिर खो जाती थी.

सुबह जब वो तैयार हो सामान ले कर बुआ के सामने खड़ा हुआ तो उन्होंने कुछ न कहा. मन ही मन सोचा इतना समझाने पर भी नहीं समझा तो अच्छा है चला ही जाये. वैसे भी सास–ससुर वाला भरा पूरा परिवार था. पति कई बार नाराजगी दबे लहजे में जिंता भी चुके थे. जब वो पैर छू कर उठा तो बुआ ने उसे सौ–सौ के दो नोट पकड़ा दिये.

****

पता है वड़ेजा मिस कहतीं हैं की मेरी आँखों का रंग उन्हें हजेल नट जैसा लगता है. कितना फैसीनेटिंग है ना हजेल कलर की आंखें होना, उर्मिला ने कहा. उसने ऐसे सर हिलाया जैसे सब समझ गया हो. घर आ कर सबसे पहले उसने शब्दकोश में हजेल का मतलब ढूंढा. उसका मानना था कि अपने से ऊंचे स्तर की लड़की से प्यार कर रहे हो तो उसकी हर छोटी–बड़ी बात का विशेष ध्यान रखना चाहिये. भले ही सरकारी आंकड़ों में यादव ओ.बी.सी. की श्रेणी में आते हों पर उसके इलाके में ये कौम दबंग मानी जाती है, और वो नये जमाने के चलन में दबंगों की लड़की से प्यार कर बड़ी हिम्मत का काम कर रहा था.

क्रमश:

लेखक युवा कहानीकार हैं

feedback@chauthiduniya.com

साल 2014 की गणना के अनुसार मावल्यान्नांग गांव में 95 परिवार रहते थे. यहां सुपारी की खेती आजीविका का मुख्य साधन है. यहां लोग घर से निकलने वाले कूड़े–कचरे को बांस से बने डस्टबिन में जमा करते हैं और उसे एक जगह इकट्ठा कर खेती के लिए खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं. पूरे गांव में हर जगह कचरा डालने के लिए ऐसे बांस के डस्टबिन लगे हैं. यह गांव 2003 में एशिया का सबसे साफ और 2005 में भारत का सबसे साफ गांव बना. इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है की यहां की सारी सफाई ग्रामवासी स्वयं करते हैं. सफाई व्यवस्था के लिए वे किसी भी तरह प्रशासन पर निर्भर नहीं करते.

करियर

दूसरों को संवार बनाएं अपना करियर

सुंदर दिखना किसे पंसद नहीं है. सुंदरता प्राचीन काल से स्त्रियों व पुरुषों के लिए एक अहम विषय रही है, पर आजकल के व्यस्त जीवन में अपनी सुंदरता की ओर ध्यान देने के लिए लोगों को बहुत कम समय मिल पाता है. संभवत: यही वजह है कि हाल के कुछ ही वर्षों में मेकअप आर्टिस्ट के रूप में रोजगार के नए अवसर सामने आ रहे हैं. आज मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत सिर्फ फैशन मॉडल्स अथवा फिल्मी सितारों की ही नहीं है, बल्कि कई ऐसी जगहों पर भी इसकी बहुत मांग है. खासकर शादी के सीजन में इन लोगों की मांग बहुत बढ़ जाती है. अब तो इसमें भी स्पेशलाइजेशन हो गया है. जैसे कई मेकअप आर्टिस्ट ऐसे हैं, जो सिर्फ दूल्हे का मेकअप करते हैं, तो कोई दुल्हन का. टेलीविजन तथा फिल्मी कलाकारों का मेकअप अलग होता है. थिएटर में स्टेज आर्टिस्ट का मेकअप टीवी आर्टिस्ट की तुलना में चटख होगा. मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए कुछ विशेष गुणों की दरकार है.

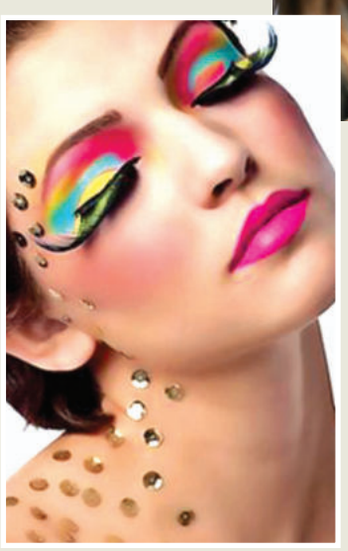

मेकअप करना एक खास किस्म का हुनर है. पार्टियों में जाने के लिए किए जाने वाले मेकअप से लेकर कलाकारों के मेकअप तक इसकी उपयोगिता से सभी भलीभांति परिचित हैं. लिहाजा, मेकअप करना शौक भी हो सकता है और एक कामयाब करियर भी. अब मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर करियर बनाने के इच्छुक युवा ट्रेनिंग लेने लगे हैं, ताकि उन्हें ब्यूटी चेन में अच्छी जॉब मिले और कम पूंजी में खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकें. मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है उम्मीदवार में सौंदर्यबोध का होना. आज मेकअप का मतलब है दूसरों को सम्मोहित करना. सबसे पहले आप में विजुअलाइजेशन की क्षमता होनी चाहिए कि कौन सा स्टाइल या गेटअप किस पर अच्छा लगेगा. उसे ऐसा रूप देना कि खुद को देखकर उसमें आत्मविश्वास भर जाए. कभी–कभी कई घंटों तक काम करना होता है. खासकर टीवी और फिल्म की शूटिंग के दौरान. शारीरिक और मानसिक रूप से मेकअप आर्टिस्ट का फिट होना जरूरी है, तभी वह अपने काम को सही–सही अंजाम दे पाएगा. आप में रंग और उसके असर की बारीक समझ होनी चाहिए.

प्रमुख संस्थान

- इंटरनैशनल पॉलीटेक्निक फॉर वूमैन, चंडीगढ़
- शहनाज हर्बल वूमेन्स वर्ल्ड इंटरनैशनल, मुम्बई
- लॉरियल एकेडमी, मुम्बई
- ब्लोसम कॉचर एस्थेटिक एंड स्पा एकेडमी, नई दिल्ली
- एल.टी.ए. स्कूल ऑफ ब्यूटी, मुम्बई
- लैकमे एकेडमी, मुम्बई व दिल्ली ■

सैर–सपाटा

चलिए एशिया के सबसे साफ गांव

शहरों की भीड़–भाड़ से आपका मन उब गया हो और आपको एक सुंदर, शांत और स्वच्छ जगह घुमने की तालाश हो तो इस बार हम आपको ले चलते हैं एक सुंदर, साफ गाांव की ओर. जो न सिर्फ भारत, बल्कि एशिया का सबसे सुन्दर और स्वच्छ गांव है. आज जहां देश में प्रधानमंत्री लोगों को स्वच्छता अभियान के लिए जागरूक कर रहे हैं, वहीं यह एक सुखद आश्चर्य की है कि एशिया का सबसे साफ़–सुथरा गांव भी हमारे देश भारत में है. यह है मेघालय का मावल्यान्नांग गांव, जिसे की भगवान का अपना बगीचा के नाम से भी जाना जाता है. सफाई के साथ–साथ यह गांव शिक्षा में भी आगे है. यहां की साक्षरता दर 100 फीसदी है. यानी यहां के सभी लोग पढ़े–लिखे हैं. इतना ही नहीं, इस गांव में ज्यादातर लोग सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करते हैं. यह गांव मेघालय के शिलांग और भारत–बांग्लादेश बॉर्डर से 90 किलोमीटर दूर है. साल 2014 की गणना के अनुसार, यहां 95 परिवार रहते थे. यहां सुपारी की खेती आजीविका का मुख्य साधन है. यहां लोग घर से निकलने वाले कूड़े–कचरे को बांस से बने डस्टबिन में जमा करते हैं और उसे एक जगह इकट्ठा कर खेती के लिए खाद की तरह इस्तेमाल करते हैं. इस गांव में हर जगह कचरा डालने के लिए ऐसे बांस के डस्टबिन लगे हैं. यह गांव 2003 में एशिया का सबसे साफ और 2005 में भारत का सबसे साफ गांव बना. इस गांव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहां की सारी सफाई ग्रामवासी स्वयं करते हैं. सफाई व्यवस्था के लिए गांववाले किसी भी तरह प्रशासन पर निर्भर नहीं हैं. पूरे गांव में जगह–जगह बांस के बने डस्टबिन लगे हैं. किसी भी ग्रामवासी को, वो चाहे महिला हो, पुरुष हो या बच्चे हों, जहां गन्दगी नज़र आती है, सफाई पर लग जाते हैं. फिर चाहे वो सुबह का वक़्त हो, दोपहर का या शाम का. इस गांव के आस–पास टूरिस्ट के लिए कई अमेंजिग स्पॉट हैं, जैसे वाटरफॉल, लिविंग रूट ब्रिज (पेड़ों की जड़ों से बने ब्रिज) और बैलेंसिंग रॉक्स और सबसे अमेजिंग तो चाय की चुस्की के साथ 80 फिट ऊंची मचान पर बैठ कर शिलांग को निहारना बेजोड़ है. यहां पर आपको पेड़ों की जड़ से बने ब्रिज दिख सकते हैं. इस तरह के ब्रिज पूरे विश्व में केवल मेघालय में ही मिलते हैं. गांव में कई जगह आने वाले पर्यटकों की जलपान सुविधा के लिए ठेठ ग्रामीण परिवेश की टी स्टाल बनी हुई है, जहां आप चाय का आनंद ले सकते हैं.

कैसे पहुंचें

मावल्यान्नांग गांव शिलॉन्ग से 90 किलोमीटर और चेरापुंजी से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. दोनों ही जगह से सड़क के द्वारा आप यहां पहुंच सकते हैं. आप चाहें तो शिलॉन्ग तक देश के किसी भी हिस्से से हवाईजहाज के द्वारा भी पहुंच सकते हैं. ■

खाना पीना

स्वाद में लाजवाब है *बंगाली खिचड़ी*

सामग्री

250 ग्राम बासमती चावल, 2 मध्यम आकार के आलू, 100 ग्राम मूंग की दाल, एक फूल गोभी, 100 ग्राम मटर दाना.

मसाला सामग्री

1 टुकड़ा अदरक, 2 हरी मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, थोड़ी–सी शक्कर, 2 खड़ी लाल मिर्च, आधा चम्मच जीरा, चुटकी भर हींग, 1 टुकड़ा दालचीनी, तेजपान के पत्ते 2, 3 लौंग, 2 छोटी इलायची, एक बड़ा चम्मच देशी घी, स्वादानुसार नमक, हरा धनिया.

विधि

सबसे पहले चावल को हाथ से मसलकर धो लें. अब आलू को छीलकर लंबे टुकड़ों में काट लें. फूल गोभी को भी बड़े–बड़े टुकड़ों में काट कर रख लें. अदरक कद्दूकस कर लें और हरी मिर्च काटकर रख लें. अब एक कड़ाही में मूंग की दाल को धीमी आंच पर गुलाबी होने तक भून लें. भूनते समय घी न डालें. अब इसमें घी, खड़ी लाल मिर्च, जीरा एवं हींग को छोड़कर बाकी सारी सामग्री मिलाकर आधा लीटर गरम पानी में धीमी आंच पर पका लें. इस दौरान बीच–बीच में चलाती रहें. पूरी तरह पक जाए तो समझ लीजिए की आपकी खिचड़ी तैयार है. तैयार खिचड़ी को परोसने से पहले एक अलग बर्तन में घी गर्म करके खड़ी लाल मिर्च, जीरा और हींग का छौंक लगाकर खिचड़ी में ऊपर से डाल दें. अच्छी तरह मिलाएं और हरा धनिया बुरकाकर गरमा–गरम लाजवाब बंगाली खिचड़ी पेश करें. ■

कोलकाता में एक फैशन शो में रैंप पर परिधानों का प्रदर्शन करतीं मॉडल्स.

व्हाट्सऐप चैट बैकअप गूगल ड्राइव पर

श्याम सुन्दर प्रसाद

smart7973@gmail.com

अगर आपके मोबाइल में मेमोरी या रैम कम हो और डेटा भर जाये तो आपका मोबाइल स्लो या हैंग हो जाता है. ऐसे समय में अगर आपका कोई जरूरी चैट फोटो या वीडियो हो, जिससे आप हमेशा अपने पास रखना चाहते हों तो आप उसे अपने गूगल ड्राइव पर सेव कर सकते हैं. इससे अगर कभी आपके फ़ोन को फॉर्मेट करना पड़े या किसी कारण वश आपका डेटा खो जाय तो आप यहां से ये सारी डेटा को फिर से वापस ले सकते हैं.

व्हाट्सऐप ने कुछ समय पहले ही अपने यूजर के लिए ये नया तोहफा दिया है, जिससे व्हाट्सऐप यूजर्स अपने व्हाट्सऐप मैसेज, ऑडियो और वीडियो का बैकअप सीधे गूगल ड्राइव पर ले सकते हैं और जब चाहे आप चैट हिस्ट्री, फोटो और वीडियो को आसानी से री–स्टोर कर सकते हैं.

एक साथ कई लोगों को मैसेज करें

व्हाट्सऐप में व्यक्तिगत चैट या मैसेज तो आसानी से करते हैं, लेकिन आप एक ही मैसेज को बहुत सारे लोगों को मैसेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कोई ग्रुप बनाते हैं और उसमे सभी मेंबर्स को ऐड करते हैं, जिसमें आप मैसेज के अलावा ग्रुप चैट करते हैं, लेकिन ग्रुप में आप मैसेज करते हैं, वह ग्रुप के सभी सदस्यों के पास पहुंच जाता है और जब ग्रुप में कोई रिप्लाई करते हैं तो वह मैसेज बाकी के सदस्यों को भी दिखाई देता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप मैसेज को सभी सदस्यों को एक साथ करें, पर उनके द्वारा भेजे गए मैसेज केवल आपको दिखाई दें तो व्हाट्सऐप में आप ब्रॉडकास्ट मैसेज ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं. इसके माध्यम से आप बिना कोई ग्रुप बनाये एक साथ बहुत सारे लोगों को मैसेज कर सकते हैं और उसका जवाब भी आपके पर्सनल चैट पर आएगा.

इसके लिए व्हाट्सऐप ओपन कर मेन्यू बटन को टच करें. यहां आपको न्यू ब्रॉडकास्ट ऑप्शन मिलेगा. उस पर टच करें. फिर जिस–जिस को आप एक साथ मैसेज शेयर करना चाहते हैं, उनका नंबर आपको सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के लिए + के अईकॉन को टच करें और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में से जितना नंबर चाहें, उसे टिक कर सेलेक्ट करें और ऊपर डाउन ऑप्शन पर टच करें. फिर सबसे ऊपर दाईं तरफ दिख रहे क्रिएट ऑप्शन पर टच करें और अपना जो भी मैसेज, फोटो या वीडियो शेयर करना चाहते हैं, उसको टाइप या सेलेक्ट कर शेयर कर दें.

शेयर करें अपनी करंट लोकेशन

व्हाट्सऐप पर अपना वर्तमान लोकेशन शेयर करने के लिए सबसे पहले फ़ोन में जीपीएस को स्टार्ट करें. फिर व्हाट्सऐप को ओपन कर अटैचमेंट्स को ओपन करें और फिर लोकेशन को सेलेक्ट कर सेंड योर करंट लोकेशन ऑप्शन पर टच कर अपने प्रिय लोगों को अपने लोकेशन की जानकारी दे सकते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

प्रो-बॉक्सिंग

विजेन्द्र ने ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए गिलेन को रस्सियों पर धकेल दिया. गिलेन अब पूरी तरह रक्षात्मक नजर आ रहे थे कि इसी बीच विजेन्द्र के एक जोरदार प्रहार ने गिलेन को फिर नीचे गिरा दिया. रेफरी ने दस तक काउंट किया, लेकिन गिलेन उठने की स्थिति में नहीं थे. विजेन्द्र ने विजेता बनने की खुशी में अपने दोनों हाथ उठा लिए. गिलेन ने अपने पहले दोनों प्रो-मुक़ाबले जीते थे.

विजेंदर की दूसरी जीत

विजेन्द्र ने अपना पहला प्रो-मुकाबला सोनी विटिंग को तीन राउंड में हराकर जीता था, लेकिन यहां जीतने में उन्हें तीन मिनट से भी कम का समय लगा. विजेन्द्र ने ढोल-नगाड़ों की थाप के बीच रिंग में प्रवेश किया और शुरुआत से ही गिलेन पर प्रहार करने शुरू कर दिये.

भारत के सुपरस्टार मुक्केबाज विजेन्द्र सिंह ने अपने दूसरे प्रो-मुक़ाबले में जबरदस्त पंच लगाते हुए अपने प्रतिद्वंद्वी डीन गिलेन को पहले ही राउंड में गिराकर नॉक-आउट कर दिया. ओलंपिक पदक विजेता विजेन्द्र ने तीन मिनट के पहले राउंड में गिलेन को इस कदर पीटा कि वह दो बार रिंग में ही गिर गए. दूसरी बार गिरने के बाद गिलेन उठ नहीं सके और विजेन्द्र को विजेता घोषित कर दिया गया. विजेन्द्र ने अपना पहला प्रो-मुकाबल सोनी विटिंग को तीन राउंड में हराकर जीता था, लेकिन यहां जीतने में उन्हें तीन मिनट से भी कम का समय लगा. विजेन्द्र ने ढोल-नगाड़ों की थाप के बीच रिंग में प्रवेश किया और शुरुआत से ही गिलेन पर प्रहार करने शुरू कर दिये. दूसरे मिनट में ही विजेन्द्र का सीधा पंच गिलेन के चेहरे से टकराया और वह गिर पड़े. इसके बाद तो विजेन्द्र ने ताबड़तोड प्रहार करते हुए गिलेन को रस्सियों पर धकेल दिया. गिलेन अब पूरी तरह रक्षात्मक नजर आ रहे थे कि इसी बीच विजेन्द्र के एक जोरदार प्रहार ने गिलेन को फिर नीचे गिरा दिया. रेफरी ने दस तक काउंट किया, लेकिन गिलेन उठने की स्थिति में नहीं थे. विजेन्द्र ने विजेता बनने की खुशी में अपने दोनों हाथ उठा लिए. गिलेन ने अपने पहले दोनों प्रो-मुक़ाबले जीते थे, लेकिन भारतीय मुक्केबाज के दमदार प्रहारों ने गिलेन को जमीन सुंघा दी और विजेन्द्र ने इस तरह अपना दूसरा प्रो मुकाबला जीत लिया.■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

क्रिकेट

आईपीएल टीम खरीदना चाहते हैं धोनी

बीसीसीआई ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट केबाद चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल से हटा दिया है. इस तरह आईपीएल में टीमों की संख्या घटकर 6 हो गई थी. टीमों की संख्या को 8 करने के लिए बीसीसीआई ने दो नई टीमों के लिए नौ शहरों का विकल्प दिया है, जिसमें अहमदाबाद, इंदौर और कानपुर शामिल हैं.

टीम इंडिया के वन-डे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इंडियन प्रीमियर लीग(आईपीएल) की एक फ्रेंचाइजी खरीदना चाहते हैं. धोनी ने बीसीसीआई को आईपीएल टीम खरीदने की ख्वाहिश से अवगत करा दिया है. बीसीसीआई ने दो नई टीमों के लिए निविदायें आमंत्रित की हैं. इसके लिए उसने बेस प्राइस 40 करोड़ रुपये रखा है. धोनी आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स से खेलते थे, जो कि अब सस्पेंड हो चुकी है. धोनी केअलावा कोलकाता के उद्योगपति संजीव गोयनका ने भी आईपीएल टीम खरीदने में रुचि दिखाई है. गोयनका इंडियन सुपर लीग की कोलकाता फ्रेंचाइजी एटलेटिको डी कोलकाता के सह मालिक भी हैं. बीसीसीआई ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में हाईकोर्ट के न्यायाधीश लोढ़ा कमेटी की रिपोर्ट के बाद चेन्नई सुपरकिंग्स और राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल से हटा दिया है. इस तरह आईपीएल में टीमों की संख्या घटकर 6 हो गई थी, टीमों की संख्या को 8 करने के लिए बीसीसीआई ने दो नई टीमों केलिए नौ शहरों का विकल्प दिया है, जिसमें अहमदाबाद, इंदौर और कानपुर शामिल हैं. इससे पहले धोनी ने हॉकी इंडिया लीग की रांची फ्रेंचाइजी को खरीदा था. उन्होंने बाइक रेसिंग की टीम भी खरीदी है. धोनी अपना रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं. आईपीएल टीम का मालिक बनकर वह धमाल मचा देंगे, जिस तरह उन्होंने चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान और रांची रेज का सह-मालिक बनकर धमाल मचाया. ■

रणजी इतिहास का पहला दस हज़ारी

पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने घरेलू क्रिकेट में ऐसा कारनामा कर दिखाया है, जो सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज नहीं कर सके. इस साल विदर्भ की ओर से खेलने वाले वसीम ने बंगाल के खिलाफ रणजी ट्रॉफी इतिहास के पहले दस हजारी बनने की उपलब्धि हासिल की. जाफर के अब रणजी मैचों में 10002 रन हैं और उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाते हुए अपने साथी पूर्व साथी खिलाड़ी मुंबई के अमोल मजूमदार के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया. वर्ष 1996-97 में मुंबई की ओर से खेलकर अपने करियर की शुरुआत करने वाले जाफर को यह उपलब्धि हासिल करने के लिए केवल आठ रनों की दरकार थी. उन्होंने बंगाल के तेज गेंदबाज वीर प्रताप सिंह की गेंद पर चौका जड़कर 10,000 रन पूरे किए. वसीम जाफर के नाम रणजी के साथ-साथ दिलीप (2545) और ईरानी ट्रॉफी (1008) में भी सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड दर्ज है. यह उपलब्धि हासिल करने के बाद जाफर ने कहा कि सबसे पुराने और एलीट टूर्नामेंट में 10 हजार रन पूरे करना मेरे लिए बहुत बड़ा पल है. मैं हमेशा से क्रिकेट के लिए जुनूनी रहा. मुझे खुद पर विश्वास था. इसी जुनून के कारण ही मैं यहां तक खेल पाया. रणजी ट्रॉफी की 1934-35 में शुरुआत के बाद यह पहला अवसर है, जबकि किसी बल्लेबाज ने यह उपलब्धि हासिल की है. 37 वर्षीय बल्लेबाज ने अपने 126वें मैच में यह मुकाम हासिल किया. जाफर के बाद रणजी में सबसे ज्यादा

रन अमोल मजूमदार (9202) और मिथुन मन्हास (8197) के नाम है. रणजी करियर में दस हजार रन बनाने वाले जाफर ने 35 शतक और 41 अर्धशतक लगाये हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 58.14 का रहा. 18 वर्ष की उम्र में करियर के दूसरे ही मैच में जाफर ने तिहरा शतक जड़ा था. साल 2000 में उन्हें भारतीय टीम में शामिल किया गया, लेकिन प्रदर्शन में निरंतरता की कमी की वजह से वह टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाये. जाफर के नाम प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 17000 से अधिक रन हैं, जिनमें 51 शतक और 83 अर्धशतक शामिल हैं.■

बीसीसीआई में बड़ा फेरबदल

पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को बीसीसीआई की तकनीकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. गांगुली इस पद पर पूर्व कप्तान अनिल कुंबले की जगह लेंगे.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में हाल ही में विवादों का केंद्र बने हितों के टकराव(कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट) के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया के मौजूदा डायरेक्टर रवि शा ी को इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की संचालन परिषद से हटा दिया गया है. वह फिलहाल भारतीय क्रिकेट टीम के डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हैं. बीसीसीआई ने अपनी वार्षिक बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए. वह अगले साल मार्च से अप्रैल में होने वाले टी-20 विश्व कप तक डायरेक्टर पद पर बने रहेंगे. आईपीएल संचालन परिषद में अध्यक्ष राजीव शुक्ला के अलावा अन्य सदस्यों में ज्योतिरादित्य सिंधिया, अजय शिर्के, एमपी पांडोव और सौरभ गांगुली शामिल हैं. हितों के टकराव के संदर्भ में सभी शिकायतों को लोकपाल को सौंपा जाएगा, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश ए पी शाह हैं. बीसीसीआई के नियमों को लेकर प्रस्तावित संशोधनों को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया है. पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को बीसीसीआई की तकनीकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. गांगुली इस पद पर पूर्व कप्तान अनिल कुंबले की जगह लेंगे. साथ ही प्रशासनिक समीक्षा समिति के सदस्य पीएस रमन को कानूनी समिति का अध्यक्ष चुना गया है. अनुशासन समिति का अध्यक्ष पद बोर्ड अध्यक्ष शशांक मनोहर के पास रहेगा. संबद्धता समिति की जिम्मेदारी बीसीसीआई सचिव अनुराग ठाकुर, प्रकाश दीक्षित और अंशुमन गायकवाड़ संभालेंगे. राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बोर्ड के अध्यक्ष निरंजन शाह, मार्केटिंग समिति के चेतन देसाई, वित्त समिति के ज्योतिरादित्य सिंधिया, दौरा कार्यक्रम समिति के जी गंगराजू, मीडिया समिति के अरुण सिंह ठाकुर, अंपायर समिति के सी के खन्ना और महिला समिति के अध्यक्ष कपिल मलहोत्रा को बनाया गया है. बीसीसीआई की बैठक में यह भी फैसला किया गया कि हर तीसरे महीने में उसकी बैठक होगी और बोर्ड प्रशासन को मजबूत बनाने के लिये प्रोफेशनल नियुक्तियां की जाएंगी.■

एथलेटिक्स

रूस पर प्रतिबंध की सिफ़ारिश

वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) की एक रिपोर्ट में सिफ़ारिश की गई है कि एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए. वाडा के एक स्वतंत्र जांच आयोग ने रूसी खिलाड़ियों से जुड़े डोपिंग, मामले की लीपापोती और ज़बरन वसूली के आरोपों की पड़ताल की है. जांच के दायरे में अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स संस्था आईएएएफ को भी शामिल किया गया था. इसमें डोपिंग के लिए पांच खिलाड़ियों और पांच कोचों पर आजीवन प्रतिबंध लगाने पर भी ज़ोर दिया गया है. इस रिपोर्ट के मुताबिक़ आईएएएफ़ डोपिंग पर क़ाबू पाने के लिए कोई प्रभावी कार्यक्रम लागू करने में असफल रहा है. रूसी एथलीटों पर डोपिंग का संदेह होने के बावजूद रूसी एथलेटिक संस्था और आईएएएफ़ की निष्क्रियता साल 2012 के लंदन ओलंपिक में भी नज़र आई थी.वहीं इस रिपोर्ट के आने से पहले आईएएएफ के अध्यक्ष लॉर्ड को ने कहा था कि ये एथलेटिक्स के लिए काले दिन हैं. जिस दिन मैं अध्यक्ष चुना गया, मैंने बड़े पैमाने पर समीक्षा शुरू की. मैं एथलेटिक्स की प्रतिष्ठा दोबारा क़ायम करने के लिए प्रतिबद्ध हूं. हालांकि सुधार का रास्ता काफ़ी लंबा है. रूस ने अपने खिलाड़ियों पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है.■

WORLD ANTI-DOPING AGENCY
play true

तुम्हें भुला न पाएंगे...

मिहिर सेन: इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय

जाने-माने भारतीय तैराक मिहिर सेन इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले पहले भारतीय तैराक थे. 22 साल की उम्र तक वह तैराकी के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे. इस दौरान उन्होंने स्थानीय समाचार पत्र में अमेरिकी महिला तैराक फ्लोरेंस चैडविक के 31 साल की उम्र में इंग्लिश चैनल पार करने संबंधी समाचार पढ़ा. मिहिर इस खबर से बेहद प्रभावित हुए. उन्होंने सोचा, जब एक अमेरिकी महिला इंग्लिश चैनल पार कर सकती है, तो कोई भारतीय ऐसा क्यों नहीं कर सकता? उस समय उन्होंने तय किया कि वह तैराकी सीखेंगे और इस उपलब्धि को हासिल करेंगे. इसके बाद उन्होंने वाईएमसीए संस्थान से तैराकी का प्रशिक्षण लेना शुरू किया और तब तक तैराकी सीखते रहे, जब तक उन्होंने फ्री स्टाइल तैराकी में महारत हासिल नहीं कर ली. वह दुनिया को यह दिखाना चाहते थे कि एक भारतीय युवक में भी वह सभी क्षमताएं हैं, जो विदेशी लोगों में होती हैं. वर्ष 1953 में उन्होंने इंग्लिश चैनल पार करने का निर्णय लिया. मिहिर ने 1955 में इंग्लिश चैनल को पार करने का पहला प्रयास किया था. उन्होंने चार साल में आठ बार प्रयास किया, जिसमें वह असफल रहे. सितंबर 1958 को मिहिर इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले एशियाई और भारतीय बने. यह उपलब्धि उन्होंने 15 घंटे 45 मिनट में

तैरकर हासिल की. श्रीलंका का पाक स्ट्रेट पार करने के बाद मिहिर ने 24 अगस्त, 1966 को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तैरकर पार किया. 12 सितम्बर, 1966 को एशियाटिक तुर्की और यूरोप के बीच 61 किलोमीटर की डार्डनेलस स्ट्रेट को पार करने वाले वह विश्व के पहले तैराक बने. 21 सितम्बर, 1966 को एशिया और यूरोप की सीमा वास्फोरस, जिसे इस्तांबुल स्ट्रेट भी कहा जाता है, उसे पार करने का गौरव हासिल किया. 29 अक्टूबर, 1966 को उन्होंने पनामा नहर को तैरकर पार किया. मिहिर की इस उपलब्धि ने देश में कई युवा तैराकों के लिए प्रेरणा का काम किया. वह सात सागर तैरकर पार करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति थे और उन्होंने विभिन्न सागरों और महासागरों में 600 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी तैरकर पार की. मिहिर की सफलताओं ने भारतीय तैराकों को लंबी दूरी की तैराकी के प्रति आकर्षित किया और उनके बाद कई भारतीयों ने इंग्लिश चैनल को पार करने में सफलता हासिल की. सरकार ने भी इस दिग्गज तैराक की उपलब्धियों को मान्यता देते हुए 1959 में उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया, जबकि 1967 में उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्म भूषण से नवाज़ा गया. 11 जून, 1997 को 66 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया.■

रणबीर और दीपिका का तमाशा

फिल्म का ट्रेलर दर्शकों के दिल और दिमाग में छाया हुआ है.बॉलीवुड के जानेमाने फिल्मकार करण जौहर भी फिल्म तमाशा देखने के लिये बेताब हैं. करण जौहर का कहना हैं कि फिल्म तमाशा बिल्कुल आश्चर्यजनक लग रही है. मैं इम्तियाज की फिल्म देखने का इंतजार नहीं कर सकता. मैं इसे रणवीर और दीपिका के लिए नहीं देखूंगा बल्कि मैं इसे इम्तियाज अली की वजह से देखूंगा.

बी टाउन एक्टर रणबीर कपूर और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण एक बार फिर अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री के साथ बड़े पर्दे पर तमाशा' करने आ रहे हैं. यूटीवी मोशन पिक्चर्स की इस फिल्म को इम्तियाज अली ने बनाया है. फिल्म का ट्रेलर दर्शकों के दिल और दिमाग में छाया हुआ है. इस फिल्मक के एक गाने में दिखाया गया है कि किस तरह रणबीर कपूर अपने पापा से डरते हुए इंजीनियर न बनने की बात कह रहे हैं. इस गाने को देखकर ये साफ पता चलता है कि फिल्म में रणबीर एक ऐसे लड़के का किरदार निभा रहे हैं जो अपने घरवालों के प्रेशर में आकर पढ़ाई करता है और लाइफ से परेशान रहता है. फिल्म में दोनों स्टार्स के कुछ दिलचस्प सीन भी हैं. जो इस जोड़ी के फैन्स को जरुर पसंद आएंगे

प्रोमों को देखकर फिल्म की कहानी का अनुमान लगाया जा सकता है. इस फिल्म की कहानी दो ऐसे जवान लोगों के इर्द–गिर्द घूमती है जो अजनबियों की तरह कोर्सिका मंन मिलते हैं. मजाक मजाक में दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फ्रेंच आइलैंड पर साथ में एक झूठी जिंदगी जीएंगे. जिसमें वो दोनों पुराने दिग्गज अभिनेताओं जैसे कि देव आनंद और डॉन से लेकर मोना डार्लिंग का किरदार निभाते नज़र आते हैं.

तमाशा की कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अनचाहे ढंग से रणबीर और दीपिका में प्यार हो जाता है. झूठी एक्टिंग की जगह असली इमोशंस सामने आते हैं. फिल्म का आई कैचिंग सीन है रणबीर औऱ दीपिका की लव मेकिंग सीन. यह सीन दर्शकों को बेहद हॉट और इंटेंस लग रहा है. दीपिका और रणबीर इससे पहले ये जवानी है दिवानी और बचना ऐ हसीनों में साथ नज़र आ चुके हैं.

बॉलीवुड के जानेमाने फिल्मकार करण जौहर भी फिल्म तमाशा देखने के लिये बेताब हैं. करण जौहर का कहना हैं कि फिल्म तमाशा बिल्कुल आश्चर्यजनक लग रही है. मैं इम्तियाज की फिल्म देखने का इंतजार नहीं कर सकता. मैं इसे रणवीर और दीपिका के लिए नहीं देखूंगा बल्कि मैं इसे इम्तियाज अली की वजह से देखूंगा. रणबीर इन दिनों करण जौहर के साथ फिल्म ऐ दिल है मुश्किल' में काम कर रहे हैं. इससे पूर्व रणबीर और दीपिका ने करण जौहर की फिल्म ये जवानी है दीवानी' में काम किया था जो सुपरहिट रही थी.फिल्म तमाशा' 27 नवंबर को प्रदर्शित होगी. अब देखते है तमाशा' फिल्म में ये जोड़ी क्या कमाल दिखाती है.■

संगीत की देवी लता मंगेशकर

ल गभग छह दशक में अपनी जादुई आवाज के जरिये बीस से अधिक भाषाओं में हजारों गीत गाकर संगीत की देवी लता मंगेशकर श्रोताओं के दिल पर राज कर रही हैं.28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच से जुड़े हुए थे.पांच वर्ष की उम्र में लता ने अपने पिता के साथ नाटकों में अभिनय करना शुरू किया. इसके साथ ही वह पिता से संगीत की शिक्षा भी लेने लगी.वर्ष 1942 में तेरहा वर्ष की छोटी उम्र में ही लता के सिर से पिता का साया उठ गया और परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गईं. इसके बाद उनका पूरा परिवार पुणे से मुंबई आ गया. हालांकि लता को फिल्मों में अभिनय करना जरा भी पसंद नही था बावजूद इसके परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को उठाते हुए लता ने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया.

लता को फिल्म मंगलगौर में अभिनय करने का मौका मिला. 1945 में लता की मुलाकात संगीतकार गुलाम हैदर से हुई. गुलाम हैदर, लता की गायकी से काफी प्रभावित हुए. गुलाम हैदर ने फिल्म निर्माता एस .मुखर्जी से यह गुजारिश की कि वह लता को अपनी फिल्म शहीद में गाने का मौका दे. एस. मुखर्जी को लता की आवाज पसंद नहीं आई और उन्होंने लता को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया. इस बात को लेकर गुलाम हैदर काफी गुस्सा हुए और उन्होंने कहा यह लड़की आगे इतना अधिक नाम करेगी कि बड़े–बड़े निर्माता–निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में गाने के लिए गुजारिश करेंगे.

महल 1949 के गाने आएगा आने वाला गाने के बाद लता बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई. इसके बाद राजकपूर की बरसात के गाने जिया बेकरार है, हवा में उड़ता जाए जैसे गीत गाने के बाद लता मंगेशकर बॉलीवुड में एक सफल पार्श्वगायिका के रूप में स्थापित हो गईं. सी. रामचंद्र के संगीत निर्देशन में लता ने प्रदीप के लिखे गीत पर एक कार्यक्रम के दौरान एक गैर फिल्मी गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया. इस गीत को सुनकर प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू इतने प्रभावित हुए कि उनकी आंखो में आंसू आ गए. लता के गाए इस गीत से आज भी लोगों की आंखें नम हो उठती है.

संगीतकार नौशाद लता की आवाज के इस कदर दीवाने थे कि वह अपनी हर फिल्म में लता को ही लिया करते थे. हिन्दी सिनेमा के शो मैन कहे जाने वाले राजकपूर को सदा अपनी फिल्मों के लिए लता मंगेशकर की आवाज की जरूरत रहा करती थी. उन्होंने लता को सरस्वती का दर्जा तक दे रखा था. साठ के दशक में लता पार्श्वगायिकाओं की महारानी कही जाने लगी. नब्बे के दशक में लता चुनिंदा फिल्मों के लिए गाने लगी. वर्ष 1990 में अपने बैनर की फिल्म लेकिन के लिए लता ने यारा सिली सिली गाना गाया. हालांकि यह फिल्म नहीं चली, लेकिन आज भी यह गाना लता के बेहतरीन गानों मे से एक माना जाता है. लता को उनके सिने करियर में कई बार फिल्मफेअर पुरस्कार मिला. उनके गाए गीत के लिए वर्ष 1992 में फिल्म परिचय, 1995 में कोरा कागज और 1990 में फिल्म लेकिन के लिए नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. इसके अलावा लता को वर्ष 1969 में पद्मभूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के सम्मान, 1999 में पद्मविभूषण और 2001 में भारत रत्न मिला.■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

बिहार की सच्चाई बयान करती फिल्म

वन्स अपॉन ए टाइम इन बिहार

फि ल्में समाज का आईना होती हैं. इस कहावत को सच करती है नितिन चंद्रा द्वारा निर्देशित फ़िल्म वन्स अपॉन ए टाइम इन बिहार. बिहार समेत समूचे उत्तर भारत की सामाजिक, आर्थिक और व्यावहारिक दशा को बखूबी इस फिल्म की शक्ल दी है. प्रोड्यूसर नीतू चंद्रा ने निर्देशक नितिन चंद्रा के सहयोग से कुछ सच्ची घटनाओं को लेकर फिल्म वन्स अपॉन ए टाइम इन बिहार में बिहार का पर्दाफाश किया है.

फिल्म कहानी शुरू होती हैं तीन युवकों से जिनमें एक पढे लिखे युवक क्रांती प्रकाश झा जो आई ए एस का दो बार एग्जाम दे चुका हैं और स्कूल में छोटी सी नौकरी करने के लिये मजबूर है. क्योंकि उसे अपनी बहन की शादी में दहेज देने के लिये पैसे चाहिये. इसी तरह एक और बी कॉम तक पढ़े विजय कुमार से सरकारी नौकरी के लिये दो लाख की घूस मांगी जाती है. तो वही तीसरा किरदार दीपक सिंह एक सिंगर और गीतकार हैं लेकिन वो भी चाय की दुकान पर काम करने के लिये मजबूर है. जब उन्हें कहीं से कोई हेल्प नही मिलती तो वे भी अपनी जरूरत पूरी करने के लिये अपहरण करने का निश्चय करते हैं और गलती से होटल मालिक की जगह आंध्र प्रदेश के बड़े नक्सल नेता आशीष विद्यार्थी का अपहरण कर लेते है जब उन तीनो को उसके बारे में पता चलता है तो वे बुरी तरह घबरा जाते हैं आशीष को जब उनकी परेशानियों के बारे में पता चलता हैं तो वो उन्हें पैसे का लालच देकर है कि वे उसे आन्ध्रा के बार्डर तक छोड़ आये . आशीष अपना वादा पूरा करता हैं लेकिन इस बीच पुलिस मुठभेड़ में दीपक सिंह मारा जाता हैं बाद में आशीष समेत सारे आंतकवादी भी मारे जाते हैं. लेकिन क्रांती बच कर आता हैं बाद में क्रांती प्रकाश भी आत्मसमपर्ण कर देता है. उनके द्वारा सारी कहानी पता चलती है तो लोगों को लगता है कि इनकी बदौलत बिहार में कितने ही निर्दोष लोग मरने से बच गये. इसलिये वे सरकार से उन्हें बरी करने के लिये आंदोलन शुरू कर देते हैं .

फिल्म बताती हैं कि बिहार में पढ़ा लिखा तबका किस कदर परेशान है. कदम कदम पर भ्रष्टाचार, खुलेआम रिश्वतखोरी, दहेज तथा बेरोजगारी जैसी विकृतियों से पूरा बिहार त्रस्त है. निर्देशक ने इन सारी चीजों का इस कदर प्रभावशाली चित्रण किया है कि फिल्म बिहार का अपनी सच्ची कहानी के द्वारा पूरी सच्चाई के साथ पर्दाफाश करती है. वहां का माहौल, लाकेशंस और भाषा फिल्म को और ज्यादा प्रभावशाली बनाती हैं.फिल्म में अंजाने चेहरे, कुशल अभिनेता साबित हुये हैं. इनमें क्रांती प्रकाश झा ने बेहतरीन अभिनय किया है. पढ़े लिखे बेरोजगार युवक की भूमिका को अजय कुमार ने सार्थक किया है इसी तरह एक सिंगर बनने का सपना देखते दीपक सिंह भी अच्छे लगे. अगर आपको सच्ची कहानी प्रेरित करती हैं तो एक बार फिल्म जरूर देखें.■

सुपरहिट फिल्मों की जान सलीम खान

स लीम खान हिंदी सिनेमा के उन पटकथा लेखकों में गिने जाते हैं जिन्हें भारतीय फिल्मों के नायक को नया रूप देने के लिए जाना जाता है. सलीम खान का जन्म 24 नवंबर 1935 को इंदौर में हुआ. 1964 में सलीम खान ने महाराष्ट्र की ब्राह्मण लड़की से शादी कर ली. और फिर 1981 में सलीम खान ने अपने जमाने की मशहूर डांसर हेलेन से दुसरी शादी की. शादी के करीब दो साल बाद उन्होंने एक छोटी बच्ची अर्पिता को गोद लिया. उन्होने शोले, दीवार, ज़ंजीर और हाथी मेरे साथी जैसी ढेरों सुपरहिट फिल्में लिखीं.

मुंबई आकर सलीम खान की इच्छा एक्टर बनने की थी. उन्होंने लगभग 14 फिल्मों में छोटे–मोटे रोल भी किए. लेकिन बतौर एक्टर कुछ खास बात नहीं कर पाऐ . सलीम खान बतौर एक्टर जिन फिल्मों में नजर आए उनमें 1966 में तीसरी मंजिल और सरहदी लूटेरा, 1967 में 'दीवाना' और 1977 में 'वफादार' प्रमुख हैं.

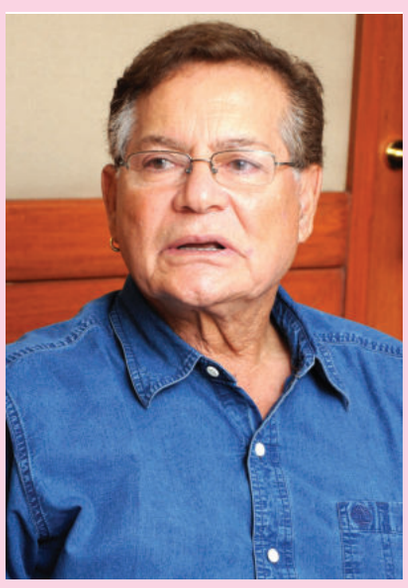

सलीम–जावेद की जोडी को कोई कैसे भुल सकता हैं.सलीम–जावेद की जोड़ी यूं तो पहली बार अंदाज में साथ आई लेकिन हाथी मेरे साथी, सीता और गीता, यादों की बारात ने उन्हें मुक्कमल जहान दिया. अमिताभ बच्चन को जंजीर, शोले और डॉन जैसी फिल्मों के जरिए एंग्री यंग मैन बनाना भी सलीम–जावेद के कलम की ही जादूगरी थी.हालांकि 1982 में फिल्म शक्ति के दौरान इस दोस्ती में दरार आ गई और फिर दोनों की राहें जुदा हो गईं. दोनों के आखिरी बार 1987 में मिस्टर इंडिया के लिए साथ काम किया.

जोड़ी टूटने के बाद जावेद अख्तर ने भले ही लिखना जारी रखा, लेकिन सलीम खान ने 1996 के बाद फिल्मों के लिए लेखन को अलविदा कह दिया. जावेद से अलगाव के बाद उन्होंने नाम, पत्थर के फूल, तूफान, मझधार और दिल तेरा दीवाना जैसी फिल्मों की कहानी लिखी. लिहाजा उन्होंने धीरे–धीरे लेखन से दूरी बना ली. हालांकि बेटे सलमान की कई फिल्मों (वीर, किक, वांटेड, दबंग) की कहानी और डायलॉग के लिए वह टिप्स जरूर देते हैं.■

दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई वाली सिंगर

कैटी ने अपनी 2013 की अल्बम 'प्रिज्म' के समर्थन में पेरी ने दुनिया भर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने 126 शो किए और हर शहर से 20 लाख डॉलर से ज्यादा की कमाई की.

अ मेरिकी गायिका कैटी पेरी 2015 में सर्वाधिक कमाई करने वाली गायिकाओं में सबसे बन चुकी हैं. फोर्ब्स पत्रिका की सूची के मुताबिक पेरी कमाई के मामले में अन्य गायिकाओं से आगे हैं. इस वर्ष 13.5 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ पेरी फोर्ब्स की बुधवार को जारी सूची में सबसे ऊपर हैं.अपनी 2013 की अल्बम 'प्रिज्म' के समर्थन में पेरी ने दुनिया भर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने 126 शो किए और हर शहर से 20 लाख डॉलर से ज्यादा की कमाई की. कैटी पेरी ने इस वर्ष की शुरुआत में फोर्ब्स को कहा कि मुझे अपनी कंपनी की मालिक खुद होने पर गर्व है. कमाई की इस दौड़ में पेरी के बाद 8 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ अगला स्थान टेलर स्विफ्ट को मिला है.■

हॉलीवुड की वजह से हो रहा है बॉलीवुड फिल्मों का बिजनेस प्रभावित : इरफान

मैं दोनों फिल्मोद्योग जगत में काम कर रहा हूं. हॉलीवुड में अलग तरह के कौशल की मांग है, उनका दर्शक अलग है. मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अलग तरह के सिनेमा में काम करने का मौका मिला.

अं तर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता हासिल कर चुके अभिनेता इरफान खान का कहना है कि विदेशी फिल्मों ने भारतीय फिल्मों पर धाक जमा ली है और इस वजह से बॉलीवुड फिल्मों का कारोबार प्रभावित हो रहा है. फ्यूरिस 7, एवेंजर्स : एज ऑफ अल्ट्रन और जुरासिक वर्ल्ड जैसी हॉलीवुड फिल्मों ने इस साल भारतीय बॉक्स ऑफिस पर काफी धमाल मचाया है .इरफान ने कहा कि मैं दोनों फिल्मोद्योग जगत में काम कर रहा हूं. हॉलीवुड में अलग तरह के कौशल की मांग है, उनका दर्शक अलग है. मैं सौभाग्यशाली हूं कि मुझे अलग तरह के सिनेमा में काम करने का मौका मिला.उन्होंने कहा कि दोनों उद्योगों में अलग–अलग खासियतें हैं. हॉलीवुड का दायरा बड़ा है अधिक सशक्त है.■

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

बिहार-झारखंड

23 नवंबर–29 नवंबर, 2015 Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

सहयोगी दल भाजपा के सिर फोड़ रहे हैं

हार का ठीकरा

यह तस्वीर चुनाव के पहले की है जब एनडीए ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की थी. एनडीए के घटक दलों के नेता एक दूसरे के हाथों में इस तरह हाथ डाले खड़े हैं जैसे जीत की बाजी इन्हीं की होनी है. लेकिन चुनाव बाद पूरी तस्वीर ही बदल गई. एनडीए की जो लहर इन नेताओं को उस समय दिखाई दे रही थी वह चुनाव हारने के बाद अब कड़वाहट में बदलती जा रही है. भाजपा के सहयोगी दल लोजपा, हम और रालोसपा के नेता सीधे तौर पर हार के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. इन नेताओं का कहना है कि ऐन चुनाव पूर्व संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान ने सारे जातीय समीकरण खराब कर दिए और उनके लिए चुनाव में बने रहना मुश्किल हो गया. इस पूरे मामले पर दोनों ही पक्षों की बातें रखती हमारी यह स्टोरी...

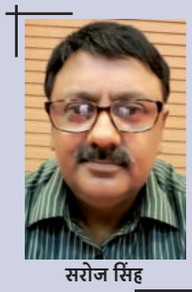

सरोज सिंह

जीत का सेहरा तो हर कोई अपने माथे पर बांधने को आतुर रहता है पर जब मौका हार का होता है तो एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है. यह बात तो वैसे हर मैदान में लागू होती है पर राजनीति के अखाड़े में इसका कुछ ज्यादा ही प्रचलन है. अभी जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो भाजपा के साथ ही साथ सहयोगी दलों का प्रर्दशन भी बेहद खराब रहा. भाजपा ने तो सधे अंदाज में टिप्पणी की कि सभी ने पूरा प्रयास किया पर नतीजे हमारे अनुकूल नहीं आए. लेकिन सहयोगी दल यानि की रालोसपा, लोजपा और हम ने गठबंधन धर्म को ताक पर रखकर भाजपा पर दोष मढ़ना शुरू कर दिया. सहयोगी दलों की नाराजगी मुख्यत: दो तीन बातों पर ज्यादा है. सहयोगी दलों का कहना है कि ज्यादातर चुनाव प्रचार में भाजपा ने यह संदेश देने का प्रयास किया कि अबकी बार भाजपा सरकार. अगर भाजपा ने पहले ही दिन से एनडीए सरकार की बात कही होती तो चुनाव नतीजे कुछ और ही होते. सहयोगी दलों ने मोहन भागवत के आरक्षण संबंधी बयान को हार का महत्वपूर्ण कारण बताया है. हालांकि यह बात भाजपा के कुछ नेता खुले तौर पर और कुछ दबी जुबान से कह रहे हैं. हम के जीतनराम मांझी और महाचंद्र सिंह का कहना है कि मोहन भागवत ने सही बयान गलत समय पर देकर सब चौपट कर दिया. चुनाव से पहले एनडीए की लहर थी और हम दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने जा रहे थे लेकिन संघ प्रमुख के बयान ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. सामाजिक समीकरण जो हमने अपने हिसाब से मजबूत और तय कर लिए थे. इसमें भारी फेरबदल हो गया और लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने इसका बखूबी फायदा उठा लिया. लोजपा और रालोसपा के बड़े नेता भी ऑफ द रिकार्ड यह कह रहे हैं कि आरक्षण के बारे में मोहन भागवत के बयान ने जीती हुई बाजी पलट दी. हमलोग लाख जतन करने के बावजूद अपने समर्थकों को नहीं रोक पाए और बुरी तरीके से हार गए. यहां यह गौर करने वाली बात है कि भाजपा सांसद हुकुमदेव यादव भी खुलेआम कह रहे हैं कि संघ प्रमुख का बयान एक बड़ी चूक थी. लेकिन भाजपा के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा कहते हैं कि हमलोग हार के कारणों की गहन समीक्षा कर रहे हैं लेकिन जहां तक हमें लगता है कि संघ प्रमुख के बयान से चुनाव के नतीजे प्रभावित नहीं हुए. एनडीए को एक करोड़ 30 लाख के करीब वोट मिले हैं.

हम के जीतनराम मांझी और महाचंद्र सिंह का कहना है कि मोहन भागवत ने सही बयान गलत समय पर देकर सब चौपट कर दिया. चुनाव से पहले एनडीए की लहर थी और हम दो तिहाई बहुमत से सरकार बनाने जा रहे थे लेकिन संघ प्रमुख के बयान ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया. सामाजिक समीकरण जो हमने अपने हिसाब से मजबूत और तय कर लिए थे, उसमें भारी फेरबदल हो गया. लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने इसका फायदा उठा लिया. लोजपा और रालोसपा के बड़े नेता भी ऑफ द रिकार्ड यह कह रहे हैं कि आरक्षण के बारे में भागवत के बयान ने जीती हुई बाजी पलट दी.

अगर आरक्षण संबंधी बयान से कुछ फर्क पड़ा होता तो हमें इतने वोट कैसे आते. सुधीर कहते हैं कि हार या जीत का कोई एक कारण नहीं होता है. सभी लोगों ने चुनाव में काफी मेहनत की. हमारे सहयोगी दलों ने भी पूरा दम लगाया पर चुनाव नतीजे हमारी आशा के अनुकूल नहीं आ सके. सुधीर शर्मा कहते हैं कि भाजपा हमेशा आगे की तरफ देखती है. बिहार की जनता की सेवा ही हमारा धर्म है और इसे हमलोग हर परिस्थिति में निभाते रहेंगे.

सहयोगी दलों का कहना है कि भाजपा का 158 सीटों पर लड़ने का फैसला भी सही नहीं था. इसका एक संदेश सहयोगी दलों के वोटरों पर यह गया कि भाजपा अपने बलबूते ही सरकार बनाना चाहती है और चुनाव बाद कहीं सहयोगी दलों को ठेंगा न दिखा दे. इसका नतीजा यह हुआ कि सहयोगी दलों के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ चुनावी अभियान में नहीं जुटे. जबकि भाजपा के नेता कहते हैं कि अगर सहयोगी दलों का वोट भाजपा में आया होता तो नतीजे कुछ और ही होते. आंकड़े बताते हैं कि राजद से पांच में चार कुशवाहा जीते हैं तो जदयू में 12 में 11. इसी तरह राजद में छह में चार पासवान जीते हैं तो जदयू से चार में चार. राजद में 10 में 9 महादलित जीते हैं तो जदयू में 6 से पांच. अब यह कैसे कहा जा सकता है कि कुशवाहा पासवान और महादलित के वोटरों ने एनडीए का खुलकर साथ दिया. रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी इन बिरादरियों के नेता होने का दावा करते हैं पर हुआ क्या यह सब अब सामने है. सहयोगी दलों का आरोप है कि टिकट बंटवारे को जान बूझकर देर से शुरू किया गया. अंतिम समय में टिकटों का फैसला होने से उम्मीदवारों को कई मुसिबतों का सामना करना पड़ा. पहला नुकसान यह हुआ कि जिस किसी को भी टिकट मिला वह समय के अभाव में अपने साथी दलों के स्थानीय कार्यकर्ताओं से समन्वय नहीं बना सका. अंतिम समय तक यह सस्पेंस बना रहा कि अमुक सीट से किस पार्टी का कौन प्रत्याशी लड़ेगा. इससे फायदा कम और नुकसान ज्यादा हुआ. सभी नेता जनता से संवाद करने के बजाय अंतिम समय तक टिकटों की आस में पटना और दिल्ली दौड़ते रहे.

– शेष पृष्ठ संख्या 18 पर

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

एक नज़र

स्वावलम्बी हो रहीं महिलायें

वैशाली जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर महुआ प्रखंड के समसपुरा गांव में रश्मि सेवा संस्थान के बैनर तले महिलाओं को स्वरोजगार हेतु ब्यूटिशियन प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाया जा रहा है. यहां गांव की लड़कियां बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं. वे बड़ी दिलचस्पी से ट्रेनिंग ले रही हैं. प्रशिक्षण का निर्देशन कर रहीं रश्मि प्रिया ने बताया कि हमारा उद्देश्य महिलाओं को आत्म निर्भर बनाना है ताकी उन्हें अपने खर्चे के लिए दूसरे पर निर्भर करना न पड़े. इससे पूर्व भी सिलाई कटाई पेंटिंग की ट्रेनिंग दी गयी है. जिन्होंने अच्छे ढंग से ट्रेनिंग ली है वे खुद का रोजगार चला रही हैं. उम्मीद है जिस तरीके से प्रशिक्षण चल रहा है, इस बार भी सफलता निश्चित होगी. प्रशिक्षण प्राप्त कर रही प्रीति, प्रीतम, निशि, कंचन, रिंकी, रेखा, सोनी, किरण, सुमन कुमारी ने बताया कि हमलोगों का भविष्य इसमें दिखाई देता है इसलिए इसे अच्छे ढंग से पहले सीख कर स्वरोजगार कर स्वबलम्बी बनना है. सबकी ललक कुछ अच्छा करने की है, सरकार चाहे तो ट्रेनिंग उपरान्त बैंक से ऋण मुहैया कराकर सभी के लिए अपना-अपना पार्लर खुलवाने की सुविधा दे दे तो सबके चेहरे पर चार चांद लग जाएगा. *– सुधीर मालाकार*

वैशाली में महागठबंधन की बही बयार

वैशाली जिला को लोकतंत्र का आंगन कहा जाता है. लोकतंत्र के इस आंगन में कई कथाएं लिखी जा चुकी हैं. किसी का सूरज उदय हुआ तो किसी का अस्त. बिहार विधानसभा चुनाव और वैशाली जिला कई मायनों में सुर्खियों में रहा, क्योंकि महागठबंधन के ताकतवर नेता जिसकी डेढ़ दशक तक बिहार में तूती बोलती थी, ने अपने दोनों पुत्र तेजप्रताप को महुआ एवं तेजस्वी को राघोपुर से प्रोजेक्ट कर राजनीति में इनके पुर्नउत्थान का श्री गणेश किया. वैशाली जिले में कुल आठ विधानसभा क्षेत्र में महागठबंधन का बोलबाला रहा वहीं एनडीए फिसड्डी साबित हुई. छह विधानसभा में महागठबंधन के उम्मीदवार विजयी रहे जिसमें ज्दातर नये चेहरे के सेहरे पर ताजपोशी हुई. राघोपुर में लालू प्रसाद के छोटे पुत्र तेजस्वी जदयू ने हाल फिलहाल में आये भाजपा के नेता सतीश कुमार को हराया, वहीं महुआ में हम उम्मीदवार एवं पूर्व में जदयू विधायक एवं नीतीश कुमार के खिलाफ बगावती तेवर अपनाने वाले रवीन्द्र राय को हराया. कभी नीतीश के नजदीकी कहे जाने वाले और हम उम्मीदवार वृषिण पटेल भी राजकिशोर सिंह के हाथों हार गये. लालगंज में दबंग चेहरा रखने वाले विजय कुमार उर्फ मुन्ना शुक्ला इस बार महागठबंधन की लहर में भी अपने आप को नहीं बचा सके और वैश्य समाज के राजकुमार साह के हाथों हार गये. हाजीपुर सीट अवधेश सिंह ने कांग्रेस के जगरनाथ राय को हरा कर अपनी प्रतिष्ठा बचायी. राजापाकर सीट (सु.) शिवचन्द्र राम ने लोजपा नेता रामनाथ रमन को शिकस्त देकर हथिया ली. वहीं, पातेपुर (सु.)पर इलटफेर करते हुए प्रेमा चौधरी ने भाजपा विधायक महेन्द्र बैठा को पराजित किया वहीं महनार सीट पर जनता ने नया चेहरा उमेश कुशवाहा को चुना. *– नसीम रबानी*

गोपालगंज

लालू का चला जादू
छह में से चार सीटों पर महागठबंधन का हुआ कब्जा

जिले की छह विधानसभा सीटों में से चार सीटें जीत कर महागठबंधन ने राजग को तगड़ा झटका दिया है. भाजपा की झोली में दो सीटें आयी है. हालांकि पार्टी स्तर पर भाजपा और जदयू दोनों को पिछले विधानसभा चुनाव से एक एक सीट का नुकसान उठाना पड़ा है. पिछले विधान सभा चुनाव में भाजपा को तीन तथा जदयू को तीन सीटें मिली थीं. लेकिन इस बार इन दोनों को दो दो सीटें मिली है. इस चुनाव में राजद और कांग्रेस को फायदा हुआ है.

अखिलेश मिश्र
feedback@chauthiduniya.com

लालूप्रसाद के गृह जिला गोपालगंज में महागठबंधन ने धमाकेदार जीत दर्ज की है. जिले की छह विधानसभा सीटों में से चार सीटें जीत कर महागठबंधन ने राजग को तगड़ा झटका दिया है. भाजपा की झोली में दो सीटें आयी हैं. हालांकि पार्टी स्तर पर भाजपा और जदयू दोनों को पिछले विधानसभा चुनाव से एक एक सीट का नुकसान उठाना पड़ा है. पिछले विधान सभा चुनाव में भाजपा को तीन तथा जदयू को तीन सीटें मिली थी. लेकिन इस बार इन दोनों को दो दो सीटें मिली हैं. इस चुनाव में राजद और कांग्रेस को फायदा हुआ है. राजद तथा कांग्रेस ने एक एक सीट पर जीत दर्ज की है. 8 नवंबर को विस्कोमान भवन में सभी छह सीटों को लेकर मतगणना शुरू होने के साथ ही सभी सीटों पर कांटे की टक्कर रही. हालांकि जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ती गया यह साफ दिखने लगा कि हथुआ विधानसभा सीट पर जदयू प्रत्याशी रामसेवक सिंह तथा बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी बड़े अंतर से जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं. शाम चार बजे जब परिणाम सामने आया तो दोनों ने अपने अपने प्रतिद्वंदी को बड़े अंतर से हराकर जीत दर्ज की. हथुआ विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी रामसेवक सिंह ने अपने निकटतम प्रत्याशी हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के महाचंद्र प्रसाद को 22984 वोट से हरा कर जीत दर्ज किया.

रामसेवक सिंह को 57917 वोट तथा महाचंद्र प्रसाद सिंह को 34933 वोट मिला. तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह रहे. इन्हें 32959 वोट मिला. बैकुंठपुर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने जदयू प्रत्याशी मंजीत कुमार सिंह को 14229 वोट से हराया. मिथिलेश तिवारी को 55950 तथा मंजीत कुमार सिंह को 41721 वोट मिला. तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी मनोरमा देवी रहीं. इन्हें 36530 वोट मिले. हालांकि इन दो सीटों के अलावे भोरे विधानसभा सीट, गोपालगंज विधानसभा, कुचायकोट विधानसभा और बरौली विधानसभा सीटों पर कड़ी टक्कर रही. भोरे विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी इंद्रदेव मांझी तथा कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल कुमार के बीच दस राउंड तक कड़ा मुकाबला हुआ. बाद में कांग्रेस प्रत्याशी की बढ़त बढ़ती चली गयी और कांग्रेस

मो. नेमतुल्ला
अनिल राम
मिथिलेश तिवारी
पप्पू पांडेय
राम सेवक सिंह
सुभाष सिंह

प्रत्याशी अनिल कुमार ने भाजपा प्रत्याशी इंद्रदेव मांझी को 14871 वोट से हरा कर जीत दर्ज किया. अनिल कुमार को 74365 तथा इंद्रदेव मांझी को 59494 वोट मिले. गोपालगंज विधानसभा में भी भाजपा व राजद में कड़ी टक्कर रही. जिसमें अंतिम कुछ राउंड में भाजपा प्रत्याशी सुभाष सिंह ने बढ़त लेते हुए राजद प्रत्याशी रेयाजुल हक उर्फ राजू को 4960 वोट से हरा कर जीत दर्ज किया. सुभाष सिंह को 77853 वोट मिले. जबकि रेयाजुल हक को 72893 वोट मिला. कुचायकोट विधानसभा में 22 राउंड तक चले मतगणना के बाद जदयू प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार पाण्डेय उर्फ पप्पू पाण्डेय ने लोजपा प्रत्याशी काली प्रसाद पाण्डेय को 3562 वोट से हरा कर जीत दर्ज किया. अमरेंद्र कुमार पाण्डेय को 72224 वोट तथा काली प्रसाद पाण्डेय को 68662 वोट मिले. सबसे अधिक कांटे की टक्कर बरौली विधानसभा में देखने को मिली. यहां अंतिम राउंड में राजद प्रत्याशी मोहम्मद नेमतुल्ला ने भाजपा प्रत्याशी रामप्रवेश राय को 357 वोट से हरा कर जीत दर्ज किया. मोहम्मद नेमतुल्ल को 61211 वोट तथा रामप्रवेश राय को 60854 वोट मिले.

जनता ने बाहरी उम्मीदवार को नकारा

विधानसभा चुनाव में जनता ने बाहरी उम्मीदवारों को नकार दिया है.जो नेता बाहर से चुनाव लड़ने आए थे, उल्टे पांव वापस चले गए. चुनाव के दौरान भी बाहरी उम्मीदवार होना मुद्दा बना रहा. हथुआ विधान सभा से डॉ. महाचन्द्र सिंह को हम ने अपना प्रत्याशी बनाया. वे अचानक नामांकन के समय आए और क्षेत्र में प्रचार करना शुरू कर किया. प्रचार के दौरान से विरोधियों ने उन्हें बाहरी होने का नारा देना शुरू किया जो चुनाव के दिन तक यह नारा गूंजते रहा. भाजपा से टिकट नहीं मिलने से नाराज राजेश कुमार सिंह निर्दलीय मैदान में उतर आए. राजेश ने बाहरी का नारा देकर वोट मांगा. यही नारा जदयू प्रत्याशी रामसेवक सिंह ने भी दिया और अपने मकसद में कामयाब रहे. जेडीयू प्रत्याशी रामसेवक सिंह को 57 हजार 917 मत मिले प्रतिद्वंदी हम प्रत्याशी डॉ. महाचन्द्र सिंह को 34 हजार 933 मत मिले जबकि निर्दलीय प्रत्याशी राजेश कुमार सिंह को 32 हजार 959 मत मिले. इस प्रकार जेडीयू प्रत्याशी रामसेवक सिंह ने हम प्रत्याशी डॉ महाचन्द्र सिंह को 22 हजार 984 मतों से हराया.■

पुरबिया तान से गुलज़ार हुई शाम

हिमांशु त्रिपाठी
feedback@chauthiduniya.com

आर के पुरम स्थित दिल्ली तमिल संगम में पूरबी स्वर संगम 2015 का आयोजन पूर्वांचल विकास संघ के द्वारा किया गया. इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि स्थानीय संसद मीनाक्षी लेखी थीं. जिन्होंने दीप प्रज्जवलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की. इस कार्यक्रम में स्थानीय निगम पार्षद सतेंद्र सिंह राणा भी मौजूद थे. पूर्वांचल के मशहूर भोजपुरी गायक विष्णु ओझा ने अपने सुरीले गीतों के साथ कार्यक्रम में शमां बांध दिया. उनके अलावा प्रिया शर्मा, विमल भोपुरिया और रवि तिवारी जैसे अन्य कलाकारों ने भी भोजपुरी लोक गीत प्रस्तुत किए.

इस आयोजन में सम्पूर्ण परिवर्तन नाम के हिन्दी अखबार का भी विमोचन किया गया. जिसके संपादक सतीश मुखिया हैं. इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक व पूर्वांचल विकास संघ के अध्यक्ष रवि तिवारी तथा उनके साथ रेखा पाण्डेय, डी. के. दुबे, रणविजय पाण्डेय, अनिल दुबे व और गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे .■

पृष्ठ 17 का शेष

सहयोगी दल भाजपा के सिर फोड़ रहे हैं हार का ठीकरा

भाजपा बड़ी पार्टी है इसलिए इसे इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा पर सहयोगी दलों को इसका खामियाजा चुनाव प्रचार में भुगतना पड़ा. खासकर पहले और दूसरे चरण के प्रत्याशियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. उल्लेखनीय है कि पहले और दूसरे चरण में महागठबंधन ने भारी बढ़त हासिल की है. भाजपा नेता कहते हैं कि टिकटों का बंटवारा रणनीति के तहत समय पर ही किया गया. महागठबंधन के टिकट भी लगभग इसी समय बांटे गए. इसलिए यह कोई वजह चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए नहीं हो सकती है. हम के नेता कहते हैं कि नेता को सामने रखकर चुनाव न लड़ने की भाजपा की रणनीति भी गलत साबित हुई. अगर नीतीश के सामने एनडीए का भी कोई चेहरा होता तो इसका प्रभाव वोटरों पर जरूर पड़ता. लेकिन वोटरों को लगा कि हम वोट किसे दे रहे हैं यह मालूम ही नहीं हो रहा है.

मुख्यमंत्री के चक्कर में कहीं एनडीए के लोग लड़ न जाएं और हमारा वोट बर्बाद न हो जाए यह भावना भी वोटरों के दिलों में थी. भाजपा के नेता इसे बेकार का तर्क दे रहे हैं. वह कहते हैं कि भाजपा कई राज्यों में बिना नेता के नाम के लड़ी है और सफल भी रही है. सहयोगी दलों का यह आरोप भी है कि प्रचार अभियान में समन्वय का घोर अभाव रहा और यह तय करने में भारी गलती हुई कि किस विधानसभा क्षेत्र में किस नेता के जाने की उपयोगिता है.

इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जिन क्षेत्रों में जिस सामाजिक समीकरण को संदेश देना था वहां उनके नेता पहुंच ही नहीं पाए. जबकि महागठबंधन ने इस पहलू का पूरा ध्यान रखा. सहयोगी दलों का कहना कि अभी तो प्रारंभिक चर्चा हुई है. छठ के बाद विस्तार से हार के कारणों की समीक्षा होगी तो बहुत सारी बातें निकलकर सामने आयेंगी. लेकिन इतना तय है कि हमारा संघर्ष जारी रहेगा. दूसरी तरफ भाजपा नेता सुधीर शर्मा कहते हैं कि हार जीत तो लगी ही रहती है पर भाजपा अपने नीति और कार्यक्रम को लेकर बहुत ही स्पष्ट रहती है. बिहार की जनता का प्यार भाजपा को मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा. हमसे कहां गलती हुई इसकी हमलोग समीक्षा कर रहे हैं. हम समीक्षा के बाद अपनी गलतियों से सीखेंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे.■

feedback@chauthiduniya.com

सीवान

एनडीए पर भारी रहा महागठबंधन का चुनावी दांव

वाल्मीकि कुमार

डीएनए, आरक्षण, बीफ, विकास जैसे अन्य मसलों को चुनावी मुददा बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव में शोर मचाया गया. राजनीतिक दल के नेताओं ने चुनावी सभाओं में अपनी ओर से एक दूसरे पर किसी भी प्रकार के आरोप व प्रत्यारोप से परहेज नहीं किया. एनडीए से लेकर महागठबंधन तक की सभाओं में जमीनी समस्या के निदान के जिक्र की जगह व्यापक स्तर पर नेताओं पर चुनावी वाणों की बरसात अंततः जारी रही. मगर चुनाव में एनडीए नेताओं की तमाम बातों को एक सिरे से खारिज किया गया है. नतीजा है कि एनडीए से भाजपा ने सीतामढ़ी जिले के बथनाहा व परिहार सीट पर ही अपना कब्जा बरकरार रखने में सफलता पायी है. जबकि महागठबंधन ने राजद की 3 क्रमशः सुरसंड, सीतामढ़ी, रून्नीसैदपुर, जदयू की 2 क्रमशः बेलसंड व बाजपट्टी और कांग्रेस की 1 रीगा सीट पर कब्जा कर सफलता पायी है.

23- रीगा विधानसभा सीट को भाजपा के कब्जे से अबकी बार महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार टुन्ना ने झटक ली है. स्थानीय विधायक सह भाजपा प्रत्याशी मोतीलाल प्रसाद को मशक्कत के बाद 56 हजार 55 मत मिला. जबकि महागठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी अमित कुमार टुन्ना को 78 हजार 807 मत प्राप्त हुआ. 24 – बथनाहा विधानसभा सीट से स्थानीय विधायक सह भाजपा प्रत्याशी दिनकर राम अपना कब्जा बरकरार रखने में सफल रहे. एनडीए के भाजपा प्रत्याशी दिनकर राम को 74 हजार 347 मत मिला. जबकि महागठबंधन से कांग्रेस के सुरेंद्र राम को महज 54 हजार 173 मत मिला. 25 – परिहार विधानसभा सीट पर एनडीए से भाजपा के पूर्व विधायक राम नरेश प्रसाद यादव की पत्नी गायत्री यादव गठबंधन की लाज बचाने में कामयाब रहीं. गायत्री को 66 हजार 388 मत मिले. जबकि महागठबंधन से राजद के प्रदेष अध्यक्ष डॉ रामचंद्र पूर्वे को 62 हजार 371 मत ही मिल सका. 26 – सुरसंड विधानसभा सीट से स्थानीय विधायक सह मंत्री शाहिद अली खान चौथा पायदान पर 13 हजार 954 मत ही लेकर अटक गये. जबकि महागठबंधन से राजद के सैयद अबु दोजाना ने 52 हजार 857 मत लाकर विजयी रहे. इस सीट से दूसरे स्थान पर जेल की सलाखों में बंद निर्दलीय प्रत्याशी अमित कुमार उर्फ माधव

चौधरी को 29 हजार 963 और तीसरा स्थान पर रहे निर्दलीय पप्पू कुमार चौधरी को 15 हजार 662 मत मिला. 27 – बाजपट्टी विधानसभा सीट से महागठबंधन की जदयू प्रत्याशी डॉ रंजूगीता 67 हजार 194 मत के साथ दूसरी बार विजयी रहीं. जबकि एनडीए से रालोसपा की रेखा कुमारी 50 हजार 248 मत लाकर दूसरे स्थान पर रहीं. तीसरे स्थान पर निर्दलीय प्रत्याशी रवींद्र कुमार शाही को 8 हजार 33 मत मिले. 28 – सीतामढ़ी विधानसभा सीट से अबकी बार महागठबंधन के राजद प्रत्याशी सुनील कुमार ने एनडीए के भाजपा से सीट छीनने में कामयाबी पायी है. इस सीट से एनडीए के भाजपा प्रत्याशी सह पूर्व पर्यटन मंत्री सुनील कुमार पिंटू को 66 हजार 53 मत मिला. जबकि महागठबंधन के राजद प्रत्याशी सुनील कुमार को 80 हजार 827 मत मिले. इस सीट से तीसरे स्थान पर लोजपा की पूर्व विधायक सह निर्दलीय प्रत्याशी नगीना देवी को 3 हजार 613 मत मिले. 29 – रुन्नीसैदपुर सीट से महागठबंधन की राजद प्रत्याशी मंगीता देवी 55 हजार 699 मत लाकर विजयी रही. दूसरे स्थान पर एनडीए से रालोसपा प्रत्याशी पंकज कुमार मिश्रा को 41 हजार 489 मत मिला. जबकि तीसरे स्थान पर स्थानीय विधायक सह समाजवादी पार्टी प्रत्याशी गुड्डी देवी को 16 हजार 38 मत मिला. 30 – बेलसंड विधानसभा सीट पर महागठबंधन से जदयू की स्थानीय विधायक सुनीता सिंह चौहान ने अपना कब्जा दूसरी बार बरकरार रखने में सफल रही. सुनीता सिंह को 33 हजार 622 मत मिला. जबकि एनडीए से लोजपा प्रत्याशी मो. नसीर अहमद को 28 हजार 102 मत मिला. तीसरे स्थान पर भाजपा के बागी पूर्व विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद को 11 हजार 334 मत से ही संतोष करना पड़ा. इधर शिवहर विधानसभा सीट पर महागठबंधन से जदयू प्रत्याशी स्थानीय विधायक सरफुद्दीन ने दुबारा अपना कब्जा बनाये रखने में सफलता पायी है. सरफुद्दीन को 44 हजार 576 मत मिले तो एनडीए से हम प्रत्याशी लवली आनंद को 44 हजार 115 मत मिला. जबकि 22 हजार 309 मत पाकर निर्दलीय प्रत्याशी ठाकुर रत्नाकर राणा तीसरे स्थान पर रहे. इस प्रकार अगर देखा जाये तो विधानसभा चुनाव में एनडीए के भाजपा समेत गठबंधन दल के नेताओं की तमाम चुनावी कसरत धरी की धरी रह गयी है. एनडीए गठबंधन के रालोसपा व लोजपा प्रत्याशी को 3 में से किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिल सकी है. महागठबंधन ने जहां इस जीत को जनता की सजगता का नतीजा बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, वहीं एनडीए को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है. चल रही चर्चाओं पर यकीन करें तो एनडीए के अंदर का लंबे अर्से से चल रहा विवाद इस चुनाव में परिणाम के रूप में सामने देखने को मिल रहा है. चुनाव नतीजा आने के बाद अब एनडीए की मजबूती को लेकर सीतामढ़ी जिले में अगली रणनीति क्या होगी इस पर सभी की नजर टीकी है.■

feedback@chauthiduniya.com

सहरसा में भाजपा चारो खाने चित्त

संजय सोनी

बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में सहरसा सीट भाजपा के कब्जे में होने के बावजूद भी पार्टी यहां जोर का गच्चा खा गई. इस सीट से राजद के उम्मीदवार अरुण कुमार यादव ने 39 हजार 206 मतों के भारी अंतर से भाजपा के प्रत्याशी निवर्तमान विधायक आलोक रंजन को पराजित करने में कामयाबी हासिल की. जबकि बसपा, जपा, बहुजन मुक्ति पार्टी, माकपा जैसे दलों ने भी भाजपा के वोट को ही बर्बाद करने का काम किया है. वैसे सभी दलों के पराजित प्रत्याशियों की दलील है कि जनता के मिजाज ने कैडर को भी पीछे छोड़ दिया.

भाजपा के प्रदेश नेतृत्व अगर चेहरा बदल कर किसी को भी मैदान में उतारा होता तो पराजय का मुंह कम से कम इस सीट से नहीं देखना पड़ता. वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव से ही जिले में पार्टी के अंदर संगठन की मनमानी और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा का जहर घुलने लगा था. संगठन का जहर घुलते-घुलते वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव में अपनी कराममत दिखा गया. कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के कारण ही पार्टी को जिले की चारों सीट सिमरी बख्तियारपुर,सोनवर्षा, महिषी के साथ-साथ सहरसा भी गंवानी पड़ी. चुनाव के दौरान कई अन्य दलों से जुड़े कार्यकर्ताओं व नेताओं का आगमन भी चुनाव परिणाम को प्रभावित करने में मददगार साबित हुआ. राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि भाजपा के निवर्तमान विधायक आलोक रंजन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विचार सबका साथ, सबका विकास से इतर कुछ खास कार्यकर्ताओं व रिश्तेदारों को ही तरजीह देते रहे. खुद का विकास, रिश्तेदारों के साथ ही पंचवर्ष का आनंद उठाया. चर्चा यह भी बनी रही कि नामांकन में दायर शपथ पत्र कानूनी रूप से तो वैध है, पर आम जनता के बीच महज झूठ का पुलिंदा ही दिख रहा है. 2009 से 2015 तक

के पांच वर्ष में अर्जित अकूत सम्पति से खुद को बचाने के लिए अपने भाई सहित परिवार के नाम पर ही रखा है. ताकि उनके इस जादूई खेल को कानूनी अमली-जामा पहनाया नहीं जा सके. कुछ बातों को कानून की नजरों से अलग रखा जा सकता है, पर समाज से अलग नहीं रखा जा सकता. चुनाव के वक्त भी पार्टी व विधायक से रूठे व असंतुष्ट कार्यकर्ताओं का न तो मान-मनोव्वल किया गया और न ही चुनाव में किसी भी प्रकार की महती जिम्मेवारी सौंपी गयी. कई क्षेत्रों में असंतुष्ट

कार्यकर्ताओं ने तो नोटा का ही बटन दबाना बेहतर समझा. सहरसा विधानसभा की आग ने ही जिले के तीन अन्य विधानसभा क्षेत्र से खड़े घटक दलों की जीत को भी हार में तब्दील कर दिया. इस चुनाव में टिकट वितरण के पूर्व आरएसएस, विहिप, धर्म जागरण परिषद सहित सतही कार्यकर्ताओं की राय पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाता तो शायद विपरीत परिस्थिति में भी इस सीट को बचाया जा सकता था. लेकिन कहा गया है विनाशकाले विपरित बुद्धि. मत मारी गयी और प्रदेश संगठन ने भी अपनी हेकड़ी दिखाकर निवर्तमान विधायक आलोक रंजन को टिकट दिया, जिसका खामियाजा हार के रूप में भुगतना पड़ा. कोसी क्षेत्र के 13 सीटों का गणित सहरसा सीट से ही जुड़ा रहा. सूत्रों का यह भी कहना है आईबी के रिपोर्ट में भी इस सीट सहित कई सीटों पर पराजय का कारण प्रत्याशी का गलत चयन ही बताया गया है.

आंकड़ों पर गौर करें तो राजद के उम्मीदवार अरुण यादव को एक लाख 28 सौ 50 और भाजपा के आलोक रंजन को 63 हजार 644 मत प्राप्त हुआ. हालांकि वर्ष 2009 के विधानसभा चुनाव में प्राप्त मतों पर गौर किया जाय तो भाजपा को प्राप्त वोट 55 हजार 687 यानी इस बार 7957 वोट का इजाफा ही हुआ वहीं पिछले बार राजद उम्मीदवार अरूण यादव महज 7979 वोट के अंतर से ही पराजित हुए थे. इस बार भाजपा उम्मीदवार खुद के ओवर कान्फीडेंस और क्षेत्र के जनता की घोर नाराजगी के कारण हार का सामना करना पड़ा. यही वजह रहा कि राजद उम्मीदवार को 39 हजार 206 मतों के अंतर का सेहरा बांध कर विधानसभा पहुंचे. जबकि मैदान में 14 प्रत्याशी दल व निर्दल के मैदान में खड़े थे. सबों की किस्मत को वोटरों ने लॉक कर राजद के पुराने व वरीय कार्यकर्ता अरूण यादव को विजयी दिया. अब सहरसा में भाजपा के पास एक ही विकल्प बचा है कि संगठन को फिर से किसी तजुर्बेकार के हाथों में कमान सौंपे.जो जनता के दुःख-दर्द में हाथ बटा सके और स्थानीय समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष कर सके.■

feedback@chauthiduniya.com

सीवान

चौकाने वाला रहा सीवान का चुनाव परिणाम

नेता डाल-डाल तो मतदाता पात-पात वाली कहावत इस बार चरितार्थ हो गई, जो भी उम्मीदवार जाता था, मतदाता अपनी बातों के भंवरजाल में फंसाकर उसको जीताकर भेज देता था. जिसको लेकर सभी अपने-अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन सच्चाई का पर्दा आठ नवंबर के पूर्वाह्न से धीरे-धीरे उठना शुरू हुआ जो आपराह्न लगभग दो बजे तक साफ हो गया. पूरे बिहार की नजरें अगर कहीं टिकी थी तो वह था देशरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद व मौलाना मजरूलहक का सीवान. जहां आठ विधान सभा की सीटों का परिणाम आना था. इन आठों सीटों पर भाजपा व महागठबंधन द्वारा अपना-अपना उम्मीदवार तो दिया ही गया था इसके अलावे अन्य राजनीतिक पार्टियों तथा निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे.

शम्भू प्रसाद अभय/सुरेन्द्र कुमार

आखिरकार लंबे इंतजार के बाद विधान सभा चुनाव 2015 का परिणाम आ ही गया, जिसने कई लोगों की आशा व उम्मीद के विपरीत होकर एक अलग मिसाल कायम कर दी. जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी. जिसका मुख्य कारण था मतदाताओं की चुप्पी. नेता डाल-डाल तो मतदाता पात-पात वाली कहावत इस बार चरितार्थ हो गई, जो भी उम्मीदवार जाता था, मतदाता अपनी बातों के भंवरजाल में फंसाकर उसको जीताकर भेज देता था. जिसको लेकर सभी अपने-अपनी जीत के प्रति आश्वस्त थे, लेकिन सच्चाई का पर्दा आठ नवंबर के पूर्वाह्न से धीरे-धीरे उठना शुरू हुआ जो आपराह्न लगभग दो बजे तक साफ हो गया. पूरे बिहार की नजरें अगर कहीं टिकी थी तो वह था देषरत्न डॉ. राजेन्द्र प्रसाद व मौलाना मजरूलहक का सीवान. जहां आठ विधान सभा की सीटों का परिणाम आना था. इन आठों सीटों पर भाजपा व महागठबंधन द्वारा अपना-अपना उम्मीदवार तो दिया ही गया था इसके अलावे अन्य राजनीतिक पार्टियों तथा निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे. सभी ने जोर आजमाईश की लेकिन परिणाम जो आया वह सभी को चित्त कर गया.

अगर हम जिक्र करें सीवान सदर विधान सभा सीट की तो यहां से एक बार पुनः भाजपा के निवर्तमान विधायक व्यासदेव प्रसाद विजयी हुए. जिन्हें 55156 मत मिला, वहीं महागठबंधन के उम्मीदवार बबलू चौहान को 51622 मत ही मिला. जदयू से टिकट नहीं मिलने के कारण बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़े, पूर्व अवध बिहारी चौधरी को 28450 मत ही मिल सका. वहीं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के गृह विधान सभा क्षेत्र जीरादेई पर अगर हम नजर डालें तो यहां से जदयू के उम्मीदवार रमेश सिंह कुशवाहा 39674 मत लेकर विजयी हो गए, वहीं निवर्तमान भाजपा विधायक आशा पाठक तीसरे स्थान पर चली गई, जिन्हें 32928 मत ही मिल पाया, जबकि भाकपा(माले) के अमरजीत कुशवाहा 33816 मत लेकर दूसरे स्थान पर रहे. जिले में सर्वाधिक चर्चा का विषय बना रघुनाथपुर विधान सभा क्षेत्र जहां से पूर्व विधान पार्षद सह भाजपा के उम्मीदवार मनोज सिंह व राजद के हरिशंकर यादव के बीच सीधा मुकाबला था, इस लड़ाई में राजद के हरिशंकर यादव 60873 मत लेकर विजयी हो गए, जबकि भाजपा के मनोज सिंह को 50297 मत मिला तथा वे दूसरे स्थान पर रहे, वहीं पूर्व विधायक सह भाकपा(माले) उम्मीदवार अमरनाथ यादव 16711 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे. वहीं दरौली सीट पर लंबे समय तक अपना कब्जा जमाने वाले भाकपा(माले) के पूर्व विधायक सत्यदेव राम इस बार भी 49576 मत लेकर विजयी हो गए, जबकि भाजपा के उम्मीदवार सह निवर्तमान विधायक रामायण मांझी 39992 मत लेकर चुनाव हार गए, वहीं पूर्व विधान पार्षद सह राजद के जिलाध्यक्ष परमात्मा राम राजद के टिकट पर चुनाव लड़े थे, जो 37345 मत लेकर तीसरे स्थान पर रहे.

वहीं दरौंदा विधान सभा सीट पर एक बार पुनः जदयू का कब्जा कायम रहा. जदयू के निवर्तमान विधायक सह जदयू की उम्मीदवार कविता सिंह 66255 मत लेकर एक पुनः विजयी हो गई. जबकि पूर्व सांसद उमाशंकर सिंह के पुत्र सह भाजपा के उम्मीदवार जितेन्द्र स्वामी को 53033 मत ही मिल पाया. वहीं बड़हरिया विधान सभा सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार सह निवर्तमान विधायक श्यामबहादुर सिंह 65168 वोट लेकर चुनाव जीत गए. जबकि लोजपा उम्मीदवार बच्चा

पांडेय 50585 मत लेकर दूसरे स्थान पर रहे. वहीं गोरयाकोठी विस सीट से राजद के उम्मीदवार सह पूर्व विधायक सत्यदेव प्रसाद सिह 65072 मत लेकर विजयी हुए. जबकि भजपा के उम्मीदवार सह पूर्व विधायक चुन्नु बाबू के पुत्र देवेश कान्त सिंह 52205 मत लेकर दूसरे स्थान पर रहे. वहीं महाराजगंज विधान सभा सीट पर जदयू के हेमनरायण साह 68459 मत लेकर विजयी हो गए. जबकि निवर्तमान भाजपा विधायक कुमार देवरंजन 48167 मत लेकर दूसरे स्थान पर रहे. इस प्रकार सीवान के आठ विधान सभा सीटों में से दरौली पर भाकपा माले, सीवान सदर पर भाजपा, तथा बाकी छः सीटों पर महाठबंधन के उम्मीदवार विजयी हुए. अब चारों तरफ चुनावी चर्चा समाप्त हो गई है, सबकी नजरें सरकार के विकास कार्यों पर टिकी है.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी शिवहर

जातीय गोलबंदी ने बिगाड़ा चुनावी समीकरण

कुल मिलाकर सीतामढ़ी व शिवहर जिले में पार्टी से अधिक जातीय गोलबंदी की चर्चा जोरों पर है. महागठबंधन की ओर से जहां बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से लेकर विकास, आरक्षण व शैतान से ब्रह्म पिशाच तक का मसला चुनावी सभाओं में गूंजता रहा, वहीं एनडीए की सभाओं में डीएनए, जंगलराज से थ्री इडीयट तक का पाठ मतदाताओं को रटाने का असफल प्रयास किया जाता रहा. मगर अबकी बार के चुनाव में जातीय गोलबंदी ने एनडीए को दोनों ही जिलों में एक दायरे से बाहर निकलने तक का रास्ता नहीं दिया. जातिगत ठेकेदार व वोटों के दलाल तक की तमाम कवायद धरी की धरी रह गयी. अब देखना है कि बिहार के एनडीए नेता किस प्रकार से दोनों जिलों में पार्टी गठबंधन को संजीवनी पिला पाते हैं.

वाल्मीकि कुमार

जाति – पार्टी से लेकर आरोप – प्रत्यारोप की चुनावी सुनामी के बाद संपन्न विधानसभा चुनाव का नतीज आम जनता के बीच चर्चा के कई पहलू छोड़ गया है. कहीं जातीय गोलबंदी तो कहीं पार्टी के मजबूत आधार को चर्चा का केंद्र बनाया जाने लगा है. संपन्न चुनाव को करीब से अगर देखा जाये तो कई तथ्य सामने आ रहे हैं. इस चुनाव के मुख्य केंद्र में रहे प्रमुख राजनीतिक दलों को भी लोग अब अलग नजरीये से देखने लगे हैं. एक ओर भारी हुंकार भरने वाली एनडीए के भाजपा के सिरमौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी वादा तो दूसरी ओर एनडीए के चुनाव प्रचार और पार्टी नेताओं के बयानों का सीधा मुकाबला करने वाले महागठबंधन नेताओं की जुबान ने चुनावी महासमर की दिशा बदल दी है. अब सीधा सा सवाल सामने आता है कि सीतामढ़ी जिले में 8 में से 4 सीट पर जहां एनडीए के भाजपा का कब्जा था, उसे अबकी बार एनडीए बरकरार रखने में नाकाम कैसे रही? दूसरी ओर कौन सी ऐसी जादुई छड़ी महागठबंधन के हाथ लग गयी, जिसके बूते महागठबंधन ने 8 में से 6 सीट पर कब्जा जमाने में सफलता प्राप्त की है. इन सवालों को लेकर अब चौक–चौराहों से गांव की गलियों तक मंथन का दौर शुरू हो गया है. चल रही चर्चाओं पर अगर यकीन करें तो एनडीए की पराजय का कारण पार्टी के अंदर लंबे अर्से से चल रहा अंर्तकलह और टिकट बंटवारे में गठबंधन नेताओं की मनमानी से उपजे आक्रोश का होना बताया जाता है. वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की जीत के लिए नमो विरोधी मुहिम और जातीय गोलबंदी की सफलता बताया जाता है. अब विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति पर एक नजर डालने की जरूरत है.

23 – रीगा विधानसभा सीट से अबकी बार कुल डेढ़ दर्जन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था. इनमें प्रमुख रूप से एनडीए ने वैश्य बिरादरी के स्थानीय भाजपा विधायक मोतिलाल प्रसाद तो महागठबंधन ने बतौर कांग्रेस प्रत्याशी राजपूत बिरादरी के अमित कुमार टुन्ना को चुनावी समर में उतारा था. वैश्य बाहुल्य मानी गई इस सीट पर अबकी बार दोनों गठबंधन के बीच सीधे मुकाबले में महागठबंधन प्रत्याशी को भारी बहुमत से सफलता मिली. इसका कारण स्थानीय भाजपा विधायक के खिलाफ बना माहौल और कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में मतदाताओं की गोलबंदी होना बताया जाता है. 24 – बथनाहा विधानसभा क्षेत्र से अबकी बार कुल एक दर्जन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था. इस सीट पर भी एनडीए व महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला रहा. एनडीए ने स्थानीय भाजपा विधायक दिनकर राम तो महागठबंधन ने कांग्रेस की टिकट पर सुरेंद्र राम को चुनाव मैदान में उतारा था. मगर क्षेत्र के मतदाताओं ने स्थानीय भाजपा विधायक की लगातार क्षेत्र में मौजूदगी को तरजीह देकर एक और मौका देने का निर्णय लिया. नतीजा हुआ कि ऐन मौके पर क्षेत्र में पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी को पराजय का सामना करना पड़ा. 25– परिहार विधानसभा सीट से अबकी बार कुल 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था. इस सीट से एनडीए ने यादव बिरादरी के पूर्व भाजपा विधायक राम नरेश प्रसाद यादव की पत्नी गायत्री देवी को बतौर भाजपा प्रत्याशी तो महागठबंधन ने वैश्य बिरादरी के प्रदेश राजद अध्यक्ष डॉ रामचंद्र पूर्वे को बतौर राजद प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा था. इस सीट से इन दो प्रमुख प्रत्याशियों के बीच कांग्रेस के बागी अल्पसंख्यक बिरादरी के मो. शम्स शाहनवाज, जन अधिकार पार्टी की यादव बिरादरी की सरिता यादव व बसपा प्रत्याशी नीलम यादव ने चुनावी गणित को उलट कर महागठबंधन को पराजय की राह दिखा दी. इस सीट पर एमवाई समीकरण धरा का धरा गया. नतीजा हुआ कि महागठबंधन प्रत्याशी को जीत नसीब नहीं हो सकी.

26 – सुरसंड विधानसभा सीट से अबकी बार कुल डेढ़ दर्जन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था. इनमें एनडीए ने हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा की टिकट पर अल्पसंख्यक बिरादरी के स्थानीय विधायक शाहिद अली खान तो महागठबंधन ने भी अल्पसंख्यक बिरादरी के ही सैयद अबु दोजाना को बतौर राजद प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा था. बताया जाता है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच इस क्षेत्र में सीधा मुकाबला के किया था. इस सीट से एनडीए ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की टिकट पर वैश्य बिरादरी की रेखा कुमारी तो महागठबंधन ने जदयू की टिकट पर यादव बिरादरी की स्थानीय विधायक डॉ रंजूगीता को चुनाव मैदान में उतारा था. एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधे मुकाबले में इस क्षेत्र से रालोसपा के बागी के तौर पर भूमिहार बिरादरी के रवींद्र कुमार शाही ने रालोसपा प्रत्याशी का जहां खेल खराब कर दिया, वहीं महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में सपा का अल्पसंख्यक प्रत्याशी मो अस्फाक के आगमन ने राहत दिला दी. एम–वाई समीकरण में संभावित दरार की तमाम आशंका धरी की धरी रह गयी और महागठबंधन को जीत मिली.

अमित कुमार

रामचंद्र पूर्वे

गुड्डी देवी

लवली आनंद

नगीना देवी

रेखा कुमारी

पंकज कुमार मिश्र

शाहिद अली खान

मोती लाल प्रसाद

सुनील कुमार

संभावना की भूमिहार बिरादरी के निर्दलीय प्रत्याशी अमित कुमार उर्फ माधव चौधरी ने दिशा बदल दी. नतीजा हुआ कि एनडीए विरोधी अल्पसंख्यक मतदाता अंत समय में एम–वाई समीकरण की मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ हो गये. नतीजा हुआ कि महागठबंधन प्रत्याशी का पलड़ा जहां भारी हो गया, वही एनडीए प्रत्याशी को चौथा पायदान पर अटकना पड़ा. दूसरे स्थान पर रहे निर्दलीय अमित कुमार को भी अपने स्वजातीय निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू कुमार चौधरी के कारण सफलता नहीं मिल सकी. महागठबंधन के पक्ष में जातीय गोलबंदी का इस क्षेत्र में आलम रहा कि यादव बिरादरी के राजद के बागी स्थानीय पूर्व विधायक जयनंदन प्रसाद यादव को भी एनडीए विरोधी लहर का खामियाजा भुगतना पडा. 27 – बाजपट्टी विधानसभा क्षेत्र से सर्वाधिक 22 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल

शिवहर जिले की एक मात्र विधानसभा सीट पर एनडीए व महागठबंधन के बीच हुए सीधे मुकाबला में जाति व पार्टीगत समीकरण लगभग समान रहे. महागठबंधन से जदयू की टिकट पर मो. सरफुद्दीन का मुकाबला एनडीए से हम प्रत्याशी राजपूत बिरादरी की पूर्व सांसद लवली आनंद से हुआ. बताया जाता है कि जातीय गोलबंदी नहीं होने के कारण ही एनडीए प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है. चर्चा है कि भाजपा के बागी राजपूत बिरादरी के ठाकुर रत्नाकर राणा ने अगर थोडी नरमी बरती होती तो शिवहर से महागठबंधन की जीत संभव नहीं होती.

28 – सीतामढ़ी विधानसभा सीट से अबकी बार 15 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था. इस सीट से एनडीए ने भाजपा से वैश्य बिरादरी के स्थानीय विधायक सुनील कुमार पिंटू तो महागठबंधन ने कुशवाहा बिरादरी के नये चेहरे सुनील कुमार को बतौर राजद प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा था. एनडीए व महागठबंधन के बीच सीधे चुनावी मुकाबले में इस सीट पर जातीय गोलबंदी ने एनडीए को अबकी बार हार का राह दिखा दिया. चर्चा है कि सीतामढ़ी में एनडीए के अंदर पिछले लोकसभा व नगर परिषद चुनाव के समय से ही आंतरिक कलह चरम पर रही है. विधान परिषद चुनाव के वक्त कलह में और इजाफा हुआ और तब से ही तय माना जाने लगा कि विधानसभा चुनाव में इसका असर पार्टी गठबंधन पर हो सकता है. परंतु एनडीए ने इसे गंभीरता से लेने का प्रयास नहीं किया और न ही स्थानीय विधायक ने इस मामले को कोई तरजीह दी. जब विधानसभा चुनाव के टिकट बंटवारे के दौरान वैश्य बिरादरी की लोजपा की पूर्व विधायक नगीना देवी को बेटिकट कर दिया गया, तब विधायक विरोधी खेमा ने बतौर वैश्य समर्थित प्रत्याशी के रूप में नगीना देवी को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतार दिया. नतीजा हुआ कि भाजपा प्रत्याशी को एक साथ पार्टी व जातिगत विरोध के बीच चुनाव लड़ना पडा. वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के कुशवाहा बिरादरी के राजद प्रत्याशी को एम–वाई समीकरण के साथ ही स्वजातीय मतों का पर्याप्त समर्थन मिल गया. इस मामले में स्थानीय एनडीए के रालोसपा सांसद राम कुमार शर्मा भी जातीय वोटों की गोलबंदी में पूर्णत: विफल रहे. नतीजा हुआ कि एनडीए अपनी सीट को बचाने में विफल रहा. 29 – रुन्नीसैदपुर सीट से अबकी बार कुल 14 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था. एनडीए ने रालोसपा की टिकट पर नया चेहरा भूमिहार बिरादरी का पंकज कुमार मिश्रा तो महागठबंधन ने यादव बिरादरी के पूर्व विधायक स्व. भोला राय की पुत्रावधु मंगीता देवी को बतौर राजद प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा था. जदयू की टिकट पर दो बार विधायक रही गुड्डी देवी को जब गठबंधन ने अचानक बेटिकट कर दिया तब उन्होंने तीसरे मोर्चे का दामन थाम लिया और समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनावी समर में आ धमकीं. एनडीए व महागठबंधन के बीच सीधे मुकाबले के संकेत को धूमिल करते हुए गुड्डी देवी ने चुनावी फिज बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी. नतीजा हुआ कि रून्नीसैदपुर में त्रिकोणीय चुनावी मुकाबले का सामना एनडीए व महागठबंधन प्रत्याशी को करना पड़ा. चल रही चर्चा पर यकीन करें तो इस क्षेत्र में एनडीए विरोधी लहर का आलम रहा कि अंत समय में अल्पसंख्यक सपा मतदाता भी अपना पाला बदल कर महागठबंधन की ओर चल पड़े. नतीजा हुआ कि सपा के तीसरे स्थान पर रहने के साथ ही एनडीए प्रत्याशी को भी पराजय का राह दिखा दी. जबकि महागठबंधन के पक्ष में यादव वोटों की गोलबंदी को स्वजातीय निर्दलीय प्रत्याशी भी तोड़ने में नाकाम रहे. 30 – बेलसंड विधानसभा सीट से इस बार कुल डेढ़ दर्जन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था. एनडीए ने इस सीट से लोजपा की टिकट पर नया चेहरा अल्पसंख्यक बिरादरी के मो नसीर अहमद तो महागठबंधन ने राजपूत बिरादरी की स्थानीय विधायक सुनीता सिंह चौहान को बतौर जदयू प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारा था. इस सीट पर भी एनडीए व महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला हुआ है. चर्चा है कि एनडीए प्रत्याशी के लिए भाजपा के बागी वैश्य बिरादरी के निर्दलीय प्रत्याशी पूर्व विधान पार्षद वैद्यनाथ प्रसाद चुनौती बने. नतीजा हुआ कि महागठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीतने में सफल रहीं. चर्चा यह भी चल रही है कि पूर्व विधान पार्षद को वैश्य बिरादरी का पूर्ण समर्थन मिलने की उम्मीद थी. परंतु बिरादरी के मतदाताओं ने खास मतलब नहीं रखा.

उधर शिवहर जिले के एक मात्र विधानसभा सीट पर एनडीए व महागठबंधन के बीच हुए सीधा मुकाबला में जाति व पार्टीगत समीकरण लगभग समान रहा. महागठबंधन से जदयू की टिकट पर अल्पसंख्यक बिरादरी के स्थानीय विधायक मो सरफुद्दीन का मुकाबला एनडीए से हम प्रत्याशी राजपूत बिरादरी की पूर्व सांसद लवली आनंद से हुआ. बताया जाता है कि जातीय गोलबंदी नहीं होने के कारण ही एनडीए प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा है. चर्चा यह भी है कि भाजपा के बागी राजपूत बिरादरी के ठाकुर रत्नाकर राणा अगर थोडी नरमी बरते होते तो शिवहर से महागठबंधन की जीत संभव नहीं होती.

कुल मिलाकर सीतामढ़ी व शिवहर जिले में पार्टी से अधिक जातीय गोलबंदी की चर्चा जोरों पर है. महागठबंधन की ओर से जहां बिहार को विशेष राज्य के दर्जे से लेकर विकास, आरक्षण व शैतान से ब्रह्म पिशाच तक का मसला चुनावी सभाओं में गूंजता रहा, वहीं एनडीए की सभाओं में डीएनए, जंगलराज से थ्री इडीयट तक का पाठ मतदाताओं को रटाने का असफल प्रयास किया जाता रहा. मगर अबकी बार के चुनाव में जातीय गोलबंदी ने एनडीए को दोनों ही जिलों में एक दायरे से बाहर निकलने तक का रास्ता नहीं दिया. जातिगत ठेकेदार व वोटों के दलाल तक की तमाम कवायद धरी की धरी रह गयी. अब देखना है कि बिहार के एनडीए नेता किस प्रकार से दोनों जिलों में पार्टी गठबंधन को संजीवनी पिला पाते हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार
23 नवंबर–29 नवंबर, 2015
Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

बिहार विधानसभा चुनाव में न्यूट्रल रहे नक्सली संगठन

अब यूपी में नक्सलियों को साधने की कोशिश

साम्प्रदायिकता से लड़ने के नाम पर पार्टियां ले रहीं नक्सलियों का समर्थन

तटस्थ समर्थन के एवज में नक्सली संगठनों को मिल रहा है अकूत धन

प्रभात रंजन दीन

नक्सलवादियों को अपने पक्ष में कर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के मतदाताओं का वोट हासिल करने के जिस तरह के प्रयास बिहार के विधानसभा चुनाव में हुए, उसी तरह उत्तर प्रदेश के भी नक्सल प्रभावित इलाकों में सक्रिय नक्सलियों को नरम कर उनके समर्थकों का वोट हासिल करने की पहल हो रही है. अति वामपंथ की विचारधारा पर चलने वाले नक्सली वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ हैं, लिहाजा उन्हें भाजपा के खिलाफ न्यूट्रल करना आसान साबित हो रहा है. बिहार में सक्रिय माओवादी संगठनों के चुनाव बहिष्कार के नारे और हिंसा की आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं और नक्सल प्रभावित इलाकों में महागठबंधन के पक्ष में खूब वोट पड़े. नक्सलियों को मैनेज करने की आधिकारिक पुष्टि तो कोई दल नहीं कर सकता, लेकिन नक्सल कैडरों और नक्सल प्रभावित इलाकों के लोगों से यह बात सुनी जा सकती है. बिहार चुनाव के बाद आंध्र प्रदेश में गिरफ्तार हुए नक्सली कमांडर गोविंद यादव ने भी इस बारे में खुफिया एजेंसियों को काफी कुछ जानकारी दी है. आपको याद ही होगा कि पश्चिम बंगाल में भी चुनाव में माओवादियों का समर्थन लेने के मामले में ममता बनर्जी का नाम सुर्खियों में आ चुका है. कांग्रेस पर भी यह आरोप लग चुका है. नीतीश–लालू इस मामले में अधिक कूटनीतिक साबित हुए हैं.

बहरहाल, उत्तर प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों और इलाकों में नक्सलियों को नरम करने की कोशिशें उसी समय शुरू हो गई थीं, जब बिहार में चुनाव की तैयारियां चरम पर थीं. तब समाजवादी पार्टी भी महागठबंधन में शरीक थी और चुनावी रणनीतियों के निर्माण में साझीदार थी. उस दरम्यान बिहार में पर्दे के पीछे नक्सलियों को भाजपा के खिलाफ अपने फेवर में लेने की कोशिशें हो रही थीं, तो इधर उत्तर प्रदेश में नक्सलियों के लिए उनके सरल–सुगम आत्मसमर्पण की नीति और उनके पुनर्वास की आलीशान योजना की घोषणा हो रही थी. मुख्यमंत्री अखिलेश ने तब भले ही यह कहा था कि सरकार इस नीति के माध्यम से नक्सलियों के जाल में फंसे युवाओं को फिर से समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास कर रही है, लेकिन असलियत में यह नक्सल–तुष्टिकरण की योजना थी. उत्तर प्रदेश सरकार का आधिकारिक तौर पर यह कहना है कि यह नीति युवाओं को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करते हुए लाभप्रद रोजगार एवं उद्यमशीलता के अवसर उपलब्ध कराकर उनको पुनः हिंसा का मार्ग अपनाने से रोकने के उद्देश्य से लागू की गई है. यूपी सरकार यह भी सफाई देती है कि यह नीति ऐसे आत्मसमर्पणों को हतोत्साहित करती है, जो सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभ लेने और अपना हित साधने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं. बल्कि यह नीति यह भी सुनिश्चित करेगी कि आत्मसमर्पण करने वाला नक्सली गतिविधियों में पुनः शामिल न हो सके और उसे रोजगार के बेहतर विकल्प मुहैया हो सकें. उत्तर प्रदेश सरकार ने नक्सलियों के लिए जो नीति बनाई है, उसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को पुनर्वास शिविर में भेजा जाएगा. कैंप में रहने की अधिकतम अवधि तीन साल होगी और इस अवधि में उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी. कैंप में रहने के दौरान नक्सलियों को चार हजार रुपये का मासिक मानदेय भी दिया जाएगा. इस योजना के लिए धनराशि का प्रावधान भी कर दिया गया है. दिलचस्प यह है कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास पर होने वाला खर्च शत–प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा उत्तर प्रदेश सरकार पर काबिज समाजवादी पार्टी उठाने जा रही है. बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी 2017 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई थीं. तभी प्रदेश की खुफिया एजेंसी की विभिन्न स्थानीय इकाइयों (एलआईयू) से अद्यतन रिपोर्ट मंगाई गई थी. खुफिया रिपोर्ट ने सरकार को बताया कि उत्तर प्रदेश में भी नक्सली संगठन अपनी जड़ें गहरी कर रहे हैं और बिहार, ओड़ीशा और छत्तीसगढ़ से लगने वाली सीमा के अलावा नेपाल से लगने वाले सीमाई क्षेत्र में नक्सली गतिविधियां काफी बढ़ गई हैं. सोनभद्र और चंदौली में नक्सलियों का प्रभाव खासा बढ़ गया है. इन दो जिलों में ही माओवादियों ने पुलिस पर हमले की कई घटनाओं को अंजाम दिया है. पिछले कुछ साल के दरम्यान इन दोनों जिलों में नक्सली हमले की तकरीबन 50 घटनाएं हुईं और दो दर्जन से अधिक माओवादी मारे भी गए. हालांकि 1994 में चंदौली जिले में 15 जवानों के मारे जाने के बाद से उत्तर प्रदेश में कोई बड़ी खूनी नक्सली वारदात तो नहीं हुई, पर इसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. केंद्र में भाजपा की सरकार बनने और राजनाथ सिंह के गृहमंत्री बनने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल इस तरफ अधिक सतर्क और सक्रिय हुईं, इससे नक्सल संगठनों में भाजपा के खिलाफ और तल्खी बढ़ी. उत्तर प्रदेश के नक्सल (माओवादी) प्रभावित जिलों में अतिरिक्त विशेष कार्यबल (एसएएफ) तैनात करने की केंद्र की कवायद इस तल्खी को और बढ़ा रही है और प्रतिरोधी राजनीतिक दल इस तल्खी का सियासी फायदा उठाने की जुगत चला रहे हैं. खुफिया रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की सीमा छत्तीसगढ़ और बिहार से जुड़े होने की वजह से माओवादी इस राज्य का इस्तेमाल पहले तो छुपने के लिए करते थे, लेकिन वे अब इसे अपनी सक्रिय गतिविधियों का भी केंद्र बना रहे हैं. नेपाल के माओवादी यूपी के नक्सली संगठनों को मदद पहुंचा रहे हैं. नेपाल के माओवादी यूपी में आकर यहां के नक्सलियों को ट्रेनिंग देने का भी काम कर रहे हैं. राज्य में दर्जनभर जिले ऐसे हैं, जहां माओवादी अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश में तेजी से लगे हैं.

पिछले कुछ अर्से में उत्तर प्रदेश में कई नक्सली मारे गए या गिरफ्तार किए गए. इनमें कमलेश चौधरी, कृष्णा वगैरह का नाम उल्लेखनीय है. कमलेश पर तो डेढ़ लाख का इनाम घोषित था. उसे यूपी में नक्सली हमलों के लिए भेजा गया था. उसका एक अन्य साथी शत्रुघ्न यूपी पुलिस के हाथों मारा गया था. इसके अलावा 50 हजार के इनामी गोपी उर्फ गिरधर गोपाल सोनभद्र के दुद्धी इलाके से गिरफ्तार किया गया था. पुलिसिया शब्दावली में बीजे सेक्टर नक्सली गतिविधियों का सक्रिय केंद्र है. बिहार–झारखंड और यूपी का सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली इसी बीजे सेक्टर में आते हैं. इन जिलों में नक्सली गतिविधियां तेज हैं. थ्री–यू सेक्टर, यानी उत्तरी बिहार, उत्तराखंड और अपर तराई बेल्ट के जिलों में नक्सलियों की गतिविधियां वैचारिकी के तौर पर चलाई जा रही हैं और उसे धीरे–धीरे एक्शन के लिए तैयार किया जा रहा है. यूपी के बुंदेलखंड, इटावा और पश्चिमी उत्तरप्रदेश में भी नक्सली संगठनों की सक्रियता काफी बढ़ी हैं. खुफिया रिपोर्ट कहती है कि यूपी स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के नाम से नक्सली यहां सक्रिय हैं, लेकिन कई गैर सरकारी संगठनों का यह भी दावा है कि ये लोग नक्सली नहीं हैं. उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में कुख्यात नक्सली कृष्णा (एक लाख का इनामी) की गिरफ्तारी ने भी यह उजागर किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नक्सलियों का नेटवर्क फैल रहा है. एसटीएफ के हाथों बिहार में पकड़े गए नक्सली चंदन उर्फ चनारिक दास ने यह खुलासा किया था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों का इस्तेमाल फरार नक्सली छुपने के लिए कर रहे हैं. गिरफ्तारी से पहले चंदन खुद ही मेरठ, मुजफ्फरनगर, ग्रेटर नोएडा में रहकर नक्सली गतिविधियों के लिए नेटवर्क खड़ा करने में जुटा था. चंदन को पश्चिम यूपी में नेटवर्क फैलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी.

नक्सली संगठनों के विचारकों में काडर और नक्सल समर्थकों के बीच साम्प्रदायिकता के खिलाफ विचार को प्रगाढ़ किया जाता है. नक्सलियों के इस विचार का राजनीतिक दल भाजपा के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और साम्प्रदायिकता के नाम पर नक्सल संगठनों को न्यूट्रल कर नक्सल समर्थकों का वोट हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं. इसके एवज में नक्सलवादियों को भरपूर आर्थिक मदद दी जाती है. यह आधिकारिक तथ्य है, जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में दर्ज है. इसे रोक पाना असंभव है, क्योंकि इसमें ताकतवर पार्टियां, बड़े–बड़े नेता और बड़े धनपतियों का धन इन्वॉल्व है. नक्सल क्षेत्रों के आसपास व्यापार चलाने वाली बड़ी–बड़ी कंपनियों के माध्यम से नक्सलवादियों को आर्थिक मदद मिलती है और एवज में नक्सलियों की तटस्थता व सैद्धांतिक आधार पर सम्बद्ध राजनीतिक दल के समर्थन में वोट डालने का संदेश नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रसारित हो जाता है. यह बात स्थापित हो चुकी है कि राजनीतिक दल नक्सलवादी संगठनों का आश्रय लेते हैं और राजनीतिक पार्टियों को सफल बनाने के एवज में नक्सल संगठन भारी आर्थिक मदद प्राप्त करते रहते हैं. ■

गिरफ्तार नक्सली ने भी बताया सियासी सौदेबाजी के बारे में

आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिलों में गिरफ्तार किए गए खुर्राट नक्सली कमांडर गोविंद यादव ने चुनावों में नक्सली संगठनों के सैद्धांतिक–सियासी इस्तेमाल की नीतियों के बारे में खुफिया एजेंसियों को भनक दी है. गोविंद यादव खास तौर पर बिहार और झारखंड में जबरदस्त तरीके से सक्रिय रहा है. गोविंद पर पांच लाख रुपये का इनाम घोषित था. गोविंद न केवल नक्सल ऑपरेशनों में, बल्कि विचारकों और राजनीतिक दलों के साथ होने वाली सैद्धांतिक–समझदारियों (सिद्धांत के नाम पर सौदेबाजियों) में बराबर शरीक रहा है. गोविंद यादव के पिता का नाम केदार यादव है. वह लातेहार जिले का रहने वाला बताया जाता है. बिहार–झारखंड का एक और कुख्यात नक्सली कमांडर जीतेंद्र उरांव अभी कुछ ही दिन पहले केरल के एर्नाकुलम से गिरफ्तार किया गया था. उरांव लातेहार के गारु में हुई नक्सली हिंसा के मामले में फरार था. लांदू उरांव का बेटा जीतेंद्र उरांव भी लातेहार जिले के गारु प्रखंड का रहने वाला है. ■

कांग्रेस भी ले चुकी है माओवादियों की मदद!

कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की सत्ता में रहते हुए भी छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के चुनावों में माओवादियों की मदद ली थी. नक्सलियों की मदद लेने का कांग्रेस पर लगा आरोप भी सुर्खियों में रहा है. लिहाजा, राजनीतिक दलों के लिए यह अब कोई नई बात नहीं रही. धर्मनिरपेक्षता के नाम पर चलने वाली समानान्तर सियासत में नक्सल–एंगल भी एक जरूरी हिस्सा बनता जा रहा है. छत्तीसगढ़ के दरभा घाटी में नक्सल हमलों में कांग्रेस नेताओं के मारे जाने के बावजूद कांग्रेस ने चुनाव में नक्सली संगठनों से मदद ली और भाजपा के खिलाफ उन्हें तटस्थ रहने के लिए उकसाया. ■

ममता ने भी ली थी माओवादियों की मदद

ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने माओवादियों की मदद ली थी, यह बात सुर्खियों में रही है. यहां तक कि देश के तत्कालीन सुरक्षा सलाहकार एमके नारायणन ने भी इस ओर इशारा किया था और कहा था कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी ने माओवादी संगठनों की मदद ली थी. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पूर्व महासचिव प्रकाश करात ने तो सार्वजनिक बयान देकर कहा था कि तृणमूल कांग्रेस माओवादियों की मदद लेकर वाम मोर्चा की सरकार को हटाने का प्रयास कर रही है. करात ने यह भी कहा था कि तृणमूल कांग्रेस ने नंदीग्राम में माओवादियों से मदद ली है. आप याद करें कि ममता बनर्जी ने मांग की थी कि सरकार लालगढ़ में तैनात सुरक्षा बल तत्काल वापस बुला ले. साथ ही, ममता ने माओवादियों से हिंसा छोड़ कर सरकार से बातचीत के लिए सामने आने की अपील भी की थी. ममता के इस बयान पर वाममोर्चा ने उन पर नक्सलियों के साथ साठगांठ का आरोप लगाया था. हालांकि इसकी पुष्टि हुई थी कि ममता बनर्जी की लालगढ़ रैली को नक्सलियों ने पूरा समर्थन दिया था. मंच पर सरकार और नक्सलियों के बीच तब धुरी बने स्वामी अग्निवेश, मेधा पाटकर और प्रख्यात लेखिका महाशवेता देवी मौजूद थीं. तब संसद में भी यह कहा गया था कि ममता की रैली नक्सालियों की मदद से आयोजित की गई थी. रैली स्थल से पीसीपीए के चार नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया, जिसमें पहले से फरार चल रहा सुशील महतो भी शामिल था. ■

feedback@chauthiduniya.com

आजम के बाद अब राय से हलकान सपा

दीनबंधु कबीर

महागठबंधन से अलग होने का फैसला लेने के बाद बिहार के चुनाव परिणामों से झटके में आई समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के इस्तीफे और योजना आयोग का सदस्य पद लेने से सीपी राय के इन्कार से हतप्रभ है. आजम खान से सपा नेतृत्व पहले से ही परेशान होता रहा है, अब डॉ. सीपी राय से भी पार्टी हलकान है. आजम खान के इस्तीफे की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सांकेतिक भाषा में नेताओं ने इसका संकेत दे दिया है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने कहा कि अब किसी का मान-मनौव्वल नहीं होगा. सपा प्रमुख का यह इशारा पाते ही आजम खान अपना कोप छोड़ कर मुलायम की प्रशंसा पर आ गए. लेकिन इन सब के बावजूद आजम खान के इस्तीफे पर असमंजस बना कर रखा जा रहा है. इस्तीफे की खबरों की पुष्टि और इन्कार, दोनों से बचते हुए आजम ने सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से किसी तरह का मतभेद होने से इंकार कर दिया. इस्तीफे को लेकर आजम ने कहा कि जो खबरें चल रही हैं, उस पर उन्हें अभी कुछ नहीं कहना है. उल्लेखनीय है कि 10 नवम्बर की शाम से ही आजम खान के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की खबरें आने लगी थीं. आजम भी लखनऊ से रामपुर के लिए चल पड़े, तबसे वो कोपभवन में ही हैं. इसके पहले आजम खान बिहार के चुनाव परिणामों को लेकर बेबाक टिप्पणी जारी कर भी सपा नेतृत्व के तनाव का कारण बन चुके थे.

सपा के पूर्व नेता अमर सिंह की मुलायम सिंह यादव से बढ़ती नजदीकियां आजम खान को बिल्कुल रास नहीं आ रही है. मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान भी आजम की बातों को सपा नेतृत्व की ओर से दरकिनार कर दिया गया था, जिससे आजम बेहद खफा हैं. आजम की बात रखने के बजाय मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे चेहरों को शामिल किया गया, जो अमर सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं. इसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी से नाराज होकर आजम ने अपने इस्तीफे की पेशकश है. उधर, बिहार चुनाव के बाद की स्थितियों में समाजवादी पार्टी को अमर सिंह जैसे बेहतरीन मैनेजर की जरूरत है. लिहाजा अमर सिंह की सलाहें पार्टी नेतृत्व मान रहा है. दूसरी तरफ, दर्जा प्राप्त मंत्री रहे सपा के वरिष्ठ नेता डॉ. सीपी राय ने राज्य योजना आयोग के सदस्य का पद ठुकरा दिया है. डॉ. सीपी राय ने कहा कि आयोग पर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च होता हो और इसके बदले में जनता के लिए कुछ नहीं मिले तो ऐसे पद को स्वीकार करना उनके लिए अनैतिक है. सपा के नेता डॉ. सीपी राय के फैसले को बगावत मान रहे हैं. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राय को पत्र लिखकर बताया था कि उन्हें राज्य योजना आयोग का सदस्य बनाया गया है. मुख्यमंत्री का पत्र मिलने के बाद राय ने फौरन उसमें अपना अनुरोध पत्र जोड़कर उन्हें वापस भेज दिया और पद लेने से इन्कार कर दिया. डॉ. सीपी राय ने इसकी पुष्टि की.

डॉ.सीपी राय समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं. वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी को मिली करारी हार के बाद ही उन्होंने प्रदेश महामंत्री और राज्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था. बलिया से पूर्व कैबिनेट मंत्री नारद राय को बर्खास्त करने के बाद अखिलेश यादव ने नुमाइंदगी के तौर पर डॉ. सीपी राय जैसे वरिष्ठ नेता को पद देकर समायोजित करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने यह पद लेने से मना करके नेतृत्व को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है. साफ-साफ संदेश जा रहा है कि पार्टी में भीतर-भीतर कुछ अच्छा नहीं चल रहा. ■

feedback@chauthiduniya.com

निषाद संघ निकालेगा एकलव्य न्याय रथ

उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव-2017 को ध्यान में रखकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने 6 नवम्बर को बैठक कर प्रदेश भर में निषाद क्रांति रथ चलवाने का निर्णय लिया. इसके जवाब में राष्ट्रीय निषाद संघ एकलव्य सामाजिक न्याय रथ निकाल कर अतिपिछड़ों व निषाद मछुआरा समाज को भाजपा की कथनी-करनी का अन्तर बताएगा. निषाद संघ राष्ट्रीय मछुआरा आयोग, राष्ट्रीय विमुक्त जाति एवं घुमन्तू जनजाति आयोग का गठन करने व अलग से स्वतंत्र मत्स्य मंत्रालय बनाने तथा वीर एकलव्य पुरस्कार घोषित करने की भी मांग कर रहा है. ■

सपा खेले एमबीसी व ईबीसी कार्ड

बिहार चुनाव परिणाम के परिप्रेक्ष्य में समाजवादी पार्टी नेतृत्व को एमबीसी व ईबीसी कार्ड खेलने की सलाह दी जा रही है. अतिपिछड़ी और अत्यन्त पिछड़ी जातियों को एकजुट करने की सपा में विचार चल रहा है. सपा सरकार से शिकायत भी है कि छठे मंत्रिमंडलीय विस्तार में भी अतिपिछड़ी व अत्यन्त पिछड़ी जातियों को कैबिनेट में समुचित व आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया. मांग उठ रही है कि कुशवाहा, मौर्य, निषाद, पाल, लोध, किसान जैसी मजबूत आधार वाली जातियों को कैबिनेट व स्वतंत्र प्रभार के मंत्री का दर्जा दिया जाए. अभी सपा सरकार में लोधी/किसान जाति के तीन, निषाद/कश्यप जाति के दो और पाल, चौरसिया जाति के एक-एक प्रतिनिधि को राज्यमंत्री बनाया गया है. प्रजापति व माली सैनी समाज के एक-एक लोगों के प्रतिनिधि को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है. 2007 की मतदाता सूची के अनुसार निषाद समुदाय की जातियों की संख्या 1 करोड़ 73 लाख, 78 हजार तथा सामाजिक न्याय समिति-2001 की रिपोर्ट के अनुसार उनकी आबादी 12.92 प्रतिशत है. इसी तरह लोधी/किसान-6.06 प्रतिशत, कुशवाहा/मौर्य/काछी/सैनी आदि-8.56 प्रतिशत, पाल/बघेल-4.43 प्रतिशत, राजभर-2.44 प्रतिशत, चैहान-2.33, तेली-3.01, कान्दू भुर्जी-1.43, विश्वकर्मा-3.72 प्रतिशत, नाई/सविता-1.01 प्रतिशत हैं. ■

महागठबंधन राग अलापने लगे सपाई

समाजवादी पार्टी के छोटे नेता बिहार में महागठबंधन की जीत को सामाजिक न्याय की जीत बताते नहीं अघा रहे हैं. समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय निषाद संघ के राष्ट्रीय सचिव चौधरी लौटन राम निषाद ने बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत पर कहा कि बिहार में सामाजिक न्याय और पिछड़ावाद जीता है और भाजपा नेताओं का बड़बोलापन, अतिवाद व छद्म समावेशी राजनीति की हार हुई है. निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी भाजपा को ऐसी ही करारी हार देखनी पड़ेगी. उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति विधानसभा चुनाव-2012 की ही तरह रहेगी. बिहार परिणाम पर बेबाकी से बोलने वाले सपा नेता ने महागठबंधन से अलग के सपा नेतृत्व के फैसले पर कुछ नहीं कहा. सपा नेतृत्व का यह फैसला सामाजिक न्याय के सिद्धांत के कितना अनुकूल था, इस पर सपाई चुप्पी साध ले रहे हैं. भाजपा के खिलाफ तल्ख टिप्पणियां करने वाले सपा नेताओं में अधिकांश वे हैं, जिन्हें भाजपा में तरजीह नहीं मिली तो वे सपा में आ गए. चौधरी लौटन राम निषाद भी ऐसे ही नेताओं में शामिल हैं. वे कहते हैं कि भाजपा ने अतिपिछड़ा, पिछड़ा, गरीब, चाय बेचने वाला वगैरह बताकर पिछड़ों, अतिपिछड़ों, दलित आदिवासियों का वोट बैंक हासिल किया, लेकिन सरकार बनते ही इन वर्गों को दरकिनार कर दिया. डेढ़ वर्ष में मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने एक भी ऐसा कार्य नहीं किया, जिससे पिछड़े दलित वर्ग को यह एहसास हो कि मोदी ओबीसी या अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बंजारा जाति की पंकजा मुंडे, हरियाणा में जाट, गुर्जर या सैनी तथा झारखंड में आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की हवा तो उड़ाई, लेकिन जब सरकार बनने की स्थिति आई तो महाराष्ट्र में देवेन्द्र फड़नवीस (ब्राह्मण), हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर (पंजाबी) व झारखंड में रघुवर दास (साहू) को मुख्यमंत्री बना दिया. दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के झूठ, फरेब व छल-कपट की राजनीति को धता बताने के लिए पिछड़ों, अतिपिछड़ों ने भाजपा को शर्मनाक हार दिलाई और बिहार में भी पिछड़ों, अतिपिछड़ों, दलित-महादलितों ने भाजपा को अपनी ताकत का एहसास कर दिया. अपना गुस्सा निकालते हुए निषाद यह भी बोल गए कि (महागठबंधन से अलग हुई) समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सरकार बनाएगी. निषाद ने कहा कि 2013 में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी व सुषमा स्वराज ने दिल्ली के मावलंकर ऑडिटोरियम में मछुआरों के राष्ट्रीय सम्मेलन में फिशरमैन विजन डॉक्यूमेन्ट जारी करते हुए मछुआरों के कल्याण के लिए उनके परम्परागत पेशों को विकसित करने का उपाय करने तथा आरक्षण की विसंगति को दूर करने का संकल्प लिया था, लेकिन सरकार बनने के बाद भी भाजपा सरकार ने आरक्षण की विसंगति दूर करने व मछुआरों के परम्परागत पेशों पर विकास के लिए कोई कदम नहीं उठाया. विधानसभा चुनाव-2012 के चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा ने निषाद, मछुआ, मल्लाह, माझी, केवट, धीवर, धीमर, कश्यप, कहार, गोड़िया, तुराहा, रैकवार, राजभर, कुम्भार, बियार, बिन्द, बंजारा, नोनिया आदि जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने का उल्लेख भी किया था, लेकिन इस ओर कोई प्रयास नहीं हुआ. चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अत्यन्त पिछड़े वर्ग की आबादी कुल जनसंख्या में 33.34 प्रतिशत व अतिपिछड़े वर्ग की संख्या 10.22 प्रतिशत है. यह आबादी प्रदेश की राजनीति की दशा-दिशा तय करेगी. ■

साहित्य के मंच पर राजनीति

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री

कवि सम्मेलन के मंच पर भी राजनेता अपना मूल गुणधर्म नहीं छोड़ते. वह अपनी सुविधा से सियासत की बात रखने का मौका तलाश ही लेते हैं. इसका नजारा लखनऊ में चल रहे गोमती उत्सव के समापन पर दिखाई दिया. इसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अरविन्द सिंह गोप और भाजपा के वरिष्ठ मंत्री व पूर्व कैबिनेट मंत्री लालजी टंडन मौजूद थे. वैसे, इन नेताओं को कवि सम्मेलन प्रारंभ होने के पहले ही आ जाना चाहिए था. उन्हें विशिष्ट लोगों को सम्मानित करने वाले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया गया था. इस कार्यक्रम की समाप्ति के बाद अगला कार्यक्रम कवि सम्मेलन होना था. पहला कार्यक्रम समय से होता तो सम्मान कार्यक्रम और कवि सम्मेलन को संयुक्त न करना पड़ता, लेकिन वरिष्ठ नेता समय से आ जाएं तो यह देखकर आश्चर्य ही होता है.

इसमें भी पूर्व और वर्तमान कैबिनेट मंत्री के बीच का फर्क दिखाई दिया. पूर्व मंत्री लालजी टंडन पहले आ गए. मंच से घोषणा की गयी कि अरविन्द सिंह गोप चल दिए हैं, आने वाले हैं, फिर सम्मान कार्यक्रम शुरू हो गया है, लेकिन हूटर, साइरन, पुलिस एस्कार्ट के बाद भी लगता है कैबिनेट मंत्री की राह आसान नहीं होती, लेट तो होना ही पड़ता है. गोप इतना लेट हुए कि कवि सम्मेलन शुरू हो गया. एक कवि काव्यपाठ कर रहे थे, तभी परिसर में लालबत्ती कारों का काफिला दिखाई दिया. हलचल होना स्वाभाविक था, लेकिन संचालक सर्वेश अस्थाना ने कवि सम्मेलन का महत्व कम नहीं होने दिया. मंत्री के तामझाम को काव्यपाठ पर हावी नहीं होने दिया. उन्होंने मंच से कहा कि मंत्री जी सामने पड़े सोफे पर अपना स्थान ग्रहण करें. यह काव्यपाठ पूरा होने के बाद उन्हें मंच पर बुलाया जाएगा. गोप ने भी शालीनता का परिचय दिया. वह नीचे ही बैठ गए. वहां लालजी टंडन और हिन्दी संस्थान के अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह पहले ही मौजूद थे. सम्मान समारोह में महापौर दिनेश शर्मा को भी मौजूद रहना था, लेकिन वह आए और गोप के आने के पहले ही निकल गए. गोप के आ जाने के बाद आयोजकों ने राहत की सांस ली. एक कवि का काव्यपाठ समाप्त हो जाने के बाद नेताओं को मंच पर बुलाया गया. कुछ समय के लिए साहित्य पीछे हो गया, सियासत आगे आ गई. उदय प्रताप सिंह तो जैसे मंत्री का इंतजार करते-करते थक गए थे, वह भी मंच पर आए. कुछ अवधि के लिए कवि सम्मेलन का मंच सम्मान समारोह में बदल गया, जिसमें आकर्षण के केन्द्र अरविन्द सिह गोप और लालजी टंडन थे. प्रत्येक अवसर पर नेताओं का माइक पर आना अनिवार्य होता है. जिस कवि का काव्य पाठ हो गया था, वह तो ट्रेन का टाइम बताकर निकल गए. मंच पर बैठे अन्य कवि रुकावट के लिए खेद देखते रहे.

गोमती उत्सव समारोह था. जाहिर है अरविंद सिंह गोप को अपना भाषण गोमती नदी से प्रारंभ करना था. इतना ध्यान प्रत्येक अनुभवी नेता रखता है, लेकिन नदी तक सीमित रहे तो सियासत का क्या होता. उन्होंने लगे हाथ प्रदेश के युवा व यशस्वी मुख्यमंत्री का गुणगान भी करना शुरू कर दिया. न करते तो धृष्टता होती. एक हफ्ता पहले ही मंत्रिमंडल में उनका कद बढ़ा है. इस गुणगान के बाद फिर गोमती पर लौटे. बताया कि उनकी सरकार गोमती के तटबन्ध बना रही है. यहां पार्क व घूमने का स्थान बनेगा. गोप अपनी, मुख्यमंत्री की और सरकार की वाहवाही करके बैठ गए.

इसके बाद लालजी टंडन की बारी थी. उन्होंने साबित कर दिया कि आज समय भले ही गोप के साथ है, लेकिन अनुभव में वह बराबरी नहीं कर सकते. गोप ने जिसे सरकार की उपलब्धि बताया था, टंडन ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन ऐसा करते समय भी मंच की मर्यादा बनाए रखी, लखनवी तहजीब बनाए रखी, विरोध का अंदाज राजनीतिक नहीं था, ऐसा लगा जैसे सुझाव दे रहे हैं. समझने वाले समझ गए. गोप की आत्म प्रशंसा स्वीकार नहीं की, विरोध भी हो गया, अंदाज भी दोस्ताना बना रहा. बहुत संभव था कि यदि गोप ने सरकार व राजनीति की बात शुरू न की होती तो टंडन भी उसका जवाब नहीं देते, लेकिन जब बात चली थी तो उनका चुप रहना भी मुनासिब नहीं था. लालजी टंडन प्रदेश के नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं. गुल्लाला घाट का सुधार उन्होंने ही कराया था.

टंडन ने कहा कि गन्दे नाले आज भी गोमती में गिर रहे हैं. पिछली व वर्तमान सरकार ने इस दिशा में कोई खास काम नहीं किया. उन्होंने पिछली सरकार पर गोमती को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया. लखनवी तहजीब देखिए कि टंडन ने गोप की तारीफ भी की और उनकी सरकार की योजनाओं में खामी भी बता दी. टंडन बोले कि उन्होंने नगर विकास मंत्री रहते हुए गोमती सफाई के जो कार्य किए थे, उसकी विपक्ष ने प्रशंसा की थी. आज वह विपक्ष में हैं, सरकार गोमती सफाई का जो कार्य कर रही है, उसकी वह प्रशंसा करते हैं. इसके बाद टंडन असली मुद्दे पर आ गए. उन्होंने कहा कि गोमती किसी पर्वत या ग्लेशियर से नहीं निकली है. इसके स्रोत जमीन से निकले हैं. यह जगह-जगह पर बिखरे हैं. ऐसे में गोमती के तटबन्ध पर निर्माण कार्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे अनेक स्रोत भी बंद हो सकते हैं. सरकार को विशेषज्ञों की सलाह पर विचार के बाद ही कोई निर्माण कार्य करना चाहिए. ■

गंदली गोमती की गवाही में गोमती उत्सव

गंदली गोमती गोमती उत्सव का गवाह बनी, जिसमें गोमती की सफाई पर बातें तो खूब हुईं, पर यथार्थ उतना ही मैला है, जितनी गोमती नदी. गोमती उत्सव के आयोजन में केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा के हाथों समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया. बदबूदार गोमती के किनारे लोक गीत और नृत्य का भी लोगों ने खूब रसास्वादन लिया. तीन दिन तक चलने वाले इस उत्सव का उद्घाटन राज्यपाल रामनाईक ने ही किया था. उन्होंने नदियों से जुड़े ऐसे उत्सवों को बढ़ावा देने का आह्वान किया. प्रायः सभी बड़े शहर किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं. राज्यपाल ने कहा कि ऐसे आयोजन नदियों की सफाई के प्रति हमारी जिम्मेदारी का स्मरण दिलाते हैं. राज्यपाल ने न केवल ऐसे आयोजनों को आवश्यक बताया, बल्कि इनके बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी उचित बताया. उद्देश्य यही होना चाहिए कि नदियों के किनारे बसे शहरों के सभी निवासी नदी की सफाई में अपना योगदान सुनिश्चित करें. राज्यपाल द्वारा उद्घाटन के बाद प्रसिद्ध गायक और सांसद मनोज तिवारी का गायन हुआ. उन्होंने नदियों के प्रति सम्मान की प्रेरणा देने वाले गीत से शुरुआत की-मेरे घर में बूढ़ी माता है, वह कहती है कि गंगा मेरी माता है. यह गाना नदियों के प्रति परम्परागत आत्मीयता का रिश्ता जोड़ने वाला था. दूसरे दिन प्रसिद्ध लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने इसी प्रसंग को आगे बढ़ाया. लोकगीत के माध्यम से उन्होंने गोमती का जल सभी देवियों को चढ़ाने की कामना की. भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉ. ओमप्रकाश ने भी गीतकार और गायक के रूप में प्रतिभा दिखाई. कवियों ने प्रकृति और गोमती के संरक्षण का महत्व प्रतिपादित किया. निःसन्देह यह महोत्सव नदियों के प्रति सम्मान व संरक्षण भाव जगाने वाला साबित हुआ. इस तरह दो बड़े रोचक कार्यक्रम संयोग से गोमती नदी के दो किनारों पर सम्पन्न हुए. राजभवन में भी राज्यपाल रामनाईक और लेडी गवर्नर कुंदा नाईक की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रसिद्ध भजन सम्राट अनूप जलोटा का गायन हुआ. दूरदर्शन में जानी-पहचानी समाचार वाचिका रही निर्मला कुमारी ने भी एक फिल्मी गाना सुनाकर समारोह को जीवंत बना दिया. निर्मला कुमारी लम्बे समय के बाद लखनऊ के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दीं. जब इलेक्ट्रॉनिक चैनल के नाम पर दूरदर्शन का बहुत दबदबा हुआ करता था, तभी से निर्मला कुमारी की विशिष्ट पहचान बनी थी, लेकिन बहुत से लोगों को यह जानकारी नहीं थी कि वह जितने अच्छे अन्दाज में समाचार पढ़ती थीं, उतना ही अच्छा गाना भी गाती हैं. अनूप जलोटा ने कहा भी कि वह अपने विद्यार्थी जीवन से ही निर्मला कुमारी का गाना सुनते आ रहे हैं, उनसे सीखते रहे हैं. निर्मला कुमारी कुछ समय के लिए मुम्बई गयी थीं, लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा, वह वापस लखनऊ आ गयीं. जलोटा ने कहा कि यदि निर्मला कुमारी कुछ समय और मुम्बई में रही होतीं तो देश की प्रसिद्ध गायिकाओं में उनका नाम शुमार होता. कार्यक्रम में अनूप जलोटा ने अपने चिरपरिचित अन्दाज में भजन पेश किए. सांस खींचकर लयकारी की प्रस्तुति किसी का भी मन मोह लेती है. श्रोता बिना किसी के कहे तालियां बजाने लगते हैं. प्रारम्भ में राज्यपाल राम नाईक के संक्षिप्त संबोधन में भी संगीतमय रोचकता थी. उन्होंने उस चर्चा का उल्लेख किया, जिसमें अनूप जलोटा का कार्यक्रम राजभवन में आयोजित करने की रूपरेखा बनी थी. अनूप जलोटा कुछ समय पहले रामनाईक से मिलने राजभवन गए थे. वहां जलोटा की पुरानी यादें ताजा हुईं. उन्होंने नाईक को बताया कि वह अपने पिता प्रसिद्ध भजन गायक पुरुषोत्तम दास जलोटा के साथ आते थे. उस समय कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी राज्यपाल थे. रामनाईक ने इस मुलाकात में ही अनूप जलोटा का कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया था. राजभवन में आयोजित इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी, पद्मश्री गोपाल दास नीरज सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. ■

नशे के खिलाफ जंग, खेल खेलेंगे हम

राजकुमार शर्मा

हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड में एक नौजवान ने नशे के खिलाफ जंग की घोषणा करके हिमालय की युवा शक्ति की बर्बादी को रोकने, युवाओं में विकास एवं समृद्धि की ललक जगाने का जो संकल्प लिया है, वह इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है. वह युवक कोई आम युवक नहीं है, बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री और हिमालय के विकास के लिए प्रतिबद्ध नेता हरीश रावत के पुत्र आनन्द रावत हैं, जो जानते हैं कि शराब लॉबी उनके परिवार की राजनीति को क्षति पहुंचा सकती है. क्षति की परवाह से बेखबर युवा शक्ति को नशे को मिटा कर युवकों को देश हित में तैयार करने की जो शानदार ललक उनमें जगी है, वह उनकी शोहरत में चार चांद लगा रहा है. राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर ओएनजीसी अम्बेडकर स्टेडियम, कौलागढ़ रोड में आयोजित नशे के खिलाफ जंग, खेल खेलेंगे हम, उनकी प्रेरणा से आयोजित कार्यक्रम की सफलता ने आनन्द को एक वजनदार युवा के रूप में पेश किया है. इस अवसर पर मुख्यमंत्री रावत ने युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ भी दिलायी. मुख्यमंत्री श्री रावत इस अवसर पर पारंपरिक खेलों में शामिल भी हुए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री रावत ने अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मुकेश रावत व प्रीतम सिंह को स्मृति चिन्ह प्रदान किया. साथ ही वरिष्ठ खेल प्रेमी प्रेम कश्यप को भी स्मृति चिन्ह दिया. मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि इस प्रकार के पारंपरिक खेल हमें हमारे गांव से जोड़ने का काम करते हैं. उन्होंने कहा कि इन पारंपरिक खेलों को मसूरी कॉर्निवाल में भी शामिल किया जायेगा. साथ ही प्रत्येक जनपद में इन खेलों के आयोजन में राज्य सरकार भी सहयोग करेगी. मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि इस प्रकार के खेल आयोजन करने से हमारे युवाओं में नया जोश और उमंग आयी है. आज के युवा अपने पारंपरिक खेलों के बारे में भी जान पाये हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि राष्ट्रीय खेलों में इन पारंपरिक खेलों को भी शामिल किया जाय, ताकि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक अवसर मिल सके. उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमने ग्रामीण खेल पर फोकस किया है. उन्होंने यह भी कहा कि युवाओं को अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, तभी जीवन में आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी. युवाओं में बढ़ती नशे की लत को दूर करने में इस प्रकार के आयोजन सफल साबित होंगे. उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे के विरुद्ध एक अभियान चलाना होगा, ताकि हमारी युवा शक्ति भविष्य का निर्माण कर सके. इस अवसर पर कार्यक्रम के संयोजक आनन्द रावत ने कहा कि युवाओं को अपने पारंपरिक खेलों से जोड़ने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि युवाओं में नशे की प्रवृत्ति छुड़ाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है. इसी के तहत पारंपरिक खेल शुरू किया गया है, जिसमें मुर्गाझपट, गिट्टी, बाघ-बकरी, फुटसाल और पिट्टू फोड़ आदि खेल शामिल किये गये हैं. उन्होंने राज्य सरकार से इन खेलों को राष्ट्रीय खेल और मसूरी कॉर्निवाल में शामिल करने का अनुरोध किया. युवा पुत्र आनन्द के साथ पिता हरीश की जुगलबन्दी को नशा के खिलाफ मजबूत जंग के रूप देखा जा रहा है. ■

उत्तराखंड में भाजपा के दिग्गजों ने एकजुटता का स्वांग रचा

रेनु शर्मा

प्रदेश भाजपा को नया अध्यक्ष मिलने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन अब तक किसी एक नाम पर सहमति बनती नहीं दिख रही है. भाजपा हाईकमान प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को कह चुका है कि किसी एक नाम पर सहमति बनायी जाए, ताकि यह संदेश दिया जा सके कि उत्तराखंड में भाजपा एकजुट है. अध्यक्ष के इस रेस में पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के कूदने से मामला पेचिदा हो गया है. त्रिवेन्द्र सिंह के बढ़ते रथ के सामने निशंक पहाड़ बन कर उभरे हैं. नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर स्थानीय स्तर पर संघ भी किसी एक नाम पर सहमति नहीं जता पा रहा है. इससे नए अध्यक्ष का मसला दिनोंदिन उलझता जा रहा है. संघ की उलझन ने प्रदेश भाजपा को भी पसोपेश में डाल दिया है. नए अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे कुछ वरिष्ठ नेता संघ तो कुछ दिल्ली दरबार में अपनी योग्यता प्रमाणित करने में जुटे हैं. सूत्रों के मुताबिक, दीपावली के बाद किसी एक नाम पर कोई सहमति नहीं बनी तो आनेवाले दिनों में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली तलब कर सकते हैं और वहीं पर अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है. इधर, नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर प्रदेश में जोड़-तोड़ की राजनीति तेज हो गई है. प्रदेश भाजपा में रोजाना ही नए-नए दावेदार सामने आ रहे हैं. भाजपा हाईकमान के पास प्रदेश से जितने भी नाम पहुंचे हैं, संघ पदाधिकारियों ने उन पर कैंची चलानी शुरू कर दी है. संघ किसी एक नाम पर मुहर नहीं लगा रहा है. संघ पदाधिकारियों की राय इस मामले में जुदा-जुदा हैं. नए अध्यक्ष के चयन को लेकर प्रदेश भाजपा के प्रभारी व शिव प्रकाश जैसे शीर्ष नेता ताकत झोंके हुए हैं, लेकिन परिणाम शून्य रहा है. दरअसल, संघ से भाजपा में आये पार्टी के शीर्ष नेताओं को लग रहा है कि भाजपा भी संघ की शैली पर चले, जिसका खुला विरोध भी शुरू हो गया है. प्रदेश भाजपा के नेताओं का कहना है कि पार्टी संघ की शैली में नहीं चल सकती. पार्टी चलाने के लिये यह जरूरी नहीं कि संघ के फॉर्मूले से नया अध्यक्ष तय किया जाये. दावेदारों में अधिकतर ही संघ के प्रचारक रहे हैं. नये अध्यक्ष के चयन को लेकर प्रदेश भाजपा में इतना ज्यादा घमासान मचा है कि भाजपा हाईकमान फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है. स्थिति तो यह हो गयी है कि भाजपा हाईकमान अब अपने विश्वासपात्रों पर भी आंख मूंद कर भरोसा करने से कतरा रहा है. बिहार के नतीजों ने भाजपा के दिग्गजों को जिस कदर हिलाया है, उससे फैसले में देरी हो सकती है. ■

गैरसैंण मुद्दा

दिग्गज नेता ने हरीश की जड़ में मट्ठा डाला

राजकुमार शर्मा

डॉ. इंदिरा हृदयेश ने हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि गैरसैंण तो कामचलाऊ राजधानी होगी. प्रदेश की स्थायी राजधानी तो देहरादून ही होगी. गैरसैंण का मुद्दा कांग्रेस में अपने-अपने धड़ों की ताकत बढ़ाने का औजार बन रहा है. डॉ. इंदिरा के इस कथन ने उत्तराखण्ड के अति संवेदनशील मुद्दे पर की गयी बेबाक टिप्पणी को राजनीति के मर्मज्ञ एक सोची-समझी राजनीति बताते हैं और कहते हैं कि दिग्गज नेता ने हरीश की जड़ में मट्ठा डालने का काम किया है. उत्तराखण्ड राज्य का निर्माण ही राजधानी गैरसैंण के नारे के साथ हुआ. जनता की इसी दुखती रग पर हाथ फेरते हुए हरीश ने गैरसैंण को अपनी राजनीति का हिस्सा जनभावना के अनुरूप कर विधानसभा सत्र का आयोजन किया. रावत ने वह सब किया, जिससे यह संदेश दिया जा सके की कांग्रेस इस मुद्दे पर जनभावना का पूरी तरह से आदर करती है. रावत ने साफ कहा था कि जो भी किया, जनभावना के अनुरूप किया. आगे भी वही करेंगे, जो जनता चाहेगी. डॉ. इंदिरा का हरीश सरकार के पत्ते खोलना कांग्रेस के भरे घड़े में छेद करने की कार्रवाई मानी जा रही है. गैरसैंण विधानसभा सत्र के बाद गुटबाजी में विश्वास रखने वाले प्रदेश कांग्रेस में यह अभियान तेज हो गया है. संसदीय एवं विधायी कार्य मंत्री डॉ. इंदिरा के गैरसैंण पर दिए बयान को राजनीतिक के मर्मज्ञ इसी तरह देख रहे हैं. माना जा रहा है कि इस बयान के जरिए अहम पद पर होते हुए भी लंबे वक्त से पार्टी के भीतर अकेले पड़ीं इंदिरा हृदयेश कांग्रेस के मैदानी क्षेत्र के विधायकों का समर्थन खुद के लिए जुटाना चाहती हैं. वह अपना खुद का धड़ा खड़ा करना चाहती हैं. राजनीति में सत्ता में काबिज होने के लिए राजनीतिक दलों को एक ओर विपक्ष से निपटना होता है, वहीं नेताओं को अपनी ही पार्टी के भीतर मौजूद विपक्ष से निपटने के लिए बहुमत जुटाना जरूरी होता है. डॉ. हृदयेश के बयान को राजनीति की गणित समझने वाले इसी मुहिम का हिस्सा मान रहे हैं. मान रहे हैं कि दिग्गज कांग्रेसी महिला नेता ने सोची-समझी राजनीति के तहत हरीश रावत के किए-धरे पर पानी फेरना चाहती है. उनके इस बयान से एक ओर विरोधियों को जहां प्रदेश सरकार को घेरने का मौका मिला है, वहीं गैरसैंण भावना की बात करने वाली कांग्रेस के लिए आने वाले समय में जनता के सवालों का जवाब देना मुश्किल होगा. सूत्रों का कहना है कि इंदिरा हृदयेश के बयान के लिए धरातल तो तभी बनना शुरू हो गया था, जब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का यह दावा कांग्रेस के गैरसैंण अधिवेशन में थोथा साबित हो गया था कि कांग्रेस पार्टी वहां अधिवेशन में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का प्रस्ताव लाएगी. कहा जा रहा है कि जैसे ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने गैरसैंण को प्रदेश की स्थायी राजधानी बनाने के प्रस्ताव की बात की, उसका विरोध कांग्रेस के हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर जिलों के विधायकों के अलावा टिहरी और उत्तरकाशी के विधायकों ने भी किया. यही वजह रही कि प्रदेश कांग्रेस के अधिवेशन में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपने इस बयान से गैरसैंण पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के बयानों से उपजी गर्मी पर ठंडा पानी डाल दिया कि वह किसान के बेटे हैं और वह फसल तब नहीं बोते, जब तक कि खेत तैयार न हो जाए. नतीजा यह हुआ कि गैरसैंण को लेकर कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव ही नहीं आया. यही नहीं, सूत्रों की मानें तो गैरसैंण विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भाजपा की गैरसैंण पर नियम 310 के तहत चर्चा पर तैयार हो गए थे. कांग्रेस के अपने ही विधायकों ने अंदरखाने इसका भारी विरोध किया और अपनी सियासी जमीन खत्म होने की आशंका तक जताई. इससे सरकार को आशंका पैदा हो गई कि इस मुद्दे पर मतदान हुआ तो उसके ही विधायक उसका साथ नहीं देंगे और सरकार के सामने संकट खड़ा हो जाएगा. इतना ही नहीं, गैरसैंण के मामले में भाजपा के सामने भी यही धर्म संकट था. उसके तो अधिकांश विधायक ही मैदानी क्षेत्रों से हैं. ऐसे में उसने सुरक्षाकर्मियों के नाम पर हंगामा खड़ा किया कि सरकार को इस मुद्दे पर किसी और नियम के तहत भी चर्चा कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी और विपक्ष के हंगामे की वजह से मामले पर चर्चा ही नहीं हुई और विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया. विश्लेषकों का कहना है कि गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का प्रस्ताव सत्र में आता तो दोनों दलों के विधायकों की गैरसैंण मामले में राय जगजाहिर हो जाती. इसके बाद दोनों के नेतृत्व को जनता को जवाब देना भारी पड़ जाता. डॉ. हृदयेश के बयान को उनकी पार्टी के मैदानी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों को अपने पक्ष में गोलबंद करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि अनुकूल राजनीतिक परिस्थितियां पैदा होने पर इस गोलबंदी को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सत्ता के शीर्ष पर काबिज हुआ जा सके. अब समय ही बताएगा कि इससे उन्हें कितनी कामयाबी मिलती है. उनकी इस हरकत ने राजनीति के कुशल खिलाड़ी हरीश के राह में रोड़ा डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. कंक्रीट हटा कर राजनीतिक सफर में शीर्ष पर पहुंचे हरीश मिशन 2017 की राह आसान बनाने की रणनीति को आकार दे रहे हैं. कांग्रेस हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा हरीश की पीठ थपथपाना उनके अपनों में ही ईर्ष्या का कारण बन रहा है. ■

feedback@chauthiduniya.com

राज्य को नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाना है-हरीश रावत

ब्यूरो कार्यालय

मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों खिलाड़ियों को देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार और देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किए. मुख्यमंत्री ने श्रीमती हंसा मनराल शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया. इसके तहत 5 लाख रुपये तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया. इसी प्रकार से स्व. राम बहादुर क्षेत्री को देवभूमि उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार तथा सुश्री रेनू कोहली को देवभूमि उत्तराखण्ड द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया. इस अवसर पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य स्थापना के 15 वर्ष की यात्रा में उत्तराखण्ड ने काफी प्रगति की है. हमारा प्रयास अक्टूबर 2016 तक राज्य को विकास की नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का है. विकास की दौड़ में पीछे रह गए राज्य के 30 लाख लोगों के जीवन में बदलाव लाना है. इसके लिए गांवों को विकास का मॉडल बनाना होगा. तेजी से हो रहे पलायन को रोकने के लिए अगले 7 वर्षों में हम संभावनाहीन क्षेत्रों को संभावनायुक्त क्षेत्रों में बदलेंगे, ताकि लोग गांवों की ओर लौटें. राज्य स्थापना दिवस पर कैन्ट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पुस्तिका उभरता उत्तराखण्ड-उन्नत उत्तराखण्ड का विमोचन किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के 15 वर्षों तक हमने काफी प्रगति की है. राज्य के विकास में लाखों लोगों के हाथ जुड़े हैं. राज्य ने इन 15 वर्षो में विकास के जो नये आयाम प्राप्त किये हैं, उसमें सबका योगदान है. यह हम सबकी एकजुटता का प्रतिफल है. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड वर्तमान में अन्य राज्यों के मध्य तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला राज्य है. हिमालयी राज्यों में हमारी मॉडल स्टेट के रूप में पहचान बनी है. प्रतिव्यक्ति आय में हम दूसरे नम्बर पर हैं. वर्ष 2013 का विध्वंस भी हमारी कर्मशीलता को विध्वंस नहीं कर सका. हम उस कठिन दौर से आगे बढ़े हैं. केदारनाथ विध्वंस का हमने सामना किया है. यह हमारी सामूहिक एकता का प्रतीक है. आपदा के बाद 10 लाख यात्रियों का यहां आना इसका प्रमाण है. उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में बेहतर है. उन्होंने यह भी कहा कि हमारा प्रयास अक्टूबर 2016 तक राज्य को विकास की नयी ऊंचाइयों तक पहुंचाने का है. 500 से अधिक सड़कों पर तेजी से काम किया जा रहा है. लगभग 1000 अन्य योजनाओं पर कार्य चल रहा है. चारधाम यात्रा हमारी बेहतर सड़कों के कारण सुगम हो, हम यात्रा के लिये लोगों को आकर्षित कर सकें और यात्रा निर्बाध रूप से संचालित हो, इसके लिये हम प्रयासरत हैं. उन्होंने मीडिया से राज्य के विकास में सहयोग की अपेक्षा करते हुये कहा कि मीडिया का सकारात्मक सहयोग चारधाम यात्रा सहित पर्यटन को बढ़ावा देने में मददगार हो सकेगा. उत्तराखण्ड से लोगों का काफी लगाव है. दून से मुनस्यारी तक लाखों लोगों का आवागमन हो रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अपने राज्य के 30 लाख लोगों के जीवन में बदलाव लाना है. उन्हें साधन व समानता उपलब्ध करानी है. इसके लिये प्रदेश के विकास की दौड़ में पीछे रह गये 30 लाख लोगों की सहायता के लिये हम सभी को आगे आना होगा. हम गांवों को विकास का मॉडल बनाने का कार्य कर रहे हैं. तेजी से हो रहे पलायन को रोकने का हम कार्य करेंगे. अगले सात साल में संभावनाहीन क्षेत्रों को संभावनायुक्त क्षेत्रों में बदलेंगे, ताकि लोग गांवों की ओर लौटें. इसके लिये सामूहिक भागीदारी की जरूरत है. अगले तीन वर्ष में 20 हजार महिला उद्यमी तैयार की जाएंगी. कमजोर महिलाओं को राज्य प्रत्येक स्थिति व स्तर पर, पेंशन या पोषण अनुदान से लाभान्वित कर रहा है. मुख्यमंत्री ने अभिव्यक्ति संस्था की ओर से चलाये जा रहे हिटो पहाड़ अभियान के लिए मुम्बई से आये प्रवासी उत्तराखण्डी केशर सिंह बिष्ट, आरएस रावत व राजेन्द्र जोशी को सम्मानित किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवासी उत्तराखण्डी भाई प्रदेश के विकास में सहभागी बनें. मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश पब्लिक स्कूल द्वारा 18 अप्रैल, 2015 को गंगा सफाई के प्रति जागरूकता के प्रचार के लिये निर्मित डेढ़ किलोमीटर लम्बी रंगोली बनाने के लिये विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक व छात्रों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया. इस अवसर पर सचिव सूचना विनोद शर्मा ने विभाग द्वारा प्रकाशित विकास पुस्तिका के संबंध में जानकारी दी. कार्यक्रम का संचालन अपर निदेशक सूचना डॉ. अनिल चन्दोला ने किया. ■

feedback@chauthiduniya.com

नेपाल को पाकिस्तान बनाने में जुटा है चीन

नेपाल में फैली अराजकता के बीच चीनी अधिकारियों का भारत के सीमाई क्षेत्र तक आना और सर्वेक्षण करके चले जाना अत्यंत संवेदनशील मसला माना जा रहा है. इतना सब होने के बाद भी भारत सरकार इससे बेपरवाह है. भारतीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर निरीक्षण करने आए चीनी अधिकारी चीन के कस्टम विभाग के बताए गए, लेकिन आशंका यह है कि कस्टम विभाग के छद्म रूप में चीनी सेना के अधिकारी और चीनी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र का जायजा लिया और चले गए. अगर यह आशंका सच साबित हुई तो यह आनेवाले दिनों में भारत के लिए खतरे की घंटी है. मामला चाहे जो भी हो भारत को इन हलचलों पर नजर रखनी होगी और विदेशी कारनामों से सावधान रहना होगा.

सूफी यायावर/शत्रुंजय सिंह रैकवार

अरुणाचल प्रदेश या फिर लेह-लद्दाख के झरोखे से अब तक चीन भारत में घुसपैठ को अंजाम देता था, लेकिन अब तो नेपाल ने ही उसका रास्ता खोल दिया है. नेपाल से लगा भारत का विशाल सीमा-क्षेत्र चीनी घुसपैठ के लिए खुलता जा रहा है, लेकिन भारत सरकार इतने संवेदनशील मुद्दे पर कोई कारगर उपाय नहीं कर पा रही है. पिछले दिनों नेपाल से लगे भारतीय सीमा क्षेत्र सोनौली इलाके में सादे वेश में चीनी अधिकारी चहलकदमी करते देखे गए. चीन के अधिकारियों के इस तरह खुलेआम बॉर्डर एरिया में घूमते देखे जाने से नेपाल के मधेसी इलाके के साथ-साथ भारत के सीमाई इलाके में एक विचित्र किस्म का भय और आशंका का माहौल बना हुआ है. मधेसी आंदोलन के कारण नेपाल में फैली अराजकता के बीच चीनी अधिकारियों का भारत के सीमाई क्षेत्र तक आना और सर्वेक्षण करके चले जाना अत्यंत संवेदनशील मसला माना जा रहा है. भारतीय सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों का कहना है कि सीमा पर निरीक्षण करने आए चीनी अधिकारी चीन के कस्टम विभाग के बताए गए, लेकिन आशंका यह है कि कस्टम विभाग के छद्म में चीनी सेना के अधिकारी और चीनी खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने सीमा क्षेत्र का जायजा लिया और चले गए. एसएसबी के अधिकारी नेपाल सीमापर तैनात अधिकारियों के हवाले से बताते हैं कि बीते पांच नवम्बर को चीन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल (कस्टम) लांग चिंग वी अन्य चीनी अधिकारियों के साथ रूपनदेही जिले के बेलहिया कस्टम कार्यालय पर पहुंचे. नेपाल पुलिस के जवान और कमांडो उनकी सुरक्षा में लगे थे. उन्होंने कस्टम कार्यालय में नेपाल के अधिकारियों से बातचीत की. बैठक के बाद चीन के अधिकारी नो मैंस लैंड पर पहुंचे.

पिछले करीब एक दशक से नेपाल के बिगड़े हालात का लाभ उठाकर चीन भारतीय सीमा में प्रवेश कर भारतीय अर्थव्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने का प्रयास कर रहा है. बद से बदतर होते जा रहे नेपाल को पुचकारने के बहाने चीनी अधिकारी अपनी कुत्सित मंशा को फलीभूत करने की कोशिशों में लगे हैं. चीन का प्रयास है कि पाकिस्तान की तरह नेपाल भी उनकी गोद में खेले और भारत उनके सीधे निशाने पर आ जाए. हिन्दुस्तान की सोनौली सरहद के पास तक चीनी अधिकारियों का पहुंचना चीन के इसी इरादे को दर्शाता है. नेपाल के मधेसी क्षेत्र की सद्भावना पार्टी के केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र मिश्रा, शिव पटेल और निजामुद्दीन कहते हैं कि यह चीन की साजिश का ही परिणाम है कि नेपाली सेना मधेसियों पर बर्बर कार्रवाइयां कर रही है.

वहां ड्यूटी पर मुस्तैद नेपाली जवानों से भी बात की और कुछ देर सोनौली सीमा पर भारतीय गतिविधियों का निरीक्षण करते रहे. कुछ देर तक भारतीय सीमा क्षेत्र का जायजा लेने के बाद वे लौट गए. भारतीय सीमा क्षेत्र के पास चीनी अधिकारियों की चहलकदमी से भारतीय सुरक्षा बल के लोग भी सतर्क हो गए और चीनी अधिकारियों के इस तरह भारतीय सीमा क्षेत्र के नजदीक आने का उनका मकसद जानने की कोशिश करते रहे. नेपाल सीमा पर तैनात एक अधिकारी ने बताया कि चीनी अधिकारियों के दौरे के दौरान ही लुम्बिनी मार्ग पर पैट्रोलिंग के दौरान नेपाल सशं पुलिस के वाहनों पर मधेसी आंदोलनकारियों ने पथराव कर दिया. बनगाई गांव के सामने अचानक सैकड़ों की तादाद में आंदोलनकारी सड़क पर उतर आए और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया. नेपाल पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और कई लोगों को गिरफ्तार किया.

मधेस प्रांत और नए संविधान में समानता की मांग को लेकर मधेसियों और थारुओं ने पिछले कई महीने से आंदोलन छेड़ रखा है. आंदोलनकारियों ने दबाव बनाने के लिए भारत से आपूर्ति के सभी नाकों को ठप्प कर दिया था. बीरगंज, विराटनगर और बढ़नी आदि नाकों से आपूर्ति पूरी तरह ठप्प हो गई तो सोनौली बॉर्डर पर दबाव बढ़ गया. यहां भी सीमावर्ती क्षेत्रों में बीच-बीच में आंदोलन उग्र होने के चलते आपूर्ति प्रभावित हुई. इसके बाद नेपाल ने भारत पर नाकेबंदी का आरोप भी लगाना शुरू कर दिया. इस पर वाहन भेजे जाने लगे, लेकिन पिछले हफ्ते भैरहवा में भारतीय ट्रक फूंके जाने और अगले ही दिन बीरगंज में नेपाल पुलिस की फायरिंग में एक भारतीय की मौत के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा कारणों से जांच सख्त कर दी. इन दिनों जरूरी वस्तुओं को लेकर करीब तीन दर्जन मालवाहक वाहन रोज सोनौली बॉर्डर के जरिए भेजे जा रहे थे, लेकिन सोनौली सीमा पर चीनी अधिकारियों के दौरे के बाद नेपाल ने तेवर दिखाना शुरू कर दिया. भारत से भेजे गए रोजमर्रा की जरूरत के सामान से लदे ट्रकों को नेपाल के बेलहिया कस्टम कार्यालय से क्लियरेंस ही नहीं दी जा रही है. इससे ट्रकों पर लदे सब्जी और फल सड़ने लगे. दूसरी तरफ चीन ने दो नाके पहले खोले और बाद में सात नाके और खोल दिए. चीन की शह पाकर ही नेपाल के तेवर बदले हैं. चीन से नजदीकियों की वजह से नेपाल के सुर तल्ख होते जा रहे हैं. चीन अधिकृत तिब्बत के तातोपानी और रसुवागढ़ी-केरूंग नाके से नेपाल को कुछ आपूर्ति शुरू की गई है. अप्रैल में आए भूकंप में रास्ते तबाह होने की वजह से इन नाकों से आपूर्ति ठप्प हो गई थी. काठमांडू में पिछले दिनों नेपाल और चीनी अधिकारियों की बैठक में 20 सूत्री समझौता हुआ है. इसके तहत दोनों देशों के बीच सात और व्यापारिक नाकों को खोलने पर सहमति बनी है. इस बैठक में नेपाल की ओर से कस्टम महानिदेशक दामोदर रेग्मी और चीन की ओर से ल्हासा कस्टम कार्यालय के डिप्टी डायरेक्टर लांग चेंग वी चीनी अधिकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. चीनी प्रतिनिधिमंडल के सोनौली नाके के दौरे और भारत से होने वाली आपूर्ति के ब्योरे जुटाने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन खुफिया एजेंसियां इस तर्क से असहमत हैं और चीन की हरकतों को उनकी सेंधमारी के इरादे से जोड़ कर देखती हैं. सवाल उठ रहा है कि चीनी अधिकारियों की टीम में चीन अधिकृत तिब्बत के खासा बार्डर के भंसार उप प्रमुख लांग चेंग वी के साथ आए आधा दर्जन चीनी अफसर कौन थे? सरहद पर चीनी अधिकारियों की हलचल देख कर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी है, लेकिन इस हरकत के बाद अब नेपाल सीमा पर भी बीएसएफ और सेना की तैनातियों की जरूरत महसूस की जाने लगी है.

पिछले करीब एक दशक से नेपाल के बिगड़े हालात का लाभ उठाकर चीनी ड्रैगन भारतीय सीमा में प्रवेश कर भारतीय अर्थव्यवस्था व सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाने का प्रयास कर रहे हैं. बद से बदतर होते जा रहे नेपाल को पुचकारने के बहाने चीनी अधिकारी अपनी कुत्सित मंशा को फलीभूत करने की कोशिशों में लगे हैं. चीन का प्रयास है कि पाकिस्तान की तरह नेपाल भी उनकी गोद में खेले और भारत उनके सीधे निशाने पर आ जाए. हिन्दुस्तान की सोनौली सरहद के पास तक चीनी अधिकारियों का पहुंचना चीन के इसी इरादे को दर्शाता है. नेपाल के मधेसी क्षेत्र की सद्भावना पार्टी के केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र मिश्रा, शिव पटेल और निजामुद्दीन कहते हैं कि यह चीन की साजिश का ही परिणाम है कि नेपाली सेना मधेसियों पर बर्बर कार्रवाइयां कर रही है. नेपाल में सहायता के नाम पर भारतीय सीमाओं की निगरानी की जा रही है. नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने भारत को नेपाल के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देने की बात कह कर अपना चीनी-प्रेम पहले ही जता दिया है. नेपाल के नेता यह भी बताते हैं कि चीन ने अपनी मर्जी का संविधान बनवा कर नेपाल को आर्थिक रूप से चीन-मुखापेक्षी बनाने और भौगोलिक वर्गीकरण को मनोनुकूल बना कर भारतीय सीमा तक घुसपैठ बनाने का अपना हित साध लिया है. चीन के कारण ही नेपाल के संविधान में प्रांतों का बंटवारा पूरब से पश्चिम न करके उत्तर से दक्षिण किया गया. प्रांतों के इस सीमांकन से भारत की 1700 सौ किलोमीटर में विस्तृत सीमा तक चीन की पहुंच बन सकेगी. ■

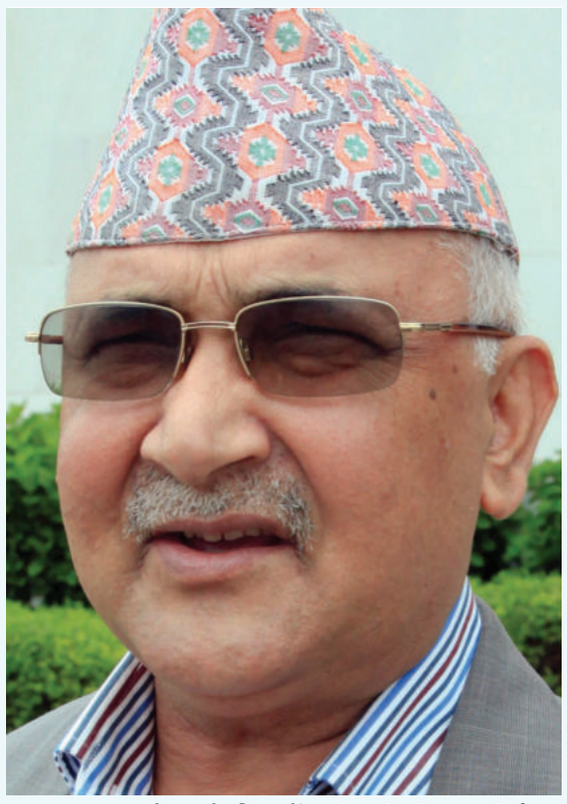

चीन की गोद में बैठ रहा नेपाल!

नेपाल के नए प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली कम्युनिस्ट हैं और चीन के हिमायती हैं. भारत-नेपाल संबंध अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है. कम्युनिस्ट के पी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल में चीनी प्रभाव बढ़ने और भारत-नेपाल संबंधों के खराब होने की आशंका बढ़ती जा रही है. यह अब दिखने भी लगा है. ओली सीधे-सीधे चीन के प्रभाव में भी हैं. इससे पहले नेपाली उप प्रधानमंत्री प्रकाशमान सिंह के नेतृत्व में एक नेपाली प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून से शिकायत की थी कि व्यापारिक मार्ग बाधित होने के कारण नेपाल में भारी किल्लत हो गई है. दरअसल, इसे चीन की गोद में जाने के पहले की नेपाली पेशबंदी के रूप में देखा जा रहा है. नेपाल में मधेसियों की आबादी 60 लाख से अधिक है. इतनी बड़ी आबादी को नेपाल नजरअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन चीन मधेसी आबादी को हिंदुस्तान तक चीनी घुसपैठ में सबसे बड़ी बाधा मानता है. मधेसी नेपाल की पूरी सप्लाई लाइन ठप्प कर सकते हैं. चीन की शह पर पहाड़ी वर्चस्व वाले राजनीतिक दलों ने मधेसियों के हितों की पूरी उपेक्षा कर रखी है. मधेसियों के हितों पर चोट पहुंचाने में ओली की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल भी शामिल है. मधेसियों पर पड़ रही चोट का सीधा असर यूपी और बिहार के उनके रिश्तेदारों पर पड़ रहा है. चीन की मंशा भी यही है. इससे यूपी और बिहार की राजनीति भी प्रभावित हो रही है और नेपाल के साथ भारत के ऐतिहासिक-पारम्परिक रिश्तों पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है. चीन भारत की चारों तरफ से घेरेबंदी करने का कुचक्र चला रहा है. नेपाल उसी का जरिया बन रहा है. भौगोलिक रूप से मैदान और पहाड़ में बंटे नेपाल में 100 से ज्यादा जातियां-जनजातियां हैं, लेकिन नेपाल की सत्ता पर पहाड़ी अभिजात्य जातियों का ही कब्जा रहा है, जिनकी आबादी 30 प्रतिशत है. ओली भी पहाड़ी हैं. नेपाल की सत्ता का सुख भोगने वाले पहाड़ी नेता मधेसियों को सत्ता की हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं हैं. नेपाल में कम्युनिस्टों के बढ़ते प्रभाव के कारण चीनी हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ा है. नेपाली कांग्रेस में भी चीन ने घुसपैठ बना रखी है. भारत इस स्थिति को संभालने में नाकाम रहा है. पिछले दस साल में चीन ने नेपाली राजनीतिक दलों की व्यवस्था अपने हाथ में नियंत्रित कर ली है. पिछले साल काठमांडू में हुए सार्क सम्मेलन में नेपाल, पाकिस्तान और चीन की भाषा बोल रहा था. नेपाल के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और सूचना मंत्री ने चीन को सार्क का स्थाई सदस्य बनाने के लिए खुलकर लॉबिंग की थी. इससे साफ हो गया था कि नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल में चीन की घुसपैठ है. ■

नेपाल का राजनीतिक समीकरण

नेपाल के राजनीतिक समीकरण को देखें तो पता चलता है कि वर्ष 2008 में संविधान सभा के चुनाव में माओवादी और मधेसी काफी मजबूत थे, लेकिन 2013 के चुनाव में नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल ने बाजी पलट दी. माओवादियों के भ्रष्टाचार और मधेसियों के आपसी झगड़े ने इन्हें कमजोर किया. 2013 में संविधान सभा के चुनाव में माओवादी 80 सीट पर व मधेसी पार्टियां 40 सीट पर सिमट गईं, जबकि नेपाली कांग्रेस 196 और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूएमएल) 175 सीट पर काबिज हो गई. भारत की कूटनीति कमजोर साबित हुई और नेपाली कांग्रेस व कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के नेताओं को काबू करने में चीन कामयाब हो गया. नेपाल में आए भूकंप में भारत ने बहुत बड़ा काम किया, लेकिन उसका श्रेय चीन को दे दिया गया. भूकंप में हजारों लोग मरे और नेपाल को तकरीबन 9 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ. भारत ने 24 घंटे से भी कम समय में अपनी राहत टीम नेपाल भेज दी और नेपाली जनता की पुरजोर मदद की, लेकिन नेपाल के भूकंप ने चीन का रास्ता खोल दिया और नेपाली नेताओं के लिए लॉटरी खोल दी. भूकंप के बहाने चीन ने नेपाली नेताओं को खूब भ्रष्ट किया. चीन नियंत्रित तिब्बत की सीमा नेपाल से लगती है. भारत की सीधी सीमा नेपाल से लगती है. चीन को भारत में तिब्बती रिफ्यूजियों का डर है. वहीं भारत को डर है कि चीन नेपाल के रास्ते भारतीय सीमा तक पहुंच रहा है. यह भारत को घेरने की चीनी नीति है. चीन तिब्बत के ल्हासा से नेपाल के काठमांडू को 540 किलोमीटर लंबी रेल लाइन से जोड़ने की योजना भारतीय हितों पर चोट पहुंचाने के लिए ही बना रहा है. यह रेल लाइन 2020 तक बन जाएगी. भारत की चिंता प्रस्तावित रेल लाइन के लिए हिमालय में चीन द्वारा सुरंग खोदे जाने को लेकर भी है. इससे हिमालय क्षेत्र के पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचने का अंदेशा है. ■

feedback@chauthiduniya.com